Ranchi ● Saturday, 28 June 2025 ● Year : 03 ● Issue : 163 ● Ranchi Edition ● Page : 12 ● Price : ₹3 ● www.thephotonnews.com
E-Paper : epaper.thephotonnews.com

Daily
सच के हक में...
THE PHOTON NEWS
द फोटोन न्यूज़
Published from Ranchi

रांची में रथयात्रा
जय जगन्नाथ

रथ खींचने के लिए दिखा अपार उत्साह

बड़कागढ़ क्षेत्र में भक्तिभाव और आध्यात्मिक ऊर्जा का हुआ संचार

ढोल-नगाड़ों और शंखध्वनि के बीच तीनों विग्रहों को रथ पर कराया गया विराजमान

शुक्रवार को धुर्वा स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में रथयात्रा को लेकर आस्था का अद्भुत ज्वार उमड़ पड़ा। राजधानी रांची जय जगन्नाथ की ध्वनि से गूंज उठी। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भव्य रथयात्रा मंदिर परिसर से विधिपूर्वक निकाली गई। रथ खींचने के लिए हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। बड़कागढ़ क्षेत्र में भक्तिभाव और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो उठा। वहीं प्रभु के दर्शन के लिए भक्तों का उत्साह देखने लायक था। इससे पहले सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी। जैसे ही मंदिर के पट खोले गए, दोपहर बाद सबसे पहले भगवान गरुड़ की प्रतिमा को मंदिर से बाहर लाया गया। इसके बाद विधि-विधान के साथ भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ को पुजारियों द्वारा बाहर लाया गया। ढोल-नगाड़ों, भेर और शंखध्वनि के बीच तीनों विग्रहों को भक्तों के जयघोष के साथ रथ पर विधिपूर्वक विराजमान कराया गया।

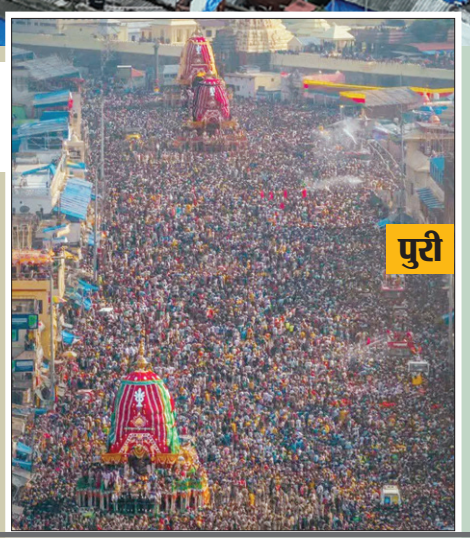

पुरी में हजारों लोगों ने खींचा रथ

PURI : ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा उत्सव का मुख्य भाग शुरू होने के साथ ही हजारों लोगों ने भगवान जगन्नाथ और उनके भाई-बहनों के रथों से जुड़ी रस्सियों को श्री गुंदेचा मंदिर की ओर खींचा। श्री गुंडिचा मंदिर, 12वीं सदी के भगवान जगन्नाथ मंदिर से करीब 2.6 किलोमीटर दूर है। राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के रथों को खींचने वालों में शामिल थे।

SHARE

सेंसेक्स	:	84,058.90
निफ्टी	:	25,637.80

SARAFA

सोना	:	9,165
चांदी	:	120.00

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

सभी जिलों में एक जुलाई तक बारिश की संभावना

RANCHI : झारखंड के सभी जिलों में एक जुलाई तक बारिश होने की संभावना है। वहीं 29 जून को राज्य के उत्तरी-मध्य और इसके निकटवर्ती हिस्सों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की आशंका है। यह जानकारी मौसम विभाग ने शुक्रवार को दी है। विभाग के अनुसार दक्षिणी-पश्चिमी मॉनसून फिलहाल झारखंड में पूरी तरह से सक्रिय बना हुआ है। यही वजह है कि पूरे राज्य भर में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की जा रही है।

केदारनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड, फंसे यात्री

NEW DELHI : देश में दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों में बारिश हो रही है। अब तक सामान्य से 12.3 फीसदी ज्यादा बारिश हो चुकी है। 26 जून तक देश में सामान्य रूप से 134.3 मिमी होनी चाहिए थी, लेकिन 146.6 मिमी हो चुकी है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते केदारनाथ हाईवे एक बार फिर मुनकटिया इलाके में लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गया है। रास्ते पर लगातार पत्थर और मलबा गिर रहा है। यात्रियों को जंगल के वैकल्पिक रास्तों से सुरक्षित निकालने का प्रयास चल रहा है।

राजनाथ ने चीन, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान व बेलारूस को बताया-

आतंकवाद का नेटवर्क नष्ट करने को भारत ने किया ऑपरेशन सिंदूर

AGENCY NEW DELHI : शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने गए राजनाथ सिंह ने किंगदाओ में चीन, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और बेलारूस के रक्षा मंत्रियों के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकें की हैं। एससीओ के संयुक्त वक्तव्य पर भारत ने इसलिए हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि इसमें पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र नहीं किया गया था। इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में पाकिस्तानी आतंकवादी नेटवर्क को नष्ट करने के उद्देश्य से भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून के साथ द्विपक्षीय बैठक में भारत-चीन सीमा पर शांति और सौहार्द बनाए रखने की आवश्यकता पर गहन विचार-विमर्श किया। रक्षा मंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने स्थायी जुड़ाव और तनाव कम करने के लिए एक व्यवस्थित प्रारूप के माध्यम से जटिल मुद्दों के समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेलारूस, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें कीं।

एससीओ के संयुक्त वक्तव्य में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र न होना दुखद

अविश्वास दूर करना जरूरी

राजनाथ सिंह ने एशिया और दुनिया में स्थिरता के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए अच्छे पड़ोसी हालात बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने जमीनी स्तर पर कार्रवाई करके 2020 के सीमा गतिरोध के बाद उत्पन्न अविश्वास को दूर करने का भी आह्वान किया। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान व्यवस्थाओं के माध्यम से सैनिकों की वापसी, तनाव कम करने, सीमा प्रबंधन और सीमांकन से संबंधित मुद्दों पर प्रगति हासिल करने के लिए विभिन्न स्तरों पर परामर्श जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने की महत्वपूर्ण उपलब्धि पर भी विचार व्यक्त किए। उन्होंने पांच वर्ष के अंतराल के बाद कैलास मानसरोवर यात्रा के पुनः शुभारंभ होने की भी सराहना की। राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री को 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ किए गए जघन्य आतंकवादी हमले और पाकिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क को नष्ट करने के उद्देश्य से भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी जानकारी दी।

- भारत-चीन सीमा पर शांति व सौहार्द बनाए रखने की आवश्यकता पर हुआ विचार-विमर्श
- व्यवस्थित प्रारूप के माध्यम से जटिल मुद्दों के समाधान की आवश्यकता पर दिया बल
- द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना
- आतंकवाद और भारत-रूस रक्षा सहयोग जैसे विषयों पर भी चर्चा

महत्वपूर्ण सैन्य साजो-सामान की खरीद पर बातचीत

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलौसोव के साथ द्विपक्षीय बैठक में वर्तमान भू-राजनीतिक स्थितियों, सीमा-पार आतंकवाद और भारत-रूस रक्षा सहयोग जैसे विषयों पर गहन चर्चा की। रूस के रक्षा मंत्री ने दीर्घकालिक भारत-रूस संबंधों का उल्लेख करते हुए जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भयावह और कायराना आतंकवादी कृत्य पर भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। बैठक के दौरान विशेष रूप से वायु रक्षा प्रणाली, वायु से वायु में मार करने वाली मिसाइलों, आधुनिक क्षमताओं और हवाई प्लेटफार्मों के उन्नयन जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं जैसे एस-400 प्रणाली की आपूर्ति, एसयू-30 एमकेआई अपग्रेड और तय समय सीमा में महत्वपूर्ण सैन्य साजो-सामान की खरीद पर मुख्य रूप से चर्चा की गई।

चिंताजनक हुई शिबू सोरेन की हालत, ब्रेन स्ट्रोक के कारण बाईं ओर हो गया है पैरालिसिस

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के संस्थापक और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की हालत चिंताजनक है। झामुमो के प्रवक्ता मनोज पांडेय ने बताया कि सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती दिशोम गुरु शिबू सोरेन की हालत थोड़ी चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की एक टीम उनका इलाज कर रही है और आईसीयू में सीमित लोगों को उनसे मिलने की अनुमति है। प्रवक्ता पांडेय ने कहा कि गुरुजी शिबू सोरेन की तबीयत स्थिर है, उसमें न तो कोई गिरावट आई है और न ही कोई सुधार हुआ है। सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन जल्द स्वस्थ होकर झारखंड लौटें। उन्होंने कहा कि अभी झारखंड और झारखंडवासियों को शिबू सोरेन के मार्गदर्शन की जरूरत है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। डॉक्टरों के मुताबिक, उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। डॉक्टरों के अनुसार, उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। इससे उनके शरीर की बाईं ओर पैरालिसिस हो गया है।

किडनी की बीमारी से भी जूझ रहे दिशोम गुरु : उल्लेखनीय है कि 81 वर्षीय गुरुजी लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं। वह एक साल से डायलिसिस पर हैं। वे डायबिटीज से पीड़ित हैं और हार्ट की बाइपास सर्जरी भी हो चुकी है।

आईसीयू में सीमित लोगों को उनसे मिलने की डॉक्टरों ने दी है अनुमति

- न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम कर रही इलाज
- अभी झारखंड और झारखंडवासियों को शिबू सोरेन के मार्गदर्शन की जरूरत

जागरूकता पशुओं के लिए एंटीबायोटिक के प्रयोग में समझदारी की जरूरत पर जोर

पशुपालकों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने बनाया नया नियम

PHOTON NEWS @ RESEARCH DESK : अपने 11 वर्षों के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि क्षेत्र में किसानों को कई प्रकार की राहत देने के अतिरिक्त पशुपालन के क्षेत्र में किसानों के लिए जागरूकता पर भी फोकस किया है। यह सही है कि पशु चिकित्सा सेवा की स्थिति आज भी बहुत अच्छी नहीं है। इसके कारण किसानों को पशुओं के लिए बिना चिकित्सकीय सलाह के भी कई किस्म की दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस स्थिति को बदलने के लिए हाल में ही केंद्र सरकार ने किसानों को मदद के लिए नया नियम बनाया है। एंटीबायोटिक जैसी दवाओं का उपयोग अब सीमित रूप में होगा और इसके लिए निगरानी तंत्र काम करेगा। केंद्र सरकार ने पशुओं में एंटीबायोटिक दवाओं के बेतरतीब इस्तेमाल को रोकने नया निगरानी तंत्र बना दिया है। इसके लिए केंद्र ने राज्यों से फार्मा कंपनियों और नोडल अधिकारियों की सूची मांगी है। इसके बाद अब बिना पर्ची बिकने वाली दवाओं पर सख्त नियंत्रण होगा, ताकि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) को रोका जा सके।

बिना चिकित्सकीय सलाह के ऐसी दवाओं का अधिक इस्तेमाल अत्यंत खतरनाक

अब निगरानी तंत्र के माध्यम से इन दवाओं के प्रयोग पर लगाई जाएगी रोक

- केंद्र ने राज्यों से फार्मा कंपनियों और नोडल अधिकारियों की मांगी सूची
- बिना पर्ची के बिकने वाली इन दवाओं पर सख्त नियंत्रण के दिए गए हैं निर्देश
- पशु स्वास्थ्य विभाग ने एएमआर की बढ़ती समस्या को देखते हुए उठाया कदम

पशुओं ही नहीं, मनुष्यों के लिए भी गंभीर खतरा बन चुकी है एएमआर की समस्या

पशु चिकित्सकों का अभाव दूर करना जरूरी

गौरतलब है भारत में पशु चिकित्सा सेवाओं की स्थिति चिंताजनक है। आंकड़ों बताते हैं कि देश में प्रति 40 हजार पशुओं पर मात्र एक पशु चिकित्सक उपलब्ध है। पशु चिकित्सकों का अभाव को दूर करना जरूरी है। इस कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालक बिना डॉक्टर की सलाह के ही मेडिकल स्टोर्स से एंटीबायोटिक दवाएं खरीद लेते हैं।

सामान्य संक्रमण भी हो सकता है लाइलाज

बिना पर्ची के बिकने वाली इन दवाओं पर सख्त नियंत्रण के निर्देश दिए गए हैं। पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशु स्वास्थ्य विभाग ने यह कदम एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) की बढ़ती समस्या को देखते हुए उठाया है। पशु चिकित्सकों के अनुसार, एएमआर तब होता है, जब बैक्टीरिया, वायरस या अन्य रोगाणु एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं, जिससे संक्रमण का इलाज मुश्किल हो जाता है। यह समस्या न सिर्फ पशुओं, बल्कि मनुष्यों के लिए भी गंभीर खतरा बन चुकी है। विभागीय जानकारी के अनुसार, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने राज्यों से पशु एंटीबायोटिक बनाने, बेचने और वितरित करने वाली सभी फार्मा कंपनियों की सूची मांगी है। राज्यों को पशु एंटीबायोटिक दवाएं बनाने, बेचने और वितरित करने वाली कंपनियों की पूरी सूची जमा करनी होगी।

नीति आयोग की ऑनलाइन समीक्षा बैठक में किया बेहतर प्रदर्शन

112 आकांक्षी जिलों में टॉप पर चतरा 10 करोड़ रुपये का मिलेगा पुरस्कार

PHOTON NEWS RANCHI : नीति आयोग की ओर से आयोजित ऑनलाइन समीक्षा बैठक में मार्च 2025 की डेल्टा रैंकिंग के अनुसार चतरा जिला ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। देश के 112 आकांक्षी जिलों में चतरा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि जिला प्रशासन एवं विभिन्न विभागों के संयुक्त प्रयासों, नवाचारों तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का प्रतिफल है। इसके अलावा गढ़वा को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए भी चुना गया है। नीति आयोग ने यह जानकारी शुक्रवार को ऑनलाइन बैठक के माध्यम से साझा की। इसमें चतरा जिले की बहुआयामी प्रगति विशेषकर स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन तथा बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में सराहा गया। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिले को नीति आयोग द्वारा 10 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी, जिसका उद्देश्य जिला स्तर पर विकासात्मक पहलों को और अधिक गति देना है।

डेल्टा रैंकिंग के अनुसार किया गया चयन

- जिला प्रशासन व विभिन्न विभागों के संयुक्त प्रयासों का सामने आया रिजल्ट
- शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए चुना गया गढ़वा

BRIEF NEWS

अवैध विदेशी शराब के साथ एक गिरफ्तार

SARAIKELA : उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह के निर्देश पर उत्पाद अधीक्षक सौरभ तिवारी के नेतृत्व में शुक्रवार को गम्हरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत रायबासा स्थित एक मकान में छापेमारी की गई। यहां 105 पेटी अवैध विदेशी शराब (किंग्स गोल्ड व्हिस्की-750 मिली. प्रति बोतल) बरामद की गई, जिसकी कुल मात्रा 945 लीटर है। इन बोतलों पर फॉर सेल इन अरुणाचल प्रदेश अंकित था। घटनास्थल से एक अभियुक्त रोहित कुमार को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई उत्पाद अवर निरीक्षक नीरज कुमार के नेतृत्व में उत्पाद बल की टीम द्वारा की गई।

बर्तन लेकर नगर निगम के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग

JAMSHEDPUR : हांडी, तशला और बर्तन लेकर शुक्रवार को मानगो डिमना बस्ती के सैकड़ों लोग नगर निगम कार्यालय के सामने पहुंच गए। 100 से अधिक परिवार पिछले छह महीने से कचरा नहीं उठने और पानी की किल्लत से त्रस्त हैं। कचरे का पहाड़ खड़ा हो चुका है, जिससे पूरे इलाके में बदबू और बीमारी फैल रही है। बस्तीवासियों ने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साफ-सफाई तथा नियमित पानी की आपूर्ति की मांग की। स्थानीय लोगों ने बताया कि दिन में कुछ मिनट ही पानी आता है, जिसके कारण उन्हें दो किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इलाके में लगातार मकान और बिल्डिंग बन रहे हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर नगर निगम कुछ नहीं कर रही। कई बार शिकायत के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है।

सर्पदंश से सात साल के बच्चे की गई जान

GHATSHILA : पूर्वी सिंहभूम जिले के गुड़ाबांदा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंहपुरा गांव में सर्पदंश से सात वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, पारा शिक्षक दिनेश महतो का पुत्र हर्ष महतो गुरुवार की रात जमीन पर सोया था। इसी दौरान किसी विषैले सांप ने उसे डस लिया। बच्चा जोर-जोर से रोने लगा और कहा कि उसे पेट में दर्द हो रहा है। परिजन आनन-फानन उसे घाटशिला के एक नर्सिंग होम ले गए। यहां बच्चे की स्थिति गंभीर होने के कारण उसे घाटशिला स्थित अनुमंडल अस्पताल ले जाने को कहा गया। जब बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया, वहां चिकित्सक डॉ. रामचंद्र मुर्मू ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पिकअप वाहन की चपेट में आकर कार क्षतिग्रस्त

GOBINDPUR : साहिबगंज स्टेट हाइवे पर गोपीकांदर थाना क्षेत्र के कुड़ुंबा चौक के पास शुक्रवार को कार व पिकअप वाहन के बीच जोरदार टक्कर हो गयी। हादसे में कार का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। कार चालक ऑफिसर मड़ैया ने बताया कि वह महेशपुर थाना क्षेत्र के बाबईखोड़ा गांव से दुमका निजी काम के लिए जा रहा था। आगे-आगे पिकअप वाहन भी जा रहा था।

अलग-अलग कमरों में मिले शव, डायन बिसाही से जुड़ा हो सकता है मामला

लोहरदगा में डबल मर्डर से दहशत युवक व उसकी दादी की हुई हत्या

PHOTON NEWS LOHARDAGA : लोहरदगा जिले में शुक्रवार की सुबह दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। सदर थाना क्षेत्र के भक्सो गांव में एक 16 वर्षीय किशोर और उसकी दादी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दोनों के शव घर के अलग-अलग कमरों में मिले हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। मृतकों की पहचान 16 साल के रितेश उरांव और उसकी दादी बरिया उरांव के रूप में हुई है। शुरूआती जांच में पता चला है कि रितेश की हत्या टांगी से गला काटकर की गई, जबकि बरिया उरांव की गला दबाकर जान ली गई। घटना के वक्त घर के अन्य सदस्य सो रहे थे और उन्हें हत्या की भनक तक नहीं लगी। यह वारदात रात के किसी समय अंजाम दी गई प्रतीत होती है।

घर के अन्य सदस्यों को नहीं लगी भनक

पुलिस ने बरामद किया हत्या में इस्तेमाल हथियार

पुलिस ने घटनास्थल से हत्या में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद कर लिया है। हालांकि, हत्या के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और जल्द ही सच्चाई सामने लाई जाएगी।

ग्रामीणों में हो रही कई तरह की चर्चा

इस दोहरे हत्याकांड को लेकर ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि यह हत्या डायन बिसाही जैसी सामाजिक कुरीति से जुड़ी हो सकती है। हालांकि, पुलिस ने इस एंगल की भी जांच शुरू कर दी है लेकिन अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है।

पुलिस कर रही सभी पहलुओं की जांच

सदर थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर ने बताया कि इस दोहरे हत्याकांड की गंभीरता से सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा, उसे कानून के तहत सख्त सजा दिलाई जाएगी।

अलग-अलग कांडों में फरार दो आरोपी हुए गिरफ्तार, भेजे गए जेल

DUMKA : शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में अलग अलग कांडों में फरार चल रहे दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी के आरोपी बरमसिया के रेजाउल अंसारी व मारपीट के आरोपी मलूटी के आकाश बाउरी को शुक्रवार को सेंट्रल जेल दुमका भेज दिया। रेजाउल अंसारी के विरुद्ध बरमसिया कैंप से बिजली के सामग्री चोरी के आरोप में कांड संख्या 90/24 दर्ज है। आकाश बाउरी मलूटी में पिकनिक मनाने आये लोगों के साथ मारपीट करने के आरोप कांड संख्या 1/24 दर्ज है।

शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने 10वीं बोर्ड की टॉपर शांभवी को किया सम्मानित

PHOTON NEWS JAMSHEDPUR : शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने शुक्रवार को जमशेदपुर की होनहार छात्रा शांभवी जायसवाल को सम्मानित किया। लोयोला स्कूल की इस प्रतिभावान छात्रा ने आईसीएसई-2025 की 10वीं बोर्ड परीक्षा में सभी विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त कर पूरे देश में टॉप किया है। इस उपलब्धि पर मंत्री ने उसे एक लाख रुपये की प्रतिभा प्रोत्साहन राशि प्रदान कर सम्मानित किया। समारोह में मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि शांभवी की सफलता पूरे झारखंड के लिए गर्व की बात है। ऐसी प्रतिभाएं राज्य की असली पहचान होती हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार होनहार विद्यार्थियों को हरसंभव सहयोग और प्रोत्साहन देती रही है और आगे भी देती रहेगी। शांभवी की मेहनत, लगन और अनुशासन हर छात्र के लिए प्रेरणास्रोत हैं। सम्मान मिलने के बाद शांभवी जायसवाल ने अपने माता-पिता, शिक्षकों और स्कूल प्रशासन का आभार व्यक्त किया।

पुलिस व उग्रवादियों में मुठभेड़, कई सामान बरामद

PHOTON NEWS LOHARDAGA : पुलिस और जेजेएमपी के उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें दोनों ओर से फायरिंग हुई। पुलिस को भारी पड़ता देखकर उग्रवादी जंगल और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गये। सर्च के दौरान कई सामान बरामद किये गये है। एसडीपीओ वेदांत शंकर ने शुक्रवार को बताया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली कि पेशरार थाना अन्तर्गत ग्राम हरकट्ठा के जंगल में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के सुप्रिमो रविन्द्र यादव, सचिन, विशाल, कालेश्वर खेरवार, शिव अपने दस्ता के साथ भ्रमणशील है।

सभी उग्रवादी कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक लोहरदगा और कमांडेंट 32वी वाहिनी सशस्त्र सीमा बल लातेहार के निर्देश पर गुरुवार रात छापेमारी की गयी। छापेमारी टीम में किस्को एसडीपीओ वेदान्त शंकर के साथ जी कंपनी सशस्त्र सीमा बल के कंपनी कमांडर इन्स्पेक्टर मनीष कुमार चौबे, हर्षवर्धन सिंह, कुलदीप राज टोप्पो, गैलन रजवार, नरेश कुमार यादव सहित अन्य शामिल थे। टीम ने सूचना का सत्यापन करते जब पेशरार से आगे निकली तो पता चला कि दस्ता हरकट्ठा से आगे निकल गया है। टीम दस्ता के जाने के रास्ते को सर्च करते हुए जब लातेहार जिला के केदलटोली पहुंची तो दस्ते के होने की जानकारी प्राप्त हुई। टीम को सतर्क करते हुए जब दस्ते के तरफ सतर्कता के साथ आगे बढ़ने लगी तो जेजेएमपी दस्ता की ओर से पुलिस बल को लक्षित कर गोली बारी किया जाने लगा।

टाटानगर रेल पुलिस के सहयोग से दबोची गई महिला तस्कर, हो रही पूछताछ

मानव तस्करी का भंडाफोड़, दो नाबालिग लड़कियां कराई गईं मुक्त

PHOTON NEWS CHAIBASA : झारखंड में एक बार फिर मानव तस्करी का उद्भेदन किया गया है। महिला तस्कर को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार, गुवा पुलिस को सूचना मिली थी कि गुवा थाना अंतर्गत नुईया गांव की लक्सरा टोला निवासी सुकराम तिरिया की 16 वर्षीय पुत्री और नोवामुंडी की एक नाबालिग को एक महिला नौकरी का झांसा देकर गुवा-टाटा पैसेंजर ट्रेन से टाटानगर ले गई है, जहां से उसे चेन्नई ले जाने का प्लान है। घटना की सूचना मिलते ही गुवा थाना प्रभारी ने नोवामुंडी थाना की पुलिस से संपर्क

साधा और तुरंत टाटानगर रेल पुलिस को अलर्ट किया। इसके बाद टाटानगर स्टेशन पर सघन तलाशी अभियान चलाया गया। टाटानगर स्टेशन पर पहुंची महिला के साथ दोनों नाबालिग लड़कियां पाई गईं। महिला से पूछताछ में पता चला कि वह इन्हें चेन्नई ले जाकर घरेलू काम या होटल में नौकरी दिलाने की बात कह रही थी। पुलिस ने दोनों नाबालिगों को बाल संरक्षण समिति के माध्यम से परिजनों को सौंपा। बताया जाता है कि महिला के साथ गांव की दो अन्य लड़कियां भी ट्रेन में सवार थीं। लेकिन, बड़ाजामदा स्टेशन पहुंचने पर उन्हें महिला की बातों पर संदेह हुआ और वे सतर्क होकर वहीं ट्रेन से उतर गईं। घर लौटने के बाद उन्होंने परिजनों को पूरी बात बताई, जिससे स्थिति की गंभीरता सामने आई। गुवा थाना क्षेत्र की जेएसएलपीएस जेंडर सीआरपी गीता देवी व पीएलवी दिल बहादुर इस सूचना के आधार पर नाबालिग लड़की के पिता को लेकर गुवा थाना पहुंचे, जहां पूरे मामले की जानकारी दी।

पलामू में बाइक की डिक्की से 30 लाख का जेवर उड़ाने वाले दो अपराधियों को पुलिस ने दबोचा

PHOTON NEWS PALAMU : पलामू जिले के लेस्लीगंज में 20 जून की देर शाम 30 लाख रुपए की जेवर बाइक की डिक्की से गायब करने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस घटना को ओडिशा और आंध्र प्रदेश के अपराधियों ने अंजाम दिया था। जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के लादी में किराये के मकान में रहते हुए इस घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने रेकी करने वाले ओडिशा और आंधप्रदेश के एक-एक अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य दो अपराधी ज्वेलरी लेकर फरार हैं। उनकी पहचान हो गयी है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

लेस्लीगंज में ज्वेलरी गायब होने और मेदिनीनगर शहर एवं सदर में

मामले की जानकारी देते पुलिस अधिकारी ● फोटोन न्यूज

सोने की चेन छिनतई की तीन घटनाएं होने पर तेजी से अनुसंधान किया गया। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए चैनपुर के लादी में छापेमारी की गयी। रामजीत शर्मा के घर से दो संदिग्ध को पकड़ा गया। पूछताछ में घटना का खुलासा हुआ। एसपी ने बताया कि घटना के अगले दिन ज्वेलरी गायब करने वाले दो अपराधी सोने-चांदी के सामान लेकर फरार हो गए थे। ऐसे में गायब हुई ज्यादातर ज्वेलरी नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि पिछले छह माह से रामजीत शर्मा के घर पर अपराधी रह रहे थे। वे बार बार बदल जाते थे। बावजूद मकान मालिक ने इसकी जानकारी नहीं दी, लेकिन पुख्ता सूचना तंत्र के बल पर चार दिनों के भीतर सफलता प्राप्त कर ली गई।

दोनों अपराधियों ने लातेहार के मनिका में भी इसी तरह की घटना को अंजाम दिया था। वहां से गायब किए गए आभूषण भी बरामद किए गए हैं। इनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। चोरी गए सोने के 135 ग्राम और चांदी के 1150 ग्राम बने हुए जेवर बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अपराधियों में आंध्रप्रदेश के विशाखापटनम के नातवरम कोंडा के दुर्गा प्रसाद (27) और ओडिशा के गंजम जिले के असका कोराटोली के आवला बलराम (25) शामिल हैं। इनमें से आवला बलराम के खिलाफ बिहार के मुज्जफरपुर एवं नायागढ थाना में एक-एक आपराधिक मामला दर्ज है।

सांसद वीडी राम ने समिति की बैठक में रेलवे से जुड़े मामले को उठाया

PHOTON NEWS PALAMU : सांसद पलामू विष्णु दयाल राम की अध्यक्षता में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के सभागार में शुक्रवार दोपहर साढे तीन बजे तक ह्यमंडल संसदीय समितिह्न रेलवे की बैठक हुई। बैठक में पलामू संसदीय क्षेत्र के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के अंतर्गत रेलवे से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में मुख्य रूप से महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह, मंडल रेल प्रबंधक उदय सिंह मीना, मंडल वाणिज्य प्रबंधक राजीव रंजन, सांसद रेलवे पदाधिकारी एवं उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि एलएचएस, आरयूबी, आरओबी, हैदरनगर के डाली और उंटारी रोड के लहर बंजारी में रैंप के साथ फुट ओवरब्रिज का निर्माण किया

जाएगा। मोहम्मदगंज के बेगमपुरा, उंटारी रोड के सतबहिनी और हैदरनगर में आरओबी बनाने के लिए डीपीआर तैयार किया जा रहा है। अमृत भारत योजना के तहत मोहम्मदगंज, जपला और हैदरनगर पर निमार्णाधीन कार्यो की समीक्षा की गयी। जपला में नवनिर्मित आरओबी का अप्रोच का निर्माण नहीं होने से उक्त आरओबी पर सुचारू रूप से आवागमन शुरू नहीं हो पा रहा है। इस स्थान पर एप्रोच पथ बनाने के लिए भू-अर्जन विभाग को भूमि अधिग्रहण करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।

पलामू में शत्रु संपत्तियों की गुपचुप नीलामी को ले स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी

PHOTON NEWS PALAMU : भारत-पाक युद्ध (1965 व 1971) के बाद पाकिस्तान चले गए लोगों की संपत्तियों को केंद्र सरकार की ओर से शत्रु संपत्ति घोषित कर ई-नीलामी के माध्यम से नीलाम किया गया। लेकिन पलामू जिले के हुसैनाबाद अनुमंडल अंतर्गत हैदरनगर के करीमनडीह गांव (मोकहर कला पंचायत) में इन संपत्तियों की नीलामी गुपचुप ढंग से कर दी गई, जो कृषि भूमि थी। इससे न केवल स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है, बल्कि सरकार को राजस्व की भी भारी क्षति हुई है।

सूत्रों के अनुसार, कुल 11 संपत्तियों को नीलामी प्रक्रिया में शामिल किया गया, जिनका कुल रकबा लगभग 3.48 हेक्टेयर (8.6 एकड़) है और कुल आरंभिक मूल्य 10,42,868 तय किया गया था। लेकिन नीलामी की प्रक्रिया को न तो समाचार पत्रों में प्रचारित किया गया और न ही माईकिंग जैसी स्थानीय सूचना माध्यमों का सहारा लिया गया। नतीजतन, आम लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी और 25 जून को हुई नीलामी में महज एक ही परिवार के चार सदस्य शामिल हुए। अंततः उसी परिवार के दो लोगों ने ये जमीनें हासिल कर लीं। 22 जून तक ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि थी, जबकि 23 जून को पंचायत भवन पर नोटिस चिपकाया गया और कुछ ही समय बाद हटा भी लिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि जब उन्हें जानकारी मिली तब तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका था, जिससे वे भाग नहीं ले सके। पंचायत की मुखिया नजमा खातून के परिजन ही नीलामी में शामिल हुए, जिससे पक्षपात का स्पष्ट संकेत मिलता है। मुखिया पति नवाजिश खान का दावा है कि सूचना पंचायत सचिवालय व अंचल कार्यालय में प्रकाशित की गई थी, लेकिन राजद के प्रदेश सचिव रिजवान खां एवं स्थानीय लोगों का कहना है कि जानबूझकर सूचना छुपाई गई।

ग्रामीणों ने सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि इस नीलामी को रद्द किया जाए और पुनः पारदर्शी तरीके से नीलामी की जाए, ताकि सभी इच्छुक लोग भाग ले सकें और सरकार को भी उचित राजस्व प्राप्त हो।

एक लाख का ब्राउन शुगर जब्त, पांच लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

PHOTON NEWS DHALBHUMGARH : पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूमगढ़ थाना अंतर्गत दूधचुआं गांव से पुलिस ने एक लाख रुपये का ब्राउन शुगर जब्त किया है। यहां बांस टाल मैदान में ट्रक की एक चेसिस के केबिन में ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री करते हुए पुलिस ने पांच युवकों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को देर रात हुई इस कार्रवाई में पुलिस को पता चला कि चेसिस का ड्राइवर शमशेर अहमद उर्फ भूटान जमशेदपुर से बालेश्वर जा रहा था। पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया है, उसमें नरसिंहगढ़ निवासी 35 वर्षीय शमशेर अहमद उर्फ भूटान, नरसिंहगढ़ निवासी 26 वर्षीय चिंटू राय, दूधचुआं निवासी 33 वर्षीय गौतम महतो, नरसिंहगढ़ के कोकपाड़ा निवासी 31 वर्षीय राहुल दुबे और मानगो-एमजीएम थाना क्षेत्र के दलदली निवासी 30 वर्षीय कामाख्या मुखर्जी उर्फ फेकू शामिल है। इनके पास से विभिन्न पैकिंग में मौजूद कुल 4.17 ग्राम ब्राउन शुगर तथा 3500 रुपये नकद, पांच एंड्रॉयड फोन और ट्रक की चेसिस भी जब्त की गई है।

बिष्टुपुर राम मंदिर सहित लौहनगरी के 10 स्थानों से निकली महाप्रभु की भव्य रथयात्रा, गाजे-बाजे की धुन पर थिरकते रहे श्रद्धालु

जय जगन्नाथ...के जयकारों से गूंजता रहा शहर

PHOTON NEWS JAMSHEDPUR : सुसज्जित रथों पर सवार महाप्रभु जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र व सुभद्रा शुक्रवार को दोपहर में जब निकले, तो पूरा माहौल आध्यात्मिक रंग से सराबोर हो गया। सड़कों पर सिर्फ जय जगन्नाथ... के जयकारे सुनाई दे रहे थे। लौहनगरी से इस बार 10 स्थानों से महाप्रभु की रथयात्रा निकली, जिसमें सबसे भव्य यात्रा बिष्टुपुर स्थित राम मंदिर की थी। यहां इस्कॉन के अलावा शहर के कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने मिलकर इस अनुष्ठान को संपन्न कराया। रथ यात्रा हरे कृष्णा-हरे राम के संकीर्तन के साथ दोपहर करीब 2.30 बजे

साकची के ताप्ती रोड स्थित उत्कल एसोसिएशन से निकली रथयात्रा में भाग लेते श्रद्धालु ● फोटोन न्यूज

मंदिर परिसर से निकली, जो गोपाल मैदान, जुस्को गोलचक्कर, स्ट्रेट माइल रोड, कीनन स्टेडियम, साकची बड़ा गोलचक्कर होते हुए साकची वाहन पड़ाव स्थल तक गई। लगभग 4.5 किलोमीटर की यह यात्रा भक्ति, भव्यता और सामाजिक समरसता का प्रतीक बन गई थी। यात्रा के दौरान सड़क के किनारे विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने शिविर लगाकर भक्तों को शीतल पेय व जलपान भेंट किया। रथयात्रा को सफल बनाने में लगभग 1000 स्वयंसेवक सक्रिय रहे।

रथ खींचने के लिए भक्तों में दिखा उत्साह

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले में शुक्रवार को धूमधाम से रथयात्रा निकाली गई। इस दौरान रथ खींचने के लिए भक्तों में खासा उत्साह दिखा। चाईबासा के जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू हुई जो सदर बाजार, रुंगटा चौक, अमला टोला, सदर थाना होते हुए मौसीबड़ी (दुर्गा मंदिर) पहुंची। पूरा क्षेत्र जय जगन्नाथ.. के उद्घोष से गूंज उठा। रथ पर सवार पंडित-पुरोहित श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद की बौछार करते रहे। प्रसाद में लड्डू के अलावा नारियल, आम, केला, सेब, अमरुद समेत विभिन्न प्रकार के फल आदि अर्पित किए गए थे। चक्रधरपुर के भी विभिन्न स्थानों से महाप्रभु की रथयात्रा निकली। इसके अलावा सोनुवा, मनोहरपुर, केरा, गोपीनाथपुर, लौजोड़ा, कराईकेला, सरायकेला आदि में भी रथयात्रा निकाली गई।

इनकी रही भागीदारी

इस्कॉन जमशेदपुर के प्रमुख स्वामी पद्मनाभ जगन्नाथ दास की अगुवाई में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, सैन्य मातृ शक्ति, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी, क्रीड़ा भारती, द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी, रॉबिनहुड आर्मी, ग्रीन कैप्स फाउंडेशन, ब्लड वॉरियर्स, साइलेंट टेल्स एनजीओ, अरका जैन यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी सहित कई संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल थे।

बीमारी से परेशान युवक ने की खुदकुशी

PHOTON NEWS JAMSHEDPUR : बीमारी से परेशान होकर एक युवक ने फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली है। घटना शुक्रवार सुबह की है। मामला जमशेदपुर के सितारामडेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भुइयांडीह बाबरी बस्ती का है, जहां 38 वर्षीय जोशी बाउरी ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों ने उसे आनन-फानन में एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार, घटना के वक्त जोशी घर पर अकेला था। उसकी मां और पत्नी घर पर नहीं थीं। जब वे लौटे तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी खटखटाने के बावजूद दरवाजा नहीं खुला, जिसके बाद पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया। अंदर देखने पर जोशी

पंखे के सहारे लटका हुआ था। बताया जा रहा है कि वह भुइयांडीह में लकड़ी टाल में काम करता था और पिछले एक हफ्ते से बीमारी को लेकर मानसिक रूप से परेशान था। मृतक के परिवार में उसका एक बेटा है और पत्नी गर्भवती हैं। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जगन्नाथपुर मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, जमकर हुई खरीदारी

सीएम हेमंत ने भेजा संदेश

सीएम हेमंत सोरेन ने 'एक्स' पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हर साल मैं वहां उपस्थित होता था। अभी आदरणीय बाबा दिशोम गुरुजी अस्वस्थ हैं, इसलिए मैं रथयात्रा में शामिल नहीं हो पाया हूं। भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय गुरुजी जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हम सभी के बीच आएं और हमेशा की तरह अपना आशीर्वाद बनाएं रखें। भगवान जगन्नाथ सभी का कल्याण करें, धन्यवाद, जोहार!

PHOTON NEWS RANCHI : राजधानी के जगन्नाथपुर में लगे ऐतिहासिक मेले के पहले दिन भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े । लोगों का उत्साह और जोश देखते ही बनता था। इसके पूर्व श्रद्धालुओं ने मेले में पारंपरिक और गृहपयोगी चीजों की जमकर खरीदारी की और मेला में लगे झूले का आनंद उठाया।

मेले में पारंपरिक हथियार तलवार, भाला, तीर-धनुष, गृहपयोगी चीजें पईला, खुरपी, दाउली, मांदर, ढोल, नगाडा, झंझरा, कुमनी, मछली मारने का जाल, बंशी, श्रृंगार प्रसाधन की सामग्री, खिलौने, सजावट के सामान, पूजा सामग्री, तरह-तरह के झूले, मौत का कुआं, चाट और फुचका का ठेला सहित अन्य चीजों की दुकानें लगाई गई हैं।

12 सौ प्रति जोडा बिक रहा लव बर्ड : मेले में रंग-बिरंगी पक्षियों की भी बिक्री हो रही है। मेला में लव बर्ड की कीमत 12 सौ रुपये प्रति जोडा है। वहीं लललुमुनिया नामक पक्षी के एक जोडे की कीमत चार सौ रुपये, तोते की प्रति जोडे की कीमत 12 सौ रुपये, जावा नामक पक्षी 12 सौ रुपए में एक जोडा तथा बजरी पक्षी की कीमत छह सौ रुपये प्रति जोडा है।

आठ से 16 सौ रुपये में बिक रहा जाल : मेले में मछली मारने वाले जाल की बिक्री आठ से 12 सौ रुपये में बिक्री की जा रही है। दुकानदार परशुराम ने बताया कि पहले दिन बिक्री खास नहीं है, लेकिन उन्हें उम्मीहद है कि मेले के दौरान अच्छी बिक्री होगी। उन्होंने बताया कि जगन्नाथपुर मेले में हर वर्ष उनके जाल की अच्छी बिक्री होती है। इस बार भी उन्हें उम्मीरद है कि मेले में अच्छी बिक्री होगी।

मौत का कुआं व झूलों की लोगों में दिखी दीवानगी

मेले में मौत का कुआं और कई तरह के झूलों पर चढने के लिए लोगों की दीवानगी देखी गई। विशेषकर बच्चे, युवतियां और महिलाओं में झूले पर चढने का काफी क्रेज देखने को मिला। सबसे अधिक भीड़ मौत का कुआं देखनेवालों की रही। जलपरी शो नामक मौत का कुआं के शो के लिए प्रति व्यक्ति 50 रुपये में टिकटों की बिक्री हो रही थी। वहीं कई तरह के झूलों में ब्रेक डांस, बडा झूला सहित कई तरह के झूले का लोगों ने आनंद उठाया।

लंबे समय से टैक्स नहीं भरने वालों की बंद हो सकती है जलापूर्ति व कूड़ा कलेक्शन सेवा

70 हजार लोगों ने नहीं भरा होल्डिंग टैक्स, अब नगर निगम करेगा कार्रवाई

- करोड़ों रुपये का राजस्व घाटा, कई महत्वपूर्ण कामों पर पड़ रहा प्रभाव
- बार-बार नोटिस भेजे जाने के बाद भी बहुत से लोग जमा नहीं कर रहे राशि
- अब तक नहीं दिया गया वित्तीय वर्ष 2024-25 का होल्डिंग टैक्स

31 मार्च 2025 तक 1.67 लाख हाउस होल्डर्स ने जमा किए 80.64 करोड़

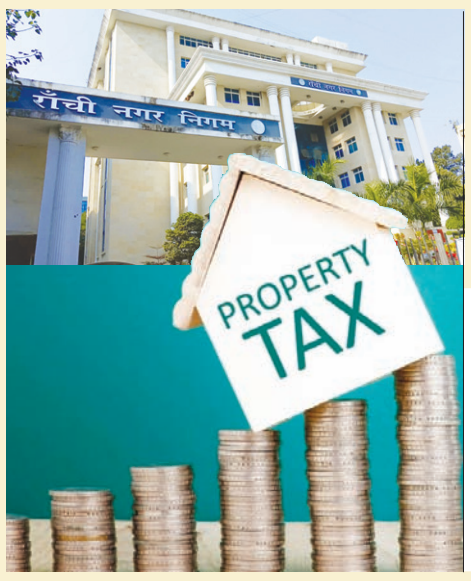

VIVEK SHARMA RANCHI : रांची नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले 70 हजार से अधिक हाउस होल्डर्स ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का होल्डिंग टैक्स अब तक जमा नहीं किया है। ऐसे में निगम को करीब करोड़ों रुपये के राजस्व घाटे का सामना करना पड़ रहा है। इससे नगर निगम का कार्य प्रभावित हो रहा है। नगर निगम लगातार बकायेदारों को नोटिस भेज रहा है, लेकिन फिर भी लोग बकाया टैक्स जमा करने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब निगम सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। लंबे समय से टैक्स जमा नहीं करने वालों की जलापूर्ति और कूड़ा कलेक्शन जैसी उपयोगिता सेवाएं बंद की जा सकती हैं।

15 परसेंट तक मिल रही छूट : नगर निगम ने करदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए पहले तिमाही में टैक्स जमा करने पर 10 से 15% तक की छूट देने की भी घोषणा की है। यह छूट डिजिटल भुगतान और डोरस्टेप कलेक्शन चैनल्स के माध्यम से करदाताओं को उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं स्पेशल कैटेगरी वाले लोगों को अलग से छूट का प्रावधान किया गया है। 30 जून तक टैक्स जमा करने वालों को छूट का लाभ मिलेगा।

डोर-टू-डोर भी टैक्स कलेक्शन

वर्तमान में निगम घर-घर जाकर, डिजिटल चैनल्स और जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से टैक्स संग्रह कर रहा है। अब निगम ने वार्ड स्तर पर सख्ती से अभियान चलाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत खाली प्लॉट की जांच की जाएगी और उन आवासीय इकाइयों पर जुमार्ना लगाया जाएगा जो बिना घोषणा के व्यावसायिक उपयोग में ली जा रही हैं।

निगम ने नागरिकों से की अपील

निगम ने नागरिकों से अपील की है कि समय पर टैक्स जमा कर अपने कर्तव्यों का पालन करें ताकि शहर को साफ, विकसित और सुविधाजनक बनाया जा सके। इस अभियान के दौरान टैक्स जमा न करने वालों की सूची सार्वजनिक की जाएगी और बार-बार चेतावनी के बाद भी भुगतान नहीं करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

टैक्स कलेक्शन के लिए सख्ती

नगर निगम की सख्ती का मुख्य उद्देश्य कर संग्रह को बढ़ाना और राजस्व में सुधार लाना है, ताकि शहर में विकास और नागरिक सुविधाओं को समय पर पूरा किया जा सके। निगम के अधिकारियों का कहना है कि शहर के विकास कार्य और साफ-सफाई अभियानों के लिए कर संग्रह आवश्यक है। बकायेदारों की वजह से योजनाओं के क्रियान्वयन में कठिनाई हो रही है। नगर निगम के उप-नगर आयुक्त गौतम प्रसाद साहू ने जानकारी दी कि नगर निगम को 83 करोड़ रुपये होल्डिंग टैक्स के रूप में प्राप्त होना था, लेकिन 31 मार्च 2025 तक 1.67 लाख घरेलू और व्यवसायिक हाउस होल्डर ने सिर्फ 80.64 करोड़ रुपये ही जमा किया। इस बीच 2019-20 से लेकर अब तक की बकाया राशि भी इस राजस्व घाटे में शामिल है।

बेड़ो में श्रद्धा व उल्लास के साथ निकाली गई भव्य रथ यात्रा

PHOTON NEWS RANCHI : भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की रथयात्रा बेड़ों प्रखंड के ईटाचिल्द्री और चनकोपी गांव में शुक्रवार को श्रद्धा, उल्लास और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। भक्तों ने जयकारों के बीच रथ को खींचते हुए भगवान को नौ दिनों के प्रवास के लिए मौसीबाड़ी पहुंचाया। ईटाचिल्द्री में सुबह पूजा, शाम को रथ यात्रा ईटाचिल्द्री गांव में सुबह 5 बजे मंदिर का कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। पुजारियों-सत्यनारायण पांडेय और पंचम नारायण के साथ यजमान लाल गोकुलनाथ शाहदेव, लाल मोहन नाथ साहदेव और लाल ईस्कैलेब नाथ साहदेव ने विधिवत पूजन-अर्चन किया। गांव के पहान टुटू उरांव द्वारा मंदिर प्रांगण में सफेद झंडा गाड़ कर पूजा संपन्न कराई गई। अपराह्न 5 बजे भक्तों ने भगवान के विग्रहों को रथ पर आरूढ़ कर जयघोषों के बीच आधा किलोमीटर दूर मौसीबाड़ी तक रथ खींचा। प्रखंड के चनकोपी गांव में भी शुक्रवार को जगन्नाथ मंदिर से रथयात्रा भव्य रूप से निकाली गई। पुजारी बालमुकुंद मिश्रा, रामवृक्ष मिश्रा और कलिंदर शुक्ला के नेतृत्व में यजमान लाल संजय नाथ शाहदेव द्वारा पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुआ। रथयात्रा एवं मेले के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन व मेला समिति की ओर से पुलिस बल के साथ वॉलंटियर्स की तैनाती की गई थी। बता दें कि चनकोपी की रथयात्रा की परंपरा लगभग 300 वर्षों से चली आ रही है, जो आज भी पूरी आस्था और परंपरा के साथ निभाई जाती है।

BRIEF NEWS

कुल्हाड़ी शाह बाबा दरगाह में किया गया कुरानखानी का आयोजन

RANCHI : शुक्रवार को अकीदत के साथ मुहर्रम महीने की पहली तारीख को हर साल की भांति कुल्हाड़ी शाह बाबा दरगाह में उर्स मनाया जा रहा है, जो यौमे आशूरा मुहर्रम की 10 तारीख तक चलेगा। शाम में दरगाह शरीफ में कुरानखानी का आयोजन किया गया। मदरसा इस्लामी मरकज के छात्रों एवं अकीदतमंदों द्वारा कुरआन की तिलावत की गई। साथ ही नारे तकबीर और नारे रिसालत के साथ दरगाह कुल्हाड़ी शाह बाबा दरगाह में मो. सईद की सरपरस्ती में शाही संदल गुलाब जल से गुस्ल दिया गया, परचम लहराया, चादर पेश की गई। मुल्क और प्रदेश की खुशहाली, अमन सलामिति की दुआ मांगी गई। मौके पर दरगाह कमेटी के महासचिव अकिलुर्रहमान खलीफा, मो महजूद,जावेद गद्दी हम लोग मौजूद थे।

इस्लामिक नए साल की शरुआत पर नवाब चिश्ती ने दी मुबारकबाद

RANCHI : रजा यूनिटी फाउंडेशन झारखंड प्रदेश अध्यक्ष जनाब नवाब चिश्ती ने इस्लामिक नए साल (1447 हिजरी) की शुरूआत पर सभी को मुबारकबाद दी। उन्होंने यह भी कहा कि 60 हिजरी का वाक्या पैगंबर मुहम्मद साहब के नवासे ने कर्बला की जंग में इमाम हुसैन एवं 72 साथियों ने सर कटाना मुनासिब समझा, लेकिन सर झुकाना नहीं। बलिदान देकर इस्लाम का परचम लहराया। दुनिया को संदेश दिया कि जंग के दौरान बातिल के आगे कभी भी झुकना नहीं चाहिए। सर सिर्फ अल्लाह की इबादत में झुकाए तीर चले या तलवार। उन्होंने यह भी कहा कि यह 1447 हिजरी नया साल सभी के जीवन में खुशियां, बरकत और अमन लेकर आए।

मस्जिद जाफरिया में दस दिवसीय जिक्र-ए-मजलिस शुरू

RANCHI : मस्जिद-ए-जाफरिया रांची में जिक्र-ए-मजलिस शहीदाने कर्बला का आगाज मुहर्रम का चांद देखते ही शुरू हो चुका है। मुहर्रम का चांद देखते ही शिया मुसलमानों के घर में हर तरफ या हुसैन की सदा गूंजने लगी। मस्जिद- ए-जाफरिया में 10 दिवसीय मजलिसे जिक्रे शहीदाने कर्बला एक मुहर्रम से दस मुहर्रम तक रात्रि 8:00 से किया गया है। यानी 27 जून से 6 जुलाई तक होगा। इस मजलिस को मुख्य रूप से हाजी मौलाना सैयद तहजीब उल हसन रिजवी इमाम जुमा व जमाअत मस्जिद ए जाफरिया रांची संबोधित करेंगे।

पुलिसकर्मियों को मिली राहत, इलाज के लिए 1.67 करोड़ की सहायता राशि मंजूर

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड में पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। झारखंड पुलिस के 622 कर्मियों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए कुल 1.67 करोड़ रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। यह धनराशि झारखंड पुलिस सहायता एवं कल्याण कोष से जारी की गई है। इस सहायता का लाभ उन पुलिसकर्मियों को मिलेगा जिन्होंने कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट, हृदय रोग या अन्य जटिल ऑपरेशनों के लिए चिकित्सा अनुदान के तहत आवेदन किया था। यह आर्थिक सहयोग उन्हें महंगे इलाज का बोझ उठाने में मदद करेगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा इस निर्णय को एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे पुलिसकर्मियों के लिए यह आर्थिक राहत न केवल उनके इलाज में सहायक होगी, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी सशक्त बनाएगी ताकि वे भविष्य में अपने कर्तव्यों का बेहतर निर्वहन कर सकें।

पुलिस कर्मियों का बढ़ेगा मनोबल : झारखंड पुलिस प्रशासन की यह पहल यह दशार्ती है कि वह न केवल राज्य की सुरक्षा में लगी है, बल्कि अपने कर्मियों की भलाई और स्वास्थ्य को लेकर भी सजग है। इस फैसले से पुलिस बल में काम करने वालों का मनोबल भी बढ़ेगा। राज्य सरकार और पुलिस विभाग के इस सहयोगात्मक कदम की विभाग में सराहना हो रही है।

10-बेड आईसीयू परियोजना के तहत ट्रेनिंग के दौरान रिम्स में दी गई विशेष जानकारी

सरकारी हॉस्पिटलों में बनाई जा रही क्रिटिकल यूनिट

PHOTON NEWS RANCHI : शुक्रवार को रिम्स में 10-बेड आईसीयू परियोजना के अंतर्गत एक व्यापक क्रिटिकल केयर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह परियोजना खासकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्थित सरकारी अस्पतालों की गहन चिकित्सा क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसका विचार कोविड-19 की डेल्टा लहर के दौरान सामने आया था। इस पहल के अंतर्गत देशभर के सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह सुसज्जित 10-बिस्तरों वाले आईसीयू की स्थापना की जा रही है। जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं की खाई को पाटा जा सके। झारखंड में इस परियोजना को कोल इंडिया की सहायता और राज्य सरकार के सहयोग से लागू किया जा रहा है। दो चरणों में लागू होगी परियोजना परियोजना को दो चरणों में लागू किया जा रहा है। पहले चरण में रांची, गुमला, लातेहार, चतरा और खूंटी जिलों के सदर अस्पतालों को रिम्स रांची में स्थापित टेली-आईसीयू हब से जोड़ा गया है। परियोजना शुरू होने से पहले इन अस्पतालों में आधुनिक क्रिटिकल केयर उपकरण, केयर ईएमआर प्लेटफार्म और टेली-आईसीयू सिस्टम स्थापित किया गया। रिम्स रांची में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में पांचों जिलों के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण के दौरान आईसीयू देखभाल के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया जैसे बेसिक और एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट, पेलिएटिव केयर, ट्रॉमा मैनेजमेंट, वेंटिलेटर संचालन और आईसीयू प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा फोर एक्सेस, सिडेशन और मानसिक आपात स्थितियों जैसे विषयों पर भी सैद्धांतिक और व्यवहारिक सत्र आयोजित किए गए।

10 राज्यों में योजना लागू

यह प्रशिक्षण न केवल आईसीयू स्टाफ की दक्षता को बढ़ाने हेतु है, बल्कि सेवाओं की गुणवत्ता को भी मानकीकृत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह पहल पांच स्तंभों पर आधारित है। जिसमें आईसीयू उपकरण, केयर प्लेटफार्म, टेली-आईसीयू, प्रशिक्षण और सामुदायिक भागीदारी शामिल है। ई-गवर्नमेंट फाउंडेशन द्वारा संचालित यह परियोजना झारखंड से पहले 10 अन्य राज्यों में चल रही है।

महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता, 30 जून को लगेगी मेमोग्राफी मशीन

सदर अस्पताल में जल्द शुरू हो जाएगी ब्रेस्ट कैंसर की जांच

PHOTON NEWS RANCHI : महिलाओं के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए रोटरी क्लब की ओर से सदर अस्पताल रांची में 30 जून को अत्यधुनिक डिजिटल मेमोग्राफी मशीन वीनस डीआरवी प्लस लगाई जाएगी।

यह जानकारी शुक्रवार को रोटरी क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता क्लब के प्रवक्ता प्रवीण राजगढ़िया ने दी। उन्होंने बताया कि रोटरी क्लब ऑफ रांची की ओर से प्रोजेक्ट आरोग्यम- बैटलिंग ब्रेस्ट कैंसर के तहत यह मशीन लगाया जा रहा है। इसमें दक्षिण कोरिया के रोटरी क्लब सुवोन-नोसोंग डी-3750 का भी सहयोग मिला है। मशीन की कीमत लगभग 45 लाख रुपये है। रोटरी क्लब रांची के अध्यक्ष गौरव बागरॉय ने बताया कि इस मशीन लगने के बाद सदर अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर जांच की सुविधा काफी कम दर पर उपलब्ध होगी। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क मिलेगी। इस पहल का उद्देश्य सिर्फ एक मशीन स्थापित करना नहीं है, बल्कि महिलाओं को समय पर जांच के लिए प्रोत्साहित करना और स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना है। उन्होंने बताया कि मशीन का उद्घाटन मुख्य अतिथि डीजी रोटेरियन बिपिन चाचन, फर्स्ट लेडी रोटेरियन शिल्पी चाचन, सिविल सर्जन डॉ प्रभात कुमार करेंगे। उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल न केवल जिला मुख्यालय का प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र है, बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी जीवन रेखा है। हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक जरूरतमंद मरीज को समय पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मिले।

क्यों जरूरी है यह मशीन

40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में स्तन कैंसर का जोखिम अधिक होता है। प्रारंभिक अवस्था में कैंसर की पहचान से न केवल इलाज आसान होता है, बल्कि जान भी बचाई जा सकती है। मेमोग्राफी एक प्रभावी तकनीक है। इससे छोटी से छोटी गांठ, ऊतक में बदलाव या असामान्य संरचना का पता क्लिनिकल लक्षणों के प्रकट होने से पहले लगाया जा सकता है। यह सुविधा स्तन कैंसर की प्रारंभिक जांच और रोकथाम में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

मैमोग्राफी वीनस डीवीआर प्लस मशीन की विशेषता

अत्यधुनिक मैमोग्राफी वीनस डीवीआर प्लस में कई विशेषताएं हैं। यह फुल फील्ड डिजिटल मैमोग्राफी (एफएफडीएम) तकनीक पर आधारित है। इसका स्मार्ट एइसी तकनीक मरीज को आवश्यकतानुसार सटीक मात्रा में एक्स-रे डोज देता है। यह उच्च गुणवत्ता वाली इमेजिंग इमेज स्क्रीन पर मात्र 10 सेकंड में दे देती है। कम दबाव और दर्द रहित जांच के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई कंप्रेशन पैडल्स है। घने स्तन ऊतक में भी स्पष्ट पहचान की सुविधा उपलब्ध है। रोटेरियन जो इस प्रोजेक्ट को मदद करनेवालों में बिपिन चाचन, सुरेश साबू, बिनोद सरावगी, रविंदर सिंह चड्ढा, सुमित अग्रवाल, रमेश धरणीधरका, ललित त्रिपाठी, पवन जायसवाल, आदित्य मल्होत्रा, राजेश नाथ शाहदेव सहित अन्य शामिल हैं।

मानव जीवन यात्रा को दिखाएगी चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति

RANCHI : आषाढ़ शुक्ल द्वितीया रथ यात्रा के अवसर पर शुक्रवार को रांची के मेन रोड स्थित चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति ने पंडाल निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। भूमि पूजन कार्यक्रम में चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के संस्थापक सदस्य अध्यक्ष रमेश सिंह सहित कई अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे। चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति का पूजा पंडाल इस बार फिर से नयी थीम पर आधारित होगा। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सांस्कृतिक संध्या का आयोजन नवरात्र के दौरान किया जायेगा। साथ ही पूजा के दौरान सुरक्षा के खास इंतजाम किए जाएंगे। थीम आधारित लाइटिंग भी मां भवानी के भक्तों को खास तौर पर आकर्षित करेगी।

पतरातू पावर प्लांट के निर्माण में लाएं तेजी : अमरदीप सिंह

PHOTON NEWS RANCHI : केंद्रीय उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी) के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने झारखंड, सिक्किम, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में मेगा आधारभूत संरचना परियोजनाओं को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और परियोजना समर्थकों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) द्वारा सुगम अंतर-मंत्रालयी और राज्य समन्वय के माध्यम से मुद्दे के समाधान में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। बैठक में झारखंड में 34213 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 11 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के 18 मुद्दों की समीक्षा की गयी। पतरातू थर्मल पावर स्टेशन की विस्तार परियोजना फेज-1 की समीक्षा की गयी। सचिव ने पतरातू पावर प्लांट के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया। यह परियोजना एनटीपीसी/ पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (पीयूवीएनएल) के माध्यम से विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना का लक्ष्य कुल 4000 मेगावाट की क्षमता स्थापित करना है। इसमें प्रथम चरण में 800 मेगावाट की तीन इकाइयां शामिल हैं, जो कुल मिलाकर 2400 मेगावाट की होंगी। यह ब्राउनफील्ड विस्तार परियोजना मौजूदा पतरातू थर्मल पावर स्टेशन स्थल पर स्थापित की जा रही है। यह परियोजना सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित है, जो बेहतर दक्षता और कम उत्सर्जन को सक्षम बनाती है।

गहवा माई मंदिर से निकली भव्य रथ यात्रा

नेपाल के साथ भारत से भी पहुंचे श्रद्धालु

AGENCY EAST CHAMPARAN : जिले के रक्सौल से सटे नेपाल के बीरगंज शहर स्थित प्रसिद्ध शक्ति पीठ गहवा माई मंदिर से शुक्रवार को भव्य रथ यात्रा निकाली गई।

इस अवसर पर नेपाल के साथ ही भारत के कई जिलों से हजारों की संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालु पहुंचे और श्रद्धापूर्वक रथ यात्रा में भाग लिया।

रथ यात्रा बीरगंज के गहवा माई मंदिर से प्रारंभ होकर पूरे बीरगंज शहर का भ्रमण किया।

उल्लेखनीय है,कि इस रथ यात्रा का आयोजन जगन्नाथ पुरी मंदिर की परंपरा से प्रेरित होकर पिछले तीन वर्षों से किया जा रहा है। गहवा माई मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि यह रथ यात्रा भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में धार्मिक आस्था का प्रतीक बन चुकी है।

इस बार भी रक्सौल सहित सीमावर्ती क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। रथ विशेष रूप से सिसम व सखुआ की लकड़ी से निर्मित किया गया है और इसका आकार जगन्नाथ पुरी मंदिर के रथ के समान बनाया गया है। श्रद्धालुओं ने रथ को रस्सियों से खींचते हुए पूरे नगर का परिभ्रमण कराया। रथ यात्रा के दौरान नगर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। प्रत्येक चौक-चौराहे पर सुरक्षा कर्मी तैनात थे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह-जगह शीतल पेयजल की व्यवस्था भी की गई थी। तेज धूप और भीषण गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था। रथ यात्रा में भक्तों की आस्था, भक्ति और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। यह आयोजन भारत-नेपाल के सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को और मजबूत करता है।

BRIEF NEWS

ब्रह्माकुमारी संस्था ने मेडिटेशन कार्यक्रम का किया आयोजन

BHAGALPUR : जिले के समीक्षा भवन सभागार में शुक्रवार को प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एवं प्रशासन सेवा प्रभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक विशेष मेडिटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कर्मयोग और सुशासन को कार्य संस्कृति में स्थापित करना था। कार्यक्रम में जिला मुख्यालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी शामिल हुए। सभी प्रतिभागियों ने ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और कार्यक्षमता में वृद्धि के उपायों पर अनुभव साझा किया।

ब्रह्माकुमारी संस्थान के प्रतिनिधियों ने कर्मयोग को प्रशासनिक जीवन में लागू करने के प्रभावी तरीकों पर प्रकाश डाला। साथ ही, नियमित मेडिटेशन को मानसिक संतुलन, तनाव प्रबंधन और बेहतर शासन व्यवस्था के लिए जरूरी बताया। कार्यक्रम के अंत में सभी कर्मियों को आत्मिक उन्नति और सेवाभाव से कार्य करने का संकल्प दिलाया गया।

मुहर्रम को लेकर अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की हुई बैठक

ARARIA : फारबिसगंज अनुमंडल कार्यालय के सभागार में मुहर्रम को लेकर अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक एसडीएम रंजीत रंजन की अध्यक्षता में हुई। इसमें मोहर्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर विचार विमर्श किया गया। मोहर्रम को लेकर ताजिया जुलूस और उसके रूट के साथ सड़क पर बने गड्ढे और पेड़ों की टहनियों की छंटाई के साथ हुड़दंगियों पर लगाम लगाने को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया। एसडीएम रंजीत रंजन ने सदस्यों के द्वारा उठाए गए मुद्दे को लेकर फारबिसगंज, जोगबनी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, नरपतगंज नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी और अनुमंडल के अधीनस्थ प्रखंडों के बीडीओ और सीओ को विधि व्यवस्था संधारण, सड़क पर बने गड्ढों की मरम्मती के साथ टहनियों की छंटाई और अन्य समुचित व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

पटना हाईकोर्ट के फैसले से राज्य सरकार को मिली राहत

हटाई गई 19,858 सिपाहियों के स्थानांतरण पर लगी अंतरिम रोक

AGENCY PATNA : पटना उच्च न्यायालय ने बिहार पुलिस में 19,858 सिपाहियों के बड़े पैमाने पर किए गए स्थानांतरण पर शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने इन ट्रांसफर पर लगी अंतरिम रोक को हटा दिया है। यह आदेश राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया गया, जिसमें कार्यवाहक चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की अगुवाई वाली खंडपीठ ने हस्तक्षेप किया। हालांकि, जिन सिपाहियों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, उनके ट्रांसफर पर फिलहाल रोक जारी रहेगी।

इस मामले में खंडपीठ ने हस्तक्षेप करते हुए आदेश में आंशिक संशोधन किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकताओं के तबादलों पर अंतरिम रोक तब तक बनी रहेगी जब तक अंतिम सुनवाई नहीं हो जाती, लेकिन अन्य सभी सिपाहियों के स्थानांतरण वैध रूप से लागू माने जाएंगे।

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में कहा गया कि 2022 तक एक ट्रांसफर पॉलिसी प्रभावी थी, लेकिन उसे रद्द कर दिया गया। अब नई नीति के बिना एक साथ इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफर

करना न केवल प्रशासनिक असंतुलन पैदा करता है, बल्कि यह सर्विस रूल्स और प्राकृतिक न्याय के भी खिलाफ है।

राज्य सरकार अब बाकी सिपाहियों का ट्रांसफर प्रभावी तरीके से लागू कर सकती है। वहीं, जिन सिपाहियों ने याचिका दायर की है, उनके मामले पर अंतिम सुनवाई के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। यह फैसला राज्य सरकार के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि लंबे समय से अटके ट्रांसफर आदेशों को लागू करने की राह अब साफ हो गई है। स्थानांतरण की सूची में पटना के अलावे नालंदा, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, भोजपुर, वैशाली, बक्सर और चंपारण समेत अन्य जिले भी शामिल हैं । आदेश में अंगरक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त ऐसे सिपाहियों का तबादला प्रतिनियक्ति अवधि तक स्थगित रहेगा। प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के बाद वे संबंधित जिले से कार्यमुक्त हो जाएंगे ।

गौरतलब है कि बीती 05 मई 2025 को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर राज्य भर के 19,858 सिपाहियों का तबादला एक जिले से दूसरे जिले में कर दिया था। इसे लेकर राज्य में काफी हलचल मच गई थी। इस फैसले को अमिताभ बच्चन समेत अन्य याचिकाकताओं ने पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकताओं की दलील थी कि बिहार में 2022 के बाद कोई नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू नहीं की गई, फिर भी इतने बड़े पैमाने पर स्थानांतरण कर दिए गए, जो नियमों के खिलाफ है। मामले की सुनवाई जस्टिस राजेश कुमार वर्मा की एकलपीठ ने की थी, जिन्होंने प्रारंभिक सुनवाई के बाद ट्रांसफर पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके बाद 22 मई को कोर्ट ने सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा और मामले की सुनवाई टाल दी गई थी।

नेपाल में पूर्णिया की तीन शातिर महिला गिरफ्तार, बुजुर्गो को बनाती थीं अपना निशाना

AGENCY ARARIA : सीमा पार नेपाल के विराटनगर में नेपाली पुलिस ने पूर्णिया की तीन शातिर महिलाओं को शुक्रवार को गिरफ्तार किया।

पुलिस ने इन महिलाओं के पास से नगद तीन लाख नेपाली रुपए बरामद किए। यह राशि नेपाल के कटहरी निवासी 70 वर्षीय नारायण प्रसाद काफ्ले के पास से चोरी की गई थी। नेपाल मोरंग जिला पुलिस कार्यालय के सूचना अधिकारी सह डीएसपी कोपिला चुड़ाल ने इस बात की पुष्टि की है। जिला पुलिस कार्यालय मोरंग के सूचना अधिकारी सह डीएसपी कोपिला चुड़ाल के अनुसार, विराटनगर के बाजार क्षेत्र में भाड़े के सवारी साधन में सवार असहाय और वृद्ध बुढ़ा और बूढ़ी के साथ नगद और जेवरात चोरी में गिरोह सक्रिय था।

पिछली कई घटना के सीसीटीवी फुटेज संकलन के आधार पर इन महिलाओं की नेपाल पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी।आखिरकार फिर से पूर्णिया से जोगबनी के रास्ते विराटनगर पहुंचने पर तीनों शातिर महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार की गई महिला की पहचान पूर्णिया निवासी 24 वर्षीय प्रियंका धामी, 25 वर्ष की बिहोला धामी और 20 वर्ष की अटकारी धामी के रूप में हुई है। इन लोगो के पास से एक हजार के तीन नोट के बंडल कुल तीन लाख रुपये भी बरामद होने की बात डीएसपी ने कही। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार की गई महिला के द्वारा कटहरी निवासी 70 वर्षीय नारायण प्रसाद काफ्ले के पास से आज रुपए चोरी करने की बात पुलिस ने कही। सिटी सफारी में यात्रा कर रहे नारायण प्रसाद काफ्ले के साथ में रहे झोला से गिरफ्तार महिलाओ ने नगद राशि निकाल ली थी। गिरफ्तार महिला को पुलिस रिमांड पर लेगी।

फारबिसगंज वार्ड संख्या 15 के पार्षद पद का उप-चुनाव आज, आमने-सामने की टक्कर

AGENCY ARARIA : फारबिसगंज नगर परिषद के वार्ड संख्या 15 के पार्षद के रिक्त पद पर शनिवार को वोट डाले जाएंगे। पार्षद पद के लिए हो रहे उप चुनाव के लिए आमने सामने की टक्कर है। पूर्व पार्षद चुन्नी खातून पति कुद्दूस अंसारी और नप के सशक्त स्थायी समिति सदस्य मो.इस्लाम की पत्नी नजराना खातून के बीच आमने सामने की टक्कर है। दरअसल वार्ड संख्या 15 के निर्वाचित प्रतिनिधि रौनक प्रवीण के बीपीएससी शिक्षक में चयन होने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।जिसके बाद यह पद रिक्त था।चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है।दोनों ही उम्मीदवारों के पक्ष में परोक्ष और अपरोक्ष रूप से बड़े बड़े सियासतदान फील्डिंग में लगे हैं।

चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज है। प्रत्याशी चुन्नी खातून वर्ष 2017 से 2022 तक वार्ड का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। वहीं नजराना खातून के पति मो. इस्लाम वार्ड संख्या 14 के वर्तमान पार्षद हैं और नगर परिषद के सशक्त स्थायी समिति के सदस्य भी हैं। दोनों ही प्रत्याशी और उनके समर्थक डोर-टू-डोर जनसंपर्क में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। वार्ड संख्या 15 में कुल 1285 मतदाता हैं, जिनमें 644 पुरुष और 641 महिलाएं शामिल हैं। मतदान वार्ड के बाल मध्य विद्यालय परिसर स्थित दो बूथों पर कराया जाएगा। प्रशासन ने मतदान की सारी तैयारियां पूरी कर लेने का दावा किया है। निवार्ची पदाधिकारी सह एसडीओ रंजीत कुमार रंजन ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

व्यावसायिक विमान सेवा शुरू करने की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन

BHAGALPUR : भागलपुर हवाई अड्डे से व्यावसायिक विमान सेवा शुरू करने की मांग को लेकर शुक्रवार को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कार्यकताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकताओं ने कहा कि साल 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी एयरपोर्ट से घोषणा की थी कि जल्द ही भागलपुर से विमान सेवा शुरू की जाएगी। लेकिन आज तक यह वादा अधूरा है। कांग्रेस कार्यकताओं ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि भागलपुर एयरपोर्ट सिर्फ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विशेष विमानों के लिए आरक्षित है। आम जनता को अब भी उड़ान की सुविधा नसीब नहीं हो सकी है। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी भी की गई भागलपुर स्मार्ट सिटी उड़ान भरने को तैयार है, कमी है तो सिर्फ प्लेन और रनवे की।

मोतिहारी में राज्य खाद्य निगम के लेखापाल के छह ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी

EAST CHAMPARAN : आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की टीम शुक्रवार की सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए मोतिहारी में राज्य खाद्य निगम के लेखपाल के पद पर पदस्थापित लेखपाल राजेश कुमार के मोतिहारी समेत छह ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। मिली जानकारी के अनुसार रोहतास में पोस्टिंग के दौरान ईओयनू आय से 201.94 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में राजेश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जिसके बाद कोर्ट से सर्च वारंट प्राप्त कर उक्त कारवाई की जा रही है। छापेमारी लेखपाल के पटना, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में स्थित कुल छह ठिकानों पर जारी है। जिसमें उनके आवास, पैतृक घर, रिश्तेदारों के ठिकाने शामिल है। बताया जा रहा

है कि छापेमारी के दौरान संदिग्ध लेन-देन से संबंधित कागजात और जमीन से जुडे दस्तावेज बरामद हुए हैं। ईओयू के अधिकारियों के अनुसार जांच में राजेश कुमार के द्वारा नगद लेन-देन, अचल संपत्ति में निवेश करने के प्रमाण मिले है।इसके साथ ही उन्होने कई फर्जी खातों के माध्यम से काले धन को वैध बनाने की भी कोशिश की है। इसके अलावा उनके कुछ करीबी रिश्तेदारों के नाम पर भी संपत्तियां मिली है,जिसकी जांच की जा रही है। संपत्ति का सटीक मूल्यांकन के बाद उनके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से 101 भूमि सुधार उप-समाहर्ता कार्यालयों की हुई समीक्षा

नंबर वन बना पूर्वी चंपारण का चकिया डीसीएलआर ऑफिस

AGENCY PATNA : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से राज्य के सभी 101 भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) कार्यालयों की समीक्षा कर मई माह की रैंकिंग शुक्रवार को जारी कर दी गई है। जारी की गई रैंकिंग के मुताबिक पूर्वी चंपारण का चकिया भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय पहले, शेखपुरा का शेखपुरा भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय दूसरे और मुंगेर का तारापुर भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय तीसरे स्थान पर बरकरार है। सुपौल का निर्मली भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय पांचवें से चौथे, अरवल भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय 58वें नंबर से लंबी छलांग लगाते हुए पांचवें नंबर

टॉप 10 भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय

1. चकिया (पूर्वी चंपारण) : 81.97 अंक
2. शेखपुरा (शेखपुरा) : 79.77 अंक
3. तारापुर (मुंगेर) : 78.72 अंक
4. निर्मली (सुपौल) : 77.82 अंक
5. अरवल (अरवल) : 76.52 अंक
6. बिरौल (दरभंगा) : 76.16 अंक
7. हिलसा (नालंदा) : 74.79 अंक
8. पालीगंज (पटना) : 74.71 अंक
9. बेलसंड (सीतामढ़ी) : 74.27 अंक
10. बेगूसराय (बेगूसराय) : 72.87 अंक

रैंकिंग में फिसड्डी 10 भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय

1. आरा सदर (भोजपुर) : 55.27 अंक
2. फारबिसगंज (अररिया) : 55.22 अंक
3. मुजफ्फरपुर पूर्वी (मुजफ्फरपुर) : 53.60 अंक
4. बेतिया (प. चंपारण) : 53.43 अंक
5. दानापुर (पटना) : 53.11 अंक
6. सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा) : 51.39 अंक
7. फुलपरास (मधुबनी) : 51.22 अंक
8. जयनगर (मधुबनी) : 50.82 अंक
9. भागलपुर सदर (भागलपुर) : 49.95 अंक
10. नवगछिया (भागलपुर)- 37.16 अंक

पर आ गया है। दरभंगा का बिरौल डीसीएलआर कार्यालय 12वें से छठे और नालंदा का हिलसा सातवें स्थान पर बरकरार है। इसके साथ ही पटना का पालीगंज नौवें से आठवें, सीतामढ़ी का बेलसंड छठे से खिसककर नौवें तो बेगूसराय दसवें स्थान पर बरकरार है। पूर्वी चंपारण का पकड़ीदयाल 23वें स्थान से लंबी छलांग लगाते हुए 11वें स्थान पर आ गया है। बेगूसराय का तेघड़ा 17वें से 12वें, नालंदा का बिहारशरीफ 26वें से 13वें, जहानाबाद 16वें से 14वें और औरंगाबाद लंबी छलांग लगाते हुए 88वें से 15वें स्थान पर आ गया है।

बायसी में दो परिजनों को मिला चार-चार लाख का अनुग्रह अनुदान

PURNIA : जिलाधिकारी अंशुल कुमार के निर्देश पर आपदा पीड़ितों को शीघ्र सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसी क्रम में आज बायसी अंचलाधिकारी द्वारा दो आपदा प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान राशि के रूप में सहायता प्रदान की गई। पहला मामला ककहरवा, खपड़ा के निवासी स्वर्गीय अनायत पिता मो. सब्बीर का है, जिनकी डूबने से मृत्यु हो गई थी। उनके निकटतम आश्रित सब्बीर अहमद (पिता - मो. सगीर) को 4 लाख की अनुग्रह राशि का चेक सौंपा गया। दूसरे मामले में चौक पानी सदरा, बायसी नगर पंचायत निवासी स्वर्गीय रजीब (पिता - स्व. कमरुल) की भी पानी में डूबने से मौत हो गई थी।

सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन परिसर को आरपीएफ ने कराया अतिक्रमण मुक्त

AGENCY SAHARSA : समस्तीपुर मंडल अंतर्गत सहरसा मानसी रेलखंड पर अवस्थित सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन परिसर का आरपीएफ द्वारा शुक्रवार को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।

सहरसा आरपीएफ पोस्ट कमांडर रेलवे सुरक्षा बल धनंजय कुमार के निदेर्शानुसार सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन अंतर्गत लगे हुए दुकानों को हटाया गया और रेल परिसर को अतिक्रमण मुक्त किया गया।

अमृत भारत स्टेशन के तहत सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन का नव निर्माण कराया जा रहा है।साथ ही साथ रेल परिसर का भी साज सज्जा के साथ पूर्ण रूप से विकसित किया जा रहा है। लेकिन स्टेशन परिसर में अवैध अतिक्रमणकारियों द्वारा दुकान

लगाकर अतिक्रमण किये जाने से रेलयात्रियों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पडता था। आरपीएफ द्वारा सभी अतिक्रमण कारियों को नोटिस निर्गत कर खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया ।लेकिन अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण नही हटाये जाने के कारण रेल सुरक्षा बल के द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया गया। वही अतिक्रमण मुक्त होने के फलस्वरूप स्टेशन परिसर की साफ-सफाई एवं रेलयात्रियों को आवागमन में काफी सहूलियत होगी।

टमाटर की उन्नत कृषि कार्यमाला

टमाटर अत्यंत ही लोकप्रिय तथा पोषक तत्वों से युक्त फलदार सब्जी है। जिसका उपयोग साल भर किया जाता है। सब्जी के अलावा उससे सूप, चटनी, सलाद, आदि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। विटामिन व अन्य खाद्य पदार्थ उपयुक्त मात्रा में पाये जाते हैं।

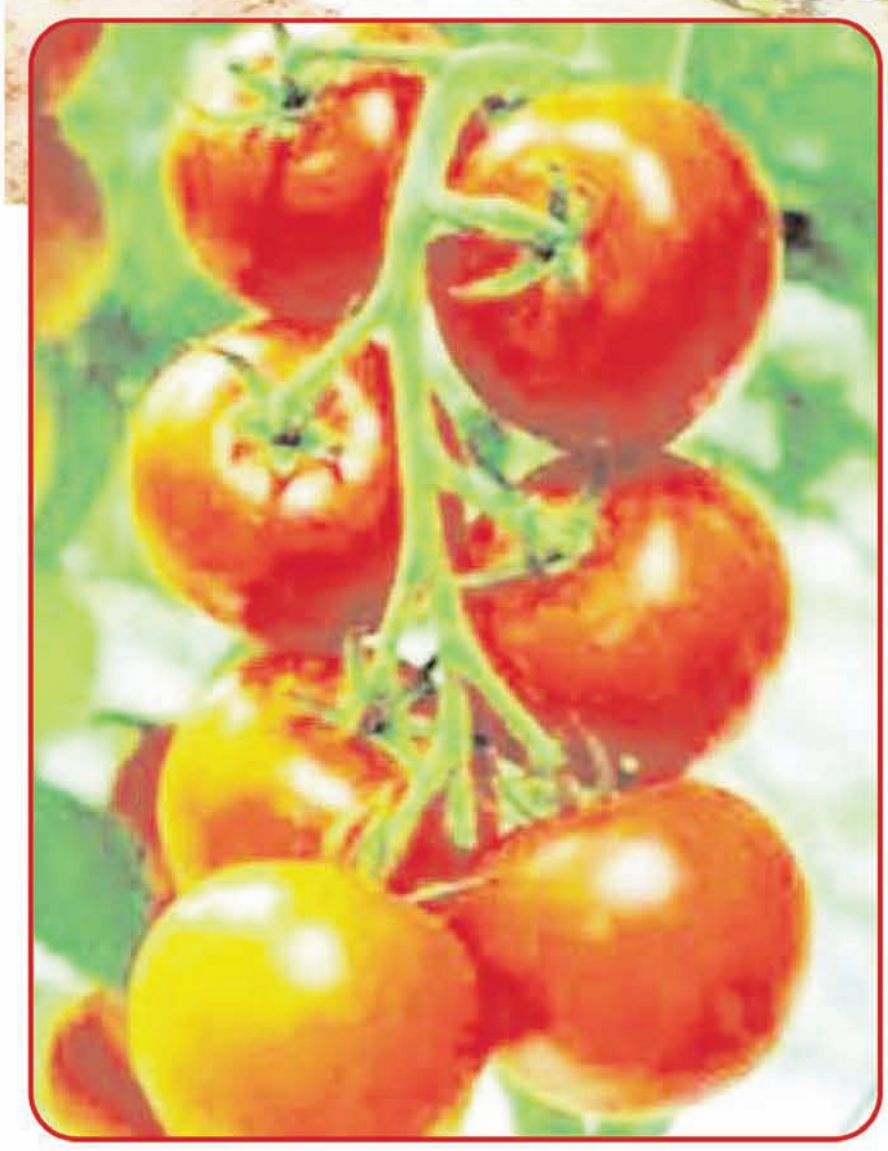

⊙**भूमि**- टमाटर की खेती कई किस्मों की मिट्टी में की जाती है लेकिन अच्छी जल निकासी चिकनी मृदा तथा दोमट मिट्टी सर्वोत्तम है।

⊙**खेत की तैयारी** :- प्रथम जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद 2-3 बार कल्टीवेटर या हैरो चलाना चाहिए ताकि भूमि की निचली कठोर परत टूट जाए। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा चलाना चाहिए ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए।

⊙**उन्नतशील किस्में** :- पूसा रूबी, पन्त टी-1 पंजाब छुआरा, अर्का विकास, पूसा अर्ली ड्वार्फ आदि।

⊙**बीज दर**:- देशी - 400-500 ग्राम/ हेक्टेयर

⊙संकर - 100 ग्राम / हेक्टेयर

⊙**पौध तैयार करना (नर्सरी)**:- वर्षा ऋतु में 10 सें.मी. ऊंची क्यारी तैयार कर उसमें बीज बोना चाहिए। बीज कतारों में बोना चाहिए।

⊙**बीजोपचार** :- बीज को बोने से पूर्व थायरम या बाविस्टिन से 2 ग्राम/ किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए।

⊙**बुआई का समय** :- खरीफ- जून-जुलाई, शीत -अक्टूबर- नवम्बर

⊙**रोपण** :- क्यारियों में जब पौधे 4 से 5 सप्ताह के हो जाएं या 7 से 10 सें.मी. के हो जाएं तब खेत में रोपित करना चाहिए। पौध रोपण के पश्चात् तुरन्त हल्की सिंचाई करनी चाहिए। एक स्थान पर एक ही पौधा लगाएं।

⊙**पौध अन्तरण**:- कतार से कतार की दूरी 75 सें.मी. एवं पौध से पौध की दूरी 60 सें.मी. रखना चाहिए।

⊙**उर्वरक की मात्रा** :- गोबर खाद 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर भूमि की तैयारी के समय मिलाना चाहिए। यूरिया 217 किलो प्रति हेक्टेयर, तीन भागों में देना चाहिए। पहला भाग, पौध रोपण के समय तथा दूसरा भाग एवं तीसरा भाग 30 दिन के अन्तर से देना चाहिए। एस.एस.पी. 500 किलो/ हेक्टेयर व पोटाश 100 किलो प्रति हेक्टेयर पौध रोपण के समय देना चाहिए।

⊙**सिंचाई** :- टमाटर में अधिक तथा कम सिंचाई दोनों ही हानिकारक हैं। शरद ऋतु में 10 से 12 दिन के अन्तर तथा गर्मी में 4-5 दिन के अन्तर में भूमि के अनुसार सिंचाई की जा सकती है।

⊙**निंदाई गुड़ाई** :- टमाटर की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए निरंतर निंदाई-गुड़ाई करते रहना आवश्यक है। गुड़ाई उथली करनी चाहिए जिससे जड़ों को नुकसान न पहुंचे। 30-40 दिन बाद पौधों पर मिट्टी चढ़ा देना चाहिए।

⊙**वृद्धि नियामकों का प्रयोग** :- वृद्धि नियामकों का प्रयोग फूलों को झड़ने से रोकने तथा बिना निषेचन के फलों को विकास के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है। पी. सी.पी.ए. 50-100 पी. पी. एम. (50-100 मि.ग्रा./ लीटर पानी में घोलना है) के घोल का छिड़काव लाभकारी होता है।

⊙**सहारा देना** :- ऊंचाई व मध्यम ऊंचाई वाली किस्मों को पेड़ की टहनियां (बांस) की सहायता से सहारा देना चाहिए, ऐसा करने से पौधे की वृद्धि अच्छी होती है, वर्षा ऋतु में फल तथा पेड़ सड़ते नहीं हैं। फलों का आकार बढ़ जाता है तथा पैदावार भी अधिक होती है।

⊙**फलों की तुड़ाई** :- टमाटर के फसल की तुड़ाई कई अवस्थाओं में की जाती है-

⊙ **कच्चे या हरे फल** :- टमाटर को अधपके हरे से गुलाबी पड़ने पर तब तोड़ा जाता है जब इसे दूर स्थित बाजारों में विपणन हेतु भेजना होता है।

⊙ **गुलाबी या हल्के लाल फल**:- टमाटर को गुलाबी या हल्के लाल होने की अवस्था में तब तोड़ा जाता है जब इसे स्थानीय बाजारों में भेजना होता है।

⊙ **पके हुए टमाटर** :- फलों का अधिकतम भाग लाल होता है व नरम होता है ऐसे फल घरेलू उपयोग या कच्चे सलाद खाने के काम आते हैं।

⊙**अधिक पके टमाटर** :- बीज उत्पादन के लिए लाल फल आदर्श माने जाते हैं। फल परीरक्षण के लिए भी अधिक पके टमाटर अच्छे माने जाते हैं।

गोभीवर्गीय में पोषक तत्वों की आवश्यकता

⊙**भूरापन या ब्राउनिंग** - यह समस्या गोभीवर्गीय फसलों में बोरान की कमी से होता है।

⊙**लक्षण** - भूरापन में शुरूआत में फूल में जल अवशोषित धब्बे पड़ जाते हैं, जो कि बाद में बड़े हो जाते हैं। इसके बाद तने में भी जल अवशोषित धब्बे पड़ते हैं तथा तना अंदर से खोखला हो जाता है। यदि भूरापन का प्रकोप ज्यादा होता है तो पूरा फूल में कुछ दिन बाद गुलाबी या भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं।

⊙**उपचार** - बोरान की कमी को दूर करने के लिये 10-15 किलो बोरेक्स प्रति हेक्टर भूमि में पौध रोपण के समय देना चाहिए अथवा जब फसल खड़ी हो 0.1 प्रतिशत बोरेक्स घोल का छिड़काव करना चाहिए प्रथम छिड़काव पौध रोपण के दो सप्ताह पश्चात और दूसरा छिड़काव फूल बनने से दो सप्ताह पहले करना चाहिए।

⊙**व्हिपटेल** - यह लक्षण गोभीवर्गीय फसलों में मालीब्डिनम नामक तत्व की कमी के कारण होता है।

⊙**लक्षण** - मुख्यत: मालीब्डिनम की कमी अम्लीय भूमि में हो जाती है अर्थात् मालीब्डिनम अनुपलब्ध रूप से हो जाता है, जिससे पौधे इस तत्व का अवशोषण नहीं कर पाते और व्हिपटेल के लक्षण दिखाई देते है, इसमें शुरूआत में पौधे की वृद्धि रुक जाती है और पत्तियाँ सिकुड़ कर सफेद पड़ने लगती हैं तथा कुछ दिन बाद पत्तियां अपना आकार खो देती हैं और मिडरिब के अलावा शेष भाग सूख जाता है, जिसके कारण इसे सामान्यत: व्हिपटेल कहा जाता है।

⊙**उपचार** - मालीब्डिनम की कमी को दूर करने के लिए अम्लीयता कम करने के उद्देश्य से

50-70 क्विंटल बुझा चूना प्रति हेक्टर खेत की तैयारी के समय भूमि में मिला देना चाहिए। इसके साथ ही पौध रोपण के पहले 2.5 से 5 किलो सोडियम मालीब्डेट प्रति हेक्टर भूमि में मिला देना चाहिए अथवा खड़ी फसल में 0.05ज् सोडियम मालीब्डिेट घोल का पौधों पर छिड़काव करना चाहिए।

⊙**बटनिंग** - बटनिंग की समस्या गोभी वर्गीय फसलों के कई कारणों से होती है जैसे अधिक उम्र के रोप के कारण, नाइट्रोजन की कमी के कारण या समय के अनुसार उचित किस्मों को ना लगाने से ऐसा होता है।

⊙**लक्षण** - फूलों का विकसित ना होकर छोटा रह जाना बटनिंग कहलाता है। इसमें फूलों का आकार छोटा हो जाता है तथा कम विकसित पत्तियाँ होती हैं।

⊙**उपचार** - बटनिंग को रोकने के लिये अगेती या पिछेती किस्में अनुशंसित समय पर ही लगाएं, पौधे की वृद्धि चाहे वह नर्सरी में हो या खेत में नहीं रूकनी चाहिए। अधिक सिंचाई न करें। जो पौधा नर्सरी में अधिक दिन के हो उन्हें खेत में न लगाएं और नाइट्रोजन की उचित मात्रा पौधों को समय-समय पर दें।

⊙**रेसीयनेस** - रेसीयनेस के लक्षण मुख्यत: वातावरण में अनुकूल तापमान की कमी, अधिक नाइट्रोजन देने के कारण तथा अधिक आर्द्रता के कारण होती हैं।

⊙**लक्षण** - समय से पूर्व अविकसित कली को रेसीयनेस कहते हैं। इसमें फूल की ऊपरी सतह ढीली पड़ जाती है तथा सफेद छोटी कलिका बन जाती है।

⊙**उपचार** - रेसीयनेस से उपचार के लिये उचित किस्म का चयन करें, समय पर पौधों की रोपाई करें, नाइट्रोजन की उचित मात्रा का प्रयोग करें तथा प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें।

⊙**अन्धता** - अन्धता गोभीवर्गीय फसलों से पौधे की वृद्धि के शुरूआत मुख्य कलिका में कीट के प्रकोप के कारण तथा वातावरण में तापमान में कमी होने वाला पाला पड़ने के कारण होता है।

⊙**लक्षण** - अन्धता में पौधे की मुख्य कलिका कीट के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है तथा इसके पत्ते बड़े, चमड़े जैसे मोटे और गहरे रंग के हो जाते हैं।

⊙**उपचार** - अन्धता की रोकथाम के लिए मुख्य कलिका को कीटों से क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिये कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए, उचित किस्म का चयन करना चाहिए।

घरेलू उत्पाद में वृद्धि के नए संकेत

जापान की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और संभवत आगामी लगभग दो वर्षों के अंदर जर्मनी की अर्थव्यवस्था से आगे निकलकर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की अपनी-अपनी विशेषताएं हैं, जिनके आधार पर यह अर्थव्यवस्थाएं विश्व में उच्च स्थान पर पहुंची हैं एवं इस स्थान पर बनी हुई हैं। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के मामले में आज भी कई विकसित देश भारत से आगे हैं। इन समस्त देशों के बीच चूंकि भारत की आबादी सबसे अधिक अर्थात 140 करोड़ नागरिकों से अधिक है, इसलिए भारत में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद बहुत कम है। अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद का आकार 30.51 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर है और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 89,110 अमेरिकी डॉलर हैं। इसी प्रकार, चीन के सकल घरेलू उत्पाद का आकार 19.23 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर है और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 13,690 अमेरिकी डॉलर है और जर्मनी के सकल घरेलू उत्पाद का आकार 4.74 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर है और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 55,910 अमेरिकी डॉलर है। यह तीनों देश सकल घरेलू उत्पाद के आकार के मामले में आज भारत से आगे हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद का आकार 4.19 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर है तथा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद केवल 2,880 अमेरिकी डॉलर है। भारत के पीछे आने वाले देशों में हालांकि सकल घरेलू उत्पाद का आकार कम जरूर है, परंतु प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के मामले में यह देश भारत से बहुत आगे हैं। जैसे जापान के सकल घरेलू उत्पाद का आकार 4.18 लाख करोड़ है और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 33,960 अमेरिकी डॉलर है। ब्रिटेन के सकल घरेलू उत्पाद का आकार 3.84 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 54,950 अमेरिकी डॉलर है। फ्रांस के सकल घरेलू उत्पाद का आकार 3.21 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर है और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 46,390 अमेरिकी डॉलर है। इटली के सकल घरेलू उत्पाद का आकार 2.42 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर है और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 41,090 अमेरिकी डॉलर है। कनाडा के सकल घरेलू उत्पाद का आकार 2.23 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर है और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 53,560 अमेरिकी डॉलर है। ब्राजील के सकल घरेलू उत्पाद का आकार 2.13 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 9,960 अमेरिकी डॉलर है। सकल घरेलू उत्पाद के आकार के मामले में विश्व की सबसे बड़ी 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत शामिल होकर चौथे स्थान पहुंच जरूर गया है, परंतु प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के मामले में भारत इन सभी अर्थव्यवस्थाओं से अभी भी बहुत पीछे है। इस सबके पीछे सबसे बड़े कारणों में शामिल है भारत द्वारा वर्ष 1947 में राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात, आर्थिक विकास की दौड़ में बहुत अधिक देर के बाद शामिल होना। भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों की शुरूआत वर्ष 1991 में प्रारंभ जरूर हुई, परंतु इसमें इस क्षेत्र में तेजी से कार्य वर्ष 2014 के बाद ही प्रारंभ हो सका है। इसके बाद, पिछले 11 वर्षों में परिणाम हमारे सामने हैं और भारत विश्व की 11वीं अर्थव्यवस्था से छलांग लगते हुए आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। दूसरे, इन देशों की तुलना में भारत की जनसंख्या का बहुत अधिक होना, जिसके चलते सकल घरेलू उत्पाद का आकार तो लगातार बढ़ रहा है, परंतु प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद अभी भी अत्यधिक दबाव में है। अमेरिका में तो आर्थिक क्षेत्र में सुधार कार्यक्रम 1940 में ही प्रारंभ हो गए थे एवं चीन में वर्ष 1960 से प्रारंभ हुए। अतः भारत इस मामले में विश्व के विकसित देशों से बहुत अधिक पिछड़ गया है। परंतु, अब भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों की संख्या में तेजी से कमी हो रही है तथा साथ ही अति धनाढ्य एवं मध्यमवर्गीय परिवारों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिससे अब उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे आने वाले समय में भारत में भी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में तेज गति से वृद्धि होगी। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका में सेवा क्षेत्र इसकी सबसे बढ़ी ताकत है। अमेरिका में केवल दो प्रतिशत आबादी ही कृषि क्षेत्र पर निर्भर है और अमेरिका की अधिकतम आबादी उच्च तकनीकी का उपयोग करती है, जिसके कारण अमेरिका में उत्पादकता अपने उच्चत्तम स्तर पर है। पेट्रोलियम पदार्थों एवं रक्षा उत्पादों के निर्यात के मामले में अमेरिका आज पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2024 में अमेरिका ने 2.08 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर मूल्य के बराबर का सामान अन्य देशों को निर्यात किया है, जो चीन के बाद विश्व के दूसरे स्थान पर है। तकनीकी वर्चस्व, बौद्धिक संपदा एवं प्रौद्योगिकी नवाचार ने अमेरिका को विकास के मामले में बहुत आगे पहुंचा दिया है। टेक्निकल नवाचार से जुड़ी विश्व की पांच शीर्ष कंपनियों में से चार, यथा एप्पल, एनवीडिया, माक्रोसोफ्ट एवं अल्फाबेट, अमेरिका की कंपनियां हैं। इन कंपनियों का संयुक्त बाजार मूल्य 12 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से भी अधिक है, जो विश्व के कई देशों के सकल घरेलू उत्पाद से बहुत अधिक है। अतः अमेरिका के नागरिकों ने बहुत तेजी से धन सम्पदा का संग्रहण किया है। इसी के चलते प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद अमेरिका में बहुत अधिक है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद वर्ष 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्ज नामक स्थान पर हुई एतिहासिक बैठक में विश्व के 44 देशों ने वैश्विक वित्तीय व्यवस्था के नए ढांचे पर सहमति जताते हुए अपने देश की मुद्रा को अमेरिकी डॉलर से जोड़ दिया था। इसके बाद से वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिकी डॉलर का दबदबा बना हुआ है। आज विश्व का लगभग 80 प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग लेन देन अमेरिकी डॉलर में होता है। अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन को पूरे विश्व का विनिर्माण केंद्र कहा जाता है क्योंकि आज पूरे विश्व के औद्योगिक उत्पादन का 31 प्रतिशत हिस्सा चीन में निर्मित होता है।

प्रधानमंत्री मोदी का हर अभियान बना जन आंदोलन

ANALYSIS

डॉ. राजेश मिश्र

मोदी सरकार ने 11 साल के कार्यकाल में कई उल्लेखनीय और अभूतपूर्व कार्य कर भारत को कई क्षेत्रो मे नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। शौचालय, पीएम आवास निर्माण के बाद बड़ी उपलब्धियों मे यदि किसी को गिना जाएगा तो वह है आयुष्मान भारत योजना, जिसने 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। इस योजना ने 6 करोड़ से अधिक लोगो का इलाज कराकर उन्हे वित्तीय संकट से बचाया। देखा जाए तो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए इलाज पर होने वाला खर्च कमर तोड़ने वाला होता है। गंभीर बीमारी के समय तो कई ऐसे परिवार रहे जो खर्च न उठा पाने की स्थिति में मरीज को अपने हाल पर छोड़ देते थे। आयुष्मान भारत योजना ने अब सब कुछ आसान कर दिया है। सामान्य हो या असामान्य सभी तरह की बीमारियों की चिंता आयुष्मान भारत पर छोड़ी जा चुकी है। आयुष्मान भारत योजना के बाद डिजिटल इंडिया का कदम क्रांतिकारी रहा है। डिजिटल इंडिया ने यूपीआई के माध्यम से भारत को वैश्विक डिजिटल भुगतान का नेतृत्वकर्ता बनाया, जिससे 2025 तक 1.3 ट्रिलियन मासिक लेन-देन दर्ज किए गए। मेक इन इंडिया विनिर्माण और निवेश को बढ़ावा दिया, जिससे भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था बना।

अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब गांधी जयंती पर स्वच्छता अभियान की शुरूआत की तो किसी को अंदाजा न रहा होगा कि यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले लेगा। स्वच्छता आंदोलन के साथ देखते ही देखते जिस तरह राजनेता, अभिनेता, अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी व आमजन जुड़ गए, वह अपने आप मे अद्वितीय ही रहा। अभियान पूरे देश में व्यापक असर तो दिखा ही साथ ही लोगों के दिलों-दिमाग में स्वच्छता के प्रति जागरुकता के प्रति अमिट छाप छोड़ गया। आज भी लोग सार्वजनिक व निजी स्थलों मे कचरा फेंकने, गंदगी करने के पहले सौ बार सोचते है। कोविड के समय स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और जन सहयोग को मिसाल के रूप मे देश ने देखा है। सरकारी मदद इलाज के इतर जिस तरह से एक दूसरे की मदद के लिए लोग सामने आए और लाखों लोगों की जान सुरक्षित किए, वह प्रधानमंत्री के आह्वान का ही नतीजा रहा है। मोदी सरकार ने 11 साल के कार्यकाल में कई उल्लेखनीय और अभूतपूर्व कार्य कर भारत को कई क्षेत्रो मे नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। शौचालय, पीएम आवास निर्माण के बाद बड़ी उपलब्धियों मे यदि किसी को गिना जाएगा तो वह है आयुष्मान भारत योजना, जिसने 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। इस योजना ने 6 करोड़ से अधिक लोगो का इलाज कराकर उन्हे वित्तीय संकट से बचाया। देखा जाए तो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए इलाज पर होने वाला खर्च कमर तोड़ने वाला होता है। गंभीर बीमारी के समय तो कई ऐसे परिवार रहे जो खर्च न उठा पाने की स्थिति में मरीज को अपने हाल पर छोड़ देते थे। आयुष्मान भारत योजना ने अब सब कुछ आसान कर दिया है। सामान्य हो या असामान्य सभी तरह की बीमारियों की चिंता आयुष्मान भारत पर छोड़ी जा चुकी है। आयुष्मान भारत योजना के बाद डिजिटल इंडिया का कदम क्रांतिकारी रहा है। डिजिटल इंडिया ने यूपीआई के माध्यम से भारत को वैश्विक डिजिटल भुगतान का नेतृत्वकर्ता बनाया, जिससे 2025 तक 1.3 ट्रिलियन मासिक लेन-देन दर्ज किए गए।

मेक इन इंडिया विनिर्माण और निवेश को बढ़ावा दिया, जिससे भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था बना। जल जीवन मिशन ने 11.82 करोड़ ग्रामीण घरो को नल जल कनेक्शन प्रदान किया, जिससे स्वच्छ पेयजल की पहुंच बढ़ी। मोदी सरकार ने अपने ग्यारह वर्ष के कार्यकाल मे ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लिए हैं। अनुच्छेद 370 का हटाया जाना ऐसा निर्णय रहा जिसे देश मान चुका था की यह संभव नही है। यह नहीं हो सकता की धारणा आम हो चुकी थी लोकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व मे यह धारणा टूट गई। अनुच्छेद 370 समाप्त हो गया और किसी तरह की चूं-चपड़ भी नही हुई। विपक्ष की यह आशंका भी निर्मूल साबित हुई कि देश में भू-चाल आ जाएगा। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद देश ने भी देखा की जब जम्मू-कश्मीर में लोकसभा चुनाव हुए तो 58.46 फीसद तक मतदान हुआ। यह परिवर्तन एक साहसिक निर्णय का असर रहा है। इसी तरह तीन तलाक की प्रथा जो मानवता के लिए त्रासदी थी, जिस पर वर्षों तक चुप्पी छाई रही। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही, लेकिन कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया गया। मोदी सरकार ने तीन तलाक को समाप्त कर यह साबित कर दिया कि वह महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है। यह निर्णय तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जब पता चलता है कि इस्लामिक देशों में तो तीन तलाक बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। प्रधानमंत्री ने गरीबों के कल्याण की सार्थक योजना चलाई, जिसका असर देखने को मिला है। गरीबी हटाओ केवल पुराने नारे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गरीबों के कल्याण को साकार रूप दिया गया। आंकड़े बताते हैं की 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ चुके हैं। नीति आयोग और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंचों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े भी इसके गवाह हैं। भारत मे अत्यधिक गरीबी में 80 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड लोगो को प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं व चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया गया, जिसे बडी उपलब्धि के रूप में माना जा सकता है। पीएम आवास योजना ने भी गरीबों की ना केवल दशा बदली, बल्कि खुशहाली की राह दिखाई है। पीएम आवास योजना के 4 करोड़ पक्के मकान बनाए जा चुके हैं और अगले पांच वर्षों में 3 करोड और मकानों के निर्माण का संकल्प लिया गया है। यदि आज आप गांवों की यात्रा करें तो पहले जहां खपरैल व घासफूस के घर दिखते थे, अब वहां पक्के मकान खड़े हैं। सड़क नेटवर्क क्षेत्र में पहले जो सड़कें अधूरी व टूटी-फूटी रहती थीं, वह अब हाईवे मे बदल चुकी हैं। यह आज के आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर का परिचायक है। पुलवामा व हाल में हुए पहलगाम आतंकी हमले से सभी वाकिफ हैं। आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री ने हवा-हवाई बातें नहीं की, बल्कि जो कहा, वह करके दिखाया है। देश ने देखा कि किस तरह सेना ने घुस कर मारा। यह तभी संभव होता, जब नेतृत्व मजबूत हाथो में हो और कुछ कर दिखाने का जज्बा हो। मोदी सरकार ने देश की आंतरिक और वाह्य सुरक्षा पर फोकस करते हुए नक्सलवाद व आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम किया है। पहले देश में 126 जिले नक्सल प्रभावित माने जाते थे, जो अब घटकर 18 रह गए हैं। हिंसा मे 53 फीसद की कमी आई है। सुरक्षाबलों की हताहत संख्या में 72 फीसद गिरावट दर्ज की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत अब नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ रहा है। संसदीय क्षेत्र सीधी के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्यारह वर्ष के कार्यकाल मे संसदीय क्षेत्र सीधी में एतिहासिक कार्य हुए हैं। ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना की आधारशिला 1985 मे रखी गई। बाद में परियोजना को ठंडे बस्ते मे डाल दिया गया। केंद्र में कांग्रेस की सरकार होने और स्थानीय स्तर पर मजबूत व पहुंचवाले नेताओं के होने के बावजूद परियोजना को गतिमान बनाने के लिए एक धेला भी नहीं दिया गया। रेल परियोजना को गति देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद हुआ है। ग्यारह वर्ष के प्रयास का नतीजा रहा कि रीवा से सीधी और सिंगरौली तक रेललाइन बिछाने का काम तेज है। जगह-जगह स्टेशन, पुल आदि का कार्य तेजी से हो रहा है। जिला मुख्यालय में भी शीघ्र बहुप्रतीक्षित रेल पहुंचने वाली है। पिछले 40 वर्ष से ठप पड़ी रेल परियोजना को जहां मोदी सरकार ने सजीव कर दिखाया, वहीं सीधी-रीवा मार्ग पर कैमोर पहाड़ में विश्वस्तरीय सुरंग का निर्माण कराकर समूचे विंध्य को बड़ी सौगात दी है। सुरंग बन जाने से सीधी और रीवा के बीच आवागमन सुगम व रोमांचित हो गया है। संसदीय क्षेत्र मे इसके अलावा बेहतरीन नेशनल हाईवे निमार्णाधीन हैं। गांव-देहात भी सड़क, पेयजल, बिजली की सुविधा से युक्त हो गए हैं। सीधी-सिंगरौली में मेडिकल कालेज की स्थापना, इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक संस्थानों की स्थापना ने शिक्षा के क्षेत्र को मजबूती प्रदान की है। साथ ही सिंचाई परियोजना की शुरूआत आदि ने किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने का काम किया है।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का अलग राग

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार की उस योजना को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें सिंधु प्रणाली की पश्चिमी नदियों के अतिरिक्त जल को जम्मू-कश्मीर से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान भेजने के लिए नहर बनाने की बात की गई थी। वर्तमान संदर्भों में उमर का कहना है कि यह पानी अभी सिर्फ जम्मू-कश्मीर के लिए है, क्योंकि जब हमें जरूरत थी, तब किसी ने हमारी मदद नहीं की थी। पठानकोट स्थित शाहपुर कंडी बैराज के लंबे विवाद का हवाला देते हुए उमर ने पंजाब को याद दिलाया कि 45 वर्षों तक इस मुद्दे पर जम्मू-कश्मीर को नुकसान उठाना पड़ा। कई सालों तक उन्होंने हमें रुलाया, अब जब हमारे पास थोड़ा अतिरिक्त पानी है, तो हम क्यों दें। इस वक्तव्य के साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि 113 किमी लंबी प्रस्तावित नहर को फिलहाल उनकी सरकार मंजूरी नहीं देगी। कहना होगा कि इस एक निर्णय से साफ दिखाई दे रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भारत के लोगों की नहीं, जम्मू-कश्मीर का बहाना लेकर पाकिस्तान की फिक्र ज्यादा है। वस्तुतः यहां पाकिस्तान को लेकर उनकी चिंताएं इतनी अधिक समझ आ रही हैं कि वे जम्मू-कश्मीर की नदियों में बहते पानी का उपयोग देश के अन्य राज्यों में होने नहीं देना चाहते, जबकि केंद्र की मोदी सरकार यह साफ कर चुकी है कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के प्रभावी निलंबन के बाद वह इस अतिरिक्त जल का उपयोग उत्तर भारत के राज्यों में करना चाहती है। दूसरी ओर उमर अब्दुल्ला की नीयत जो स्पष्ट कर रही है, वह यही है कि जब अन्य राज्यों को पानी देने के लिए प्रस्तावित नहर बनेगी ही नहीं, तब आखिर भारत जल के तेज बहाव को अपने यहां कब तक रोककर रख पाएगा, ऐसी परिर्स्थितयों में आखिरकार उसे पानी को बहाना ही होगा और ऐसे में उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प रहेगा कि उस जल को वह पाकिस्तान की तरफ बहा दे। स्वभाविक है कि जिस उद्देश्य से भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और सिंधु जल संधि को रोका वह विफल हो जाएगा। पाकिस्तान में भारत के विरोध में एक ओर आतंकवादी पनपते रहेंगे तो दूसरी ओर उन्हें जैसे पहले पानी मिलता था वैसे भी आगे भारत की ओर से पानी मिलता रहेगा। अब यहां केंद्र सरकार की इस संदर्भ में बनाई गई योजना को समझने की बात है। सिंधु नदी के पानी का पूरा इस्तेमाल करने के लिए भारत ने अपनी अंतर-बेसिन जल हस्तांतरण योजना की दिशा में बड़ा काम करना शुरू कर दिया है। 113 किलोमीटर लंबी नहर बनाने की तैयारी चल रही है। इसमें जम्मू-कश्मीर की नदियों को आपस में जोड़ने का काम होगा और इस राज्य के साथ ही पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पानी ले जाने के लिए यह नहर चिनाब नदी को रावी-ब्यास-सतलुज नदी प्रणाली से जोड़ेगी। इससे पूर्वी (रावी, ब्यास, सतलुज) और पश्चिमी (सिंधु, झेलम, चिनाब) नदियों के पानी का सही उपयोग हो सकेगा और पाकिस्तान में बहने वाले अतिरिक्त पानी को रोका जा सकेगा। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं सिंधु जल समझौते को लेकर अपने वक्तव्य पिछले दिनों देते दिखे, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि आखिर भारत के पानी का उपयोग भारत ही नहीं कर पा रहा, यह अब आगे नहीं चलने वाला। पाकिस्तान के साथ खून और पानी एक साथ नहीं बहाया जा सकता है। स्वभाविक है कि प्रधानमंत्री ने जो मंशा व्यक्त की, उसी अनुरूप केंद्र के अधिकारियों ने योजना बनाना शुरू किया और अब उस पर कार्य किया जाना है। प्रधानमंत्री मोदी की तरह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बड़ी योजना पर बोला है और बताया भी कि सिंधु का पानी तीन साल के भीतर नहरों के माध्यम से राजस्थान के श्रीगंगानगर तक पहुंचाया जाएगा। प्रस्तावित नहर नेटवर्क जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 13 मौजूदा नहरों से जुड़ेगा और आखिरकार यह इंदिरा गांधी नहर प्रणाली में मिल जाएगा। देखा जाए तो कितनी अच्छी और सफल योजना है यह। इस नहर योजना को लेकर आज कई पर्यावरणविज्ञ एवं जल विशेषज्ञ भी अपनी राय रख रहे हैं और सभी ने यह समान रूप से स्वीकार्य किया है कि कश्मीर से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अतिरिक्त पानी भेजने से इलाके में जल की उपलब्धता को संतुलित करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही आंतरिक स्तर पर पानी के वितरण में इस बदलाव से जलवायु परिवर्तन और बदलते वर्षा पैटर्न का सामना करना भारत के लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। जिस क्षेत्र में अभी सूखा है वहां तो इस प्रोजेक्ट से हरियाली आएगी ही, साथ में रोजगार के कई नए अवसर इस पूरे क्षेत्र में जहां से ये नहर गुजरेगी, वहां पैदा हो जाएंगे। भारत के इस पूरे क्षेत्र में पर्यटन उद्योग भी बढ़ेगा। यानी मोदी सरकार के एक कदम उठाने से एक साथ अनेक प्रकार के लाभ होना स्वभाविक है। इसके चलते इस पूरे परिक्षेत्र में अनेक नई योजनाएं जहां आएंगी, वहीं रुकी हुई योजनाओं पर फिर से काम संभव हो सकेगा। फिलहाल गौर करने वाली बात है कि भारत अपनी सिंधु प्रणाली के पानी का बेहतर उपयोग करने के लिए कई पनबिजली परियोजनाओं, जैसे-पाकल दुल (1,000 मेगावाट), रतले (850 मेगावाट), किरू (624 मेगावाट), और क्वार (540 मेगावाट) पर भी तेजी से काम कर रहा है। कठुआ जिले में वर्षों से लंबित उझ बहुउद्देशीय परियोजना को भी पुनर्जीवित किया जा रहा है। उझ के नीचे दूसरा रावी-ब्यास लिंक, जिसकी योजना पहले रावी के अतिरिक्त पानी को पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए बनाई गई थी, अब बड़ी नहर पहल का हिस्सा होगा। इसमें व्यास बेसिन में पानी स्थानांतरित करने के लिए एक बैराज और सुरंग शामिल होगी। उस रावी की एक सहायक नदी है।

Social Media Corner

सच के हक में...

आषाढ़ी बीज के विशेष अवसर पर, विशेष रूप से दुनिया भर के कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष सभी के लिए शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए।

(प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'एक्स' पर पोस्ट)

रथयात्रा के पावन अवसर पर श्री जगन्नाथ मंदिर, अहमदाबाद की मंगला आरती में शामिल होना अपने आप में दिव्य और अलौकिक अनुभव होता है। आज महाप्रभु की मंगला आरती में शामिल होकर दर्शन-पूजन किया। महाप्रभु सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें।

(अमित शाह का 'एक्स' पर पोस्ट)

किंगदाओ में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डॉन जून के साथ बातचीत की। हमने द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित मुद्दों पर रचनात्मक और दूरदर्शी विचारों का आदान-प्रदान किया। लगभग छह वर्षों के अंतराल के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर अपनी खुशी व्यक्त की। दोनों पक्षों के लिए यह आवश्यक है कि वे इस सकारात्मक गति को बनाए रखें और द्विपक्षीय संबंधों में नई जटिलताओं को जोड़ने से बचें।

(राजनाथ सिंह का 'एक्स' पर पोस्ट)

व्यर्थ है भारत के कमजोर होने का कांग्रेसी तर्क

कांग्रेस ने इन दिनों अपने युवराज राहुल गांधी के जरिए लगातार केंद्र सरकार की आलोचना के लिए जो रास्ता चुना है, वह सही नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उनके द्वारा उठाया गया ये मुद्दा सत्य से बहुत दूर दिखता है। उनका तर्क है कि मोबाइल फोन एवं विनिर्माण क्षेत्र के सभी उत्पाद भारत में असेंबल किए जा रहे हैं और उनके पुर्जे विदेश से आयात किए जा रहे। वे केंद्र सरकार को यह कहकर घेरते दिखे कि मेक इन इंडिया ने फैक्टरी बूम का वादा किया था। तो फिर विनिर्माण रिकॉर्ड निचले स्तर पर क्यों है, युवा बेरोजगारी रिकॉर्ड ऊंचाई पर क्यों है और चीन से आयात दोगुने से अधिक क्यों हो गया है राहुल यह भी समझाते हैं कि हमें दूसरों के लिए बाजार बनना बंद करना होगा। अगर हम यहां निर्माण नहीं करते हैं, तो हम उन लोगों से खरीदते रहेंगे जो निर्माण करते हैं। किंतु, क्या राहुल यहां जो बता रहे हैं, वह उतना ही सच है, जैसा कि कहा जा रहा है भारत क्या विनिर्माण क्षेत्र में लगातार कमजोर हुआ है या फिर जैसा कांग्रेस कह रही है कि हम दूसरों के लिए बाजार बन गए हैं, वह पूरा सच है। वस्तुतः जैसा कि अर्थ, वाणिज्य और उद्योग जगत के जानकार जानते हैं, बाजार में हर कुछ एक दूसरे पर निर्भर है। यह हो सकता है कि कभी कोई आगे तो कभी कोई कुछ या अधिक पीछे दिखाई दे, लेकिन हमेशा परिणाम सकारात्मक या नकारात्मक ही होंगे, यह बाजार में कभी स्थायी रूप से होता नहीं है। जहां तक भारत के विनिर्माण क्षेत्र में कार्य करने एवं विकास का प्रश्न है तो आंकड़े जो कहते हैं, वह ऐसे वक्त में जब दुनिया के तमाम देशों के बीच जहां परस्पर युद्ध का साया मंडरा रहा है तो कहीं सीधे युद्ध जैसी स्थितियां हैं, फिर भी बहुत आशावादी और उत्साहवर्धक कहे जा सकते हैं। ये कुछ आंकड़े हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब केंद्र में सरकार बनी तब देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी। ग्यारह साल में अर्थव्यवस्था को ग्यारहवें नंबर से चौथे नंबर पर आ गई। आज भारत दुनिया की टॉप पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है। यह लगातार चौथा वर्ष है, जब भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रहा है। प्रति व्यक्ति आय में 67 प्रतिशत, विदेशी मुद्रा भंडार में 135 प्रतिशत, निर्यात में 825 अरब अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड स्तर, एफडीआई में 106 प्रतिशत, टैक्सपेयर्स की संख्या में 127 प्रतिशत और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 238 प्रतिशत की वृद्धि भारत के संदर्भ में आज दिखाई देती है। पिछले 11 वर्षों में 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। विचार करें, क्या यह सरकार के बिना सही प्रयास वगैर संभव होता। यह तो सभी जानते हैं कि सरकारी नौकरियां कुल जनसंख्या में अधिकतम तीन प्रतिशत लोगों को ही दी जा सकती हैं। ऐसे में शेष 97 प्रतिशत के लिए रोजगार, श्रम एवं कृषि ही वह उपाय है, जहां से वे अपने लिए आय प्राप्त कर सकते हैं। स्वभाविक तौर पर इसमें सबसे बड़ा हिस्सा वर्तमान में उद्योग-धंधे से होनेवाली आय का है। यदि देश में विनिर्माण क्षेत्र कमजोर होता, तब फिर 27 करोड़ लोगों का गरीबी की रेखा से बाहर निकलना कभी संभव ही नहीं होत। यानी भारत के विनिर्माण क्षेत्र में अच्छा कार्य हो रहा है और रोजगार के तमाम अवसर सुगम है, इसलिए देश में गरीबी कम हो रही है, लखपति के बाद अब करोड़पति और अरबपतियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसी जून माह के प्रारंभ में भारत के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के संबंध में रिपोर्ट देखने को मिली। जो कहती है कि मई में भारत का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई मई में 57.6 रहा। मजबूत मांग और रिकॉर्ड हायरिंग दर्ज की जा रही है। हालांकि मई में पीएमआई अप्रैल के 58.2 से मामूली रूप से कम रहा है, फिर भी ध्यान देने योग्य है कि पीएमआई 50 से ऊपर होता है तो यह वृद्धि को दिखाता है। यानी भारत वर्तमान में वृद्धि करते हुए साफ दिखाई देता है। स्वभाविक है कि यह मजबूत वृद्धि घरेलू और विदेशी मांग के साथ-साथ सफल मार्केटिंग प्रयासों के कारण हुई है, जिसने निर्यात ऑर्डर को पिछले तीन वर्षों के सबसे उच्च स्तर पर पहुंचा दिया। एचएसबीसी की ओर से किए गए पीएमआई सर्वेक्षण में देश भर की फर्मों ने एशिया, यूरोप, पश्चिम एशिया और अमेरिका के प्रमुख बाजारों से बढ़ती रुचि के बारे में भी बताया है।

नतीजों का इशारा

पांच विधानसभा क्षेत्रों- गुजरात में कडी (एससी) व विसावदर, केरल में नीलांबुर, पंजाब में लुधियाना पश्चिम और पश्चिम बंगाल में कालीगंज में उप-चुनाव के नतीजे स्थानीय और क्षेत्रीय स्तरों पर भूमिका निभाने वाले कारकों की ओर इशारा करते हैं। कांग्रेस-नीत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के उम्मीदवार आर्यदान शौकत ने नीलांबुर सीट जीती। साल 2021 में वाम समर्थित निर्दलीय के रूप में जीतने वाले पीवी अनवर ने स्थानीय गठबंधन के साथ तकरार के बाद यह सीट खाली की थी। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया, जिसके खारिज होने के बाद वह निर्दलीय खड़े हुए। यह सीट वायनाड लोकसभा क्षेत्र में पड़ती है, जिसकी नुमाइंदगी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी करती हैं। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार ने खराब प्रदर्शन किया। यह नतीजा अगले साल होने वाले केरल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के सुर पर असर डाल सकता है। नीलांबुर के नतीजे से दोनों मोर्चों में समुदायों की गुटबंदी और दलों की सापेक्षिक शक्ति प्रभावित होगी। नदिया जिले में कालीगंज निर्वाचन क्षेत्र में, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार आलिफा अहमद ने 50 हजार से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। उनके पिता की मौत के चलते उप-चुनाव हुआ। देसी बम फटने से एक बच्चे की मौत ने मतगणना के दिन को दागदार बनाया, जो इस बात की निशानी है कि राज्य में लगातार और परेशान करनेवाली हिंसा की भूमिका बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव अगले साल होंगे। विसावदर और लुधियाना पश्चिम में आम आदमी पार्टी (आप) की जीत, फरवरी में अपने मूल गढ़ दिल्ली में सत्ता गंवा चुकी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। विसावदर में उसके विधायक भाजपा में चले गए थे और नए सिरे से मिला यह जनादेश राज्य की राजनीति में अपना हिस्सा बनाए रखने में आम आदमी पार्टी की मदद करेगा। उसके पूर्व राज्य अध्यक्ष गोपाल इटालिया विजयी हुए हैं। आप के पूर्व राज्यसभा सांसद और उद्योगपति संजीव अरोड़ा ने लुधियाना पश्चिम सीट जीती, जो उस राज्य में है जहां इस पार्टी का राज है।

Printed and Published by Fahim Akhtar on behalf of MAA MEDIA VENTURE and Printed at SHIVA SAI PUBLICATION PVT.LTD, Ratu, Kathitand, Near Tender Bagicha, H.P. Petrol Pump P.O.+P.S.- Ratu, Dist.-Ranchi, 835222, Jharkhand And Published at Roshpa Tower, 5th Floor, Main Road, Ranchi, Jharkhand-834001. R.N.I Number - JHABIL/2022/85899, Editor- Fahim Akhtar. Mob - 9431311669, E-mail : thephotonnewsjharkhand@gmail.com

Boon or bane? Expert says India's Colon Hydrotherapy trend may not be for everyone

New Delhi. Colon hydrotherapy or colonic irrigation has taken India's wellness scene by storm. Said to detoxify the body by purifying, detoxifying, aiding weight loss, and ensuring healthy skin, it has emerged as a so-called therapy service at spas, naturopathy centers, and luxury wellness resorts. However, while the idea of detoxifying the body is in vogue among Indians with a health-conscious lifestyle, doctors are cautioning people to use caution. Colon hydrotherapy entails inserting a pipe into the rectum to flow massive quantities of water into the colon, which is afterward flushed out to supposedly purify the intestines. While it may sound harmless cleansing method, the medical aspect of this trend must be unravelled before it can be taken as a health treatment.

Dr. Aravind Badiger, Technical Director, BDR Pharmaceuticals, explained why this trend is becoming famous among Indians.

Why Colon Hydrotherapy Appeals to Urban India

Growing digestive issues like bloating, gas, and unpredictable bowel habits are driving Indians into quick fixes.

A growing number of wellness influencers and social media marketing have fuelled the idea that colonic cleansing is a necessary reboot for health. Most people experience instant relief and lightness after the procedure, which also drives demand. But the science disagrees.

The Colon Cleans Itself: The human body is very efficient at detox. The colon, kidneys, and liver all work together in the natural removal of waste. There is no scientific basis for which colon flushing increases this process naturally. Over-involvement can deplete good gut bacteria that support digestion and immunity.

Potential Risks and Complications: Side effects of colon hydrotherapy include dehydration, electrolyte imbalance, bowel perforation, or infections, especially if improperly or too frequently performed. Prolonged treatments may impair the normal ability of the colon to contract, resulting in chronic constipation or addiction.

Not Recommended for Everyone: People with a history of gastrointestinal issues like hemorrhoids, diverticulitis, or inflammatory bowel disorders like Crohn's disease or ulcerative colitis are at higher risk for complications. Elderly individuals and pregnant women should also avoid it unless recommended by a doctor.

The dependence on psychological factors: Individuals might have a psychological need for colonic surgeries in certain situations so that they can feel "healthy" rather than taking longer-term, more effective treatments such as medication or diet changes.

A More Secure Route to Digestive Health: To encourage regular bowel movement, boost your intake of fibre found naturally in foods including fruits, vegetables, and whole grains. Drink plenty of water during the day to make digestion easier and soften the feces.

Regular exercise to boost the natural digestion of the body: Walk, exercise gently, or do yoga daily to naturally stimulate your digestive system. To maintain your gut microbiota balance, have probiotics in your diet through curd or fermented foods.

When the tail wags the dog

Trump's stern warning to Israel played a key role in shoring up a fragile ceasefire with Iran

IN the end, Tehran's roar of anger over the blatant violation of its sovereignty by Israel and the US came out as little more than a hesitant whimper. Its missile attack on the US Central Command air base at Al Udeid in Qatar on the night of June 23 had been telegraphed well in advance, and the 40 American fighter jets and several thousand defence personnel had been evacuated to safe locations. Their air defence systems were waiting, the incoming missiles were intercepted, but Iran's faltering regime could announce that it had hit back at the enemy and could now accept a ceasefire.Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu called it a historic win for his country. For Iran, pragmatism and a strong instinct for self-preservation had prevailed over bravado and bluster. Like Iraq under Saddam Hussein, the Iranian regime stood exposed before the world and before its own people for the shambolic performance of its armed forces in the face of Israel's technological superiority. Its vast defence and security infrastructure was clearly more effective in suppressing its own people than in countering a real enemy. Having survived the ordeal, the regime quickly declared its own victory so that it can again turn its misogynist eye towards its own people.Even as the guns have nervously fallen silent, it is useful to review the events of a truly unprecedented fortnight since Israel launched its unprovoked attack on Iran's nuclear and military facilities on June 13. Netanyahu has clearly accomplished something of a coup in the US, even as a second one in Tehran remains an aspirational goal. Against odds, he persuaded President Donald Trump to use the full force of US weaponry against Iranian nuclear facilities in Fordow, Natanz and Isfahan.Trump agreed to do Netanyahu's bidding despite testimony by Director of National Intelligence Tulsi Gabbard before the US Congress in March that Iran was not building a nuclear weapon and that Supreme Leader Ali Khamenei had not reauthorised the nuclear weapons programme that had been suspended in 2003. And Trump acquiesced to Netanyahu's demand despite strong opposition from MAGA stalwarts like Steve Bannon, Tucker Carlson and Marjorie Taylor Greene and his own campaign pledges to stay away from foreign conflicts. From a distance, it looked like a case of the tail wagging the dog?

Netanyahu's own histrionics were on repeated display as he warned against Iran's suspected nuclear weapons programme as an imminent and existential threat for Israel. It's a line that he has been practising since he was a young Member of the Knesset in 1992, one that he has repeated in testimony at the US Congress in 2002, at the UN in 2012 and on numerous other occasions. "By next spring, at most by next summer…" he cried as he displayed a kindergarten-level cartoon drawing of a bomb in the UN General Assembly. His melodrama invoked incredulous gasps from an audience that still remembered US Secretary of State Colin Powell brandishing fuzzy satellite images to make the infamous case about Saddam's 'Weapons of Mass Destruction' as a prelude to the disastrous invasion of Iraq.In between bombing Iranian facilities and carrying out targeted assassinations of key figures from the Iranian regime, Netanyahu also shifted gears on the dubious and dangerous gambit of regime change in Iran. The notion quickly travelled to Washington and produced some

genuinely mind-bending dissonance, with Vice President Vance and Secretary of State Rubio vigorously denying any such intent, while Trump mused about its virtues in his social media posts. Memories of the unmitigated disasters that followed US-led regime change operations in Afghanistan, Iraq, Libya and elsewhere were temporarily erased by Washington's selective amnesia.

Amid the din of the 12-day war and its aftermath, three elements stood out. First, the emasculation of the UN and the burial of international law under the debris of the 14 GBU-57 'bunker buster' bombs that the US dropped on Iran. The collapse of the multilateral international order is now proceeding on steroids. It is being replaced by the ancient reality of hard power spelled out by Thucydides some 2,500 years ago. "The strong do what they can and the weak suffer what they must", aka "Jiski laathi, uski bhains".Second, the hypocrisy of the Western nations as they line up to support the case for Israel's attack on Iran. In doing so, they ignore the glaring contradiction that Israel's formidable fighting force, armed with an estimated 90 nuclear bombs and enjoying the unlimited support of the world's only military superpower, faces 'an existential threat' from Iran because of suspicion that it is developing a nuclear weapon.Commitments to a rules-based international order and sovereign borders that were so central when Russia invaded Ukraine now lie discarded in the dustbins of convenience. And third, beware the law of unintended consequences. Several middle powers will now view the acquisition of nuclear weapons as an essential insurance policy. The case histories of Ukraine and Iran will be contrasted with the experience of Israel and North Korea and indeed of India and Pakistan to reinforce the logic of going nuclear. No one should be surprised if Iran becomes the first in this race to go nuclear despite the damage wrought on its declared and clandestine facilities.The Arab countries of the Gulf also got a reality check as they faced precisely the kind of scenario that they had hoped to avoid when they rolled out the red carpet for Trump in May. Transactional Trump was happy to take the big arms deals, the business and crypto contracts and even the gilded Boeing 747, but the vital interests of his allies in the Gulf quickly fell by the wayside. Their fears of Iran as a regional bully that was bent upon exporting its medieval version of Islam to its neighbours are now replaced by two more immediate concerns — of Israel as the belligerent regional hegemon, and of a wounded Iran that had its back to the wall and could have lashed out by attacking their oil facilities, the US bases that they host or even by blocking the Strait of Hormuz.This also had serious implications for India in terms of our energy security, trade flows and the wellbeing of our nine million-strong expatriate community in the Gulf states.Fortunately, Trump likes to position himself as the big dog in a fight. He surprised everyone, including members of his own team, by announcing a ceasefire in the early hours of June 24. And his stern warning to Israel to stop its planes from bombing Iran played a decisive role in shoring up a fragile ceasefire. It is still early days, but Trump showed that when push comes to shove, he can still turn around and snap at his tail.

Fix Kabini dam soon to avert disaster

Although experts have ruled out an immediate threat to the Kabini dam structure, they have insisted that any neglect or delay in filling up the cavity and crack can have disastrous consequences

The 51-year-old Kabini dam in Karnataka's Mysuru district has raised serious concerns after an inspection. Underwater robots and cameras deployed by the irrigation department recently detected a crack of up to half a metre and a cavity through which water is leaking. The dam is on Kapila river, a tributary of the Cauvery, and is crucial to provide water for irrigation, drinking and power generation in both Karnataka and Tamil Nadu, between whom water-sharing is a very sensitive issue. Kapila as a feeder to Cauvery benefits the Karnataka districts of Mandya, Hassan, Tumakuru, Ramanagara, Mysuru, and the state capital Bengaluru, besides the Tamil Nadu districts of Thanjavur, Thiruvarur, Nagapattinam, Mayiladuthurai, Pudukkottai, Cuddalore and RamanathapuramThe Kabini reservoir now is almost up to the brim, recording 2,278.4 feet against the maximum storage height of 2,284 feet, due to the persistent heavy rains in its catchment area over the past few days. Any weakening of the structure leading to more water leakage could pose severe problems for the downstream Krishnaraja Sagara dam, which is already filled up to 120.9 feet against a maximum height of 124.8

feet. Unusual flows from these dams would not just adversely affect agricultural activities in the delta regions of the two states, but a worse-case scenario like a structural collapse can be catastrophic with flooding of parts of Mysuru and Kodagu.Although experts have ruled out an immediate threat to the Kabini dam structure, they have insisted that any neglect or delay in filling up the cavity and crack can have disastrous consequences. Irrigation department officials are preparing a report for the ?85-crore strengthening work to present to the Union government and are expecting to invite project bids in November. The high turbidity of water is claimed to be an obstacle for professional divers to do the filling up right away, raising the question why maintenance works were not taken up when the reservoir's levels were not as high. Dam Safety Act, 2021 mandates both the state and central institutional frameworks to undertake regular maintenance. The Karnataka and Union governments must work together on a war-footing despite their political differences to avert any catastrophe arising from delayed maintenance work at these crucial sites.

A look below India's poverty lines

While a World Bank report claims India's poverty rates have fallen sharply, other studies show that tackling deprivation remains a deeply challenging endeavour. While the government's safety nets have helped, India must fix its unemployment problem and grow at a much faster rate if it is to eradicate poverty in the near future

Has poverty been nearly eradicated in India? Yes, if one goes by the findings of a World Bank brief on poverty and equity released in April. As per the report, the proportion of people in India living below the revised international poverty line of $3 per capita per day at 2021's purchasing power parity (PPP) has declined sharply from 27.1 percent in 2011-12 to 5.3 percent in 2022-23.

If one uses the previous international poverty line of $2.15 per capita per day (2017 PPP) the proportion below the poverty line in India fell from 16.2 percent in 2011-12 to 2.3 percent in 2022- 23. This implies that over the period from 2011-12 to 2022-23, about 171 million people were lifted above the poverty line. If, on the other hand, one uses the international poverty line of $3.65, applicable for lower middle-income countries such as India, the proportion declined from 61.8 percent to 28.1 percent during the same period.The World Bank's findings are based on data from India's Household Consumer Expenditure Surveys of 2011-12 and 2022-23. Given that the methodology used for these two surveys was different, the World Bank has not clarified how these two sets of data were made comparable. The Indian government did not release the 2017-18 HCES due to data quality issues, although it followed the same methodology as the 2011-12 survey.

In a recent article, former RBI Governor C Rangarajan and Mahendra Dev, Chairman of the Economic Advisory Council to the Prime Minister, argue that India's GDP growth primarily explains this decline in poverty. This is questionable considering the history of East Asian economies, which experienced a sharp decline in poverty levels only at high economic growth rates. China, for instance, reported a sharp decline in poverty levels only when GDP growth exceeded 10 percent between 1978 to 2010. India's average GDP growth rates have ranged between 3.8 percent and around 7 percent in the last 10 years, except for -5.38 percent in 2020 due to the Covid pandemic.

Moreover, evidence shows the fruits of growth have largely accrued to the rich. Despite the growth, the share of labour in India's gross value added has recorded only a slight increase whereas corporate profits have surged. Oxfam's Inequality report for India shows the richest 1 percent controlled more than 40 percent of the country's total wealth, whereas the bottom 50 percent owned a mere 3 percent. About 73 percent of the wealth generated in 2017 went to the top 1 percent, whereas the bottom half reported a mere 1 percent increase in their wealth.Then what explains this steep decline in poverty? There is no doubt that the safety nets provided by the government such as the provision of free foodgrains to over 60 percent of the population and subsidised LPG to poor households largely explain it. However, if less than a twentieth are extremely poor in India, one may question the justification for providing free foodgrains to three-fifths of the population overlooking its adverse fiscal implications and impact on agricultural prices.Unlike the monetary-based poverty line used by the World Bank, the UNDP's multidimensional poverty index (MPI) measures the extent of deprivation based on 10 health,

education and standard of living indicators. Based on it, India reported 234 million people as multidimensionally poor in 2024. The poverty rate in terms of this broader definition of deprivation was 16.4 percent. India along with Pakistan, Ethiopia, Nigeria and the Democratic Republic of the Congo accounted for nearly half the global multidimensionally poor population of 1.1 billion people.According to the National Family Health Survey conducted in 2019-21, despite the government's initiatives to address malnutrition such as POSHAN and Integrated Child Development Services, about 35.5 percent of children aged under 5 years are stunted, 19.3 percent 'wasted', and 32.1 percent underweight. Further, 7.7 percent of children are 'severely wasted', or are facing acute malnutrition.Unemployment among youth, women and rural people continues to be high alongside wage stagnation among workers. As per the latest Periodic Labour Force Survey data released by the Union ministry of statistics, the unemployment rate among youth in the age group 15-29 years in rural areas rose to 13.7 percent in May 2025 and 17.9 percent in urban areas. Unemployment rates for women also rose to 5.8 percent. The Centre for Monitoring Indian Economy states that India's youth unemployment rate during the past decade has hovered around 22 percent. Critics therefore refer to the past decade as one characterised by jobless growth.India still has a long way to go before poverty can be totally eradicated. For this to happen, India's annual GDP growth rate needs to be accelerated to 10 percent or more. While it is laudable that India has outstripped Japan in total economic output, the GDP per capita in India—at $2,711 in 2024—is still a tenth of that in Japan, where it is at $33,950.

No guarantees in mutual funds: Investment adviser warns against risky PF advice

New Delhi. Withdraw your PF and invest in mutual funds. I can get you 12% guaranteed." That's what a financial advisor told someone recently. Sounds smart? "It's actually reckless advice," said Abhishek Kumar, a Sebi-Registered Investment Adviser and founder of SahajMoney."Because here's the truth: no one can 'guarantee' 10–13% returns in mutual funds. That's not how market-linked products work," he said in a recent Linkedin post.Kumar, who has been in the financial planning business for over 15 years, says he has seen many such cases—"well-meaning families being misled in the name of 'higher returns.'"He calls this kind of advice dangerous, especially when it involves the Provident Fund, or PF. "PF is your retirement safety net. That money is meant to grow slowly, safely, and tax-free. Touching it for higher-risk products can wreck your future security."

While mutual funds can be valuable tools for wealth creation, Kumar stresses they are not meant to replace guaranteed instruments. "Mutual funds are great, but not for guaranteed income. Returns are market-driven. One year may give 15%, another might give -2%."The push for guaranteed returns, he adds, often comes from individuals who don't have the investor's best interests in mind. "Many 'advisors' are actually sales agents. They earn commission when you invest through them. That means their advice often serves their income, not your goals."

And just because it's possible to withdraw PF doesn't mean it's the right choice. "Yes, you can withdraw PF. But should you? Unless there's an emergency or a solid retirement backup—don't mess with it."Kumar also points out that "risk isn't always visible up front."

"When the market crashes, it's not the advisor who suffers—it's you," he added.His advice for individuals is to stay alert and avoid falling for promises related to market-linked returns. "So take 'guarantees' with a mountain of salt. If your advisor pushes risky products with fake guarantees, fire them. A real advisor will protect your peace of mind, not gamble your future."

JSW Paints to acquire majority stake in Akzo Nobel India

NEW DELHI. JSW Paints has signed a definitive agreement to acquire a 74.7% stake in Akzo Nobel India Ltd for Rs 8,986 crore, marking the Jindal Group's biggest acquisition to date and signalling a major shake-up in India's paints industry.

With this move, JSW Paints will take sole control of Akzo Nobel India, which operates under the Dulux brand, and emerge as the fourth-largest player in the decorative paints segment.The transaction involves the sale of shares held by Akzo Nobel's two promoter entities—Imperial Chemical Industries Ltd (50.46%) and Akzo Nobel Coatings International B.V. (24.30%). Following the acquisition, JSW Paints is required to make an open offer for an additional 26% stake, in line with SEBI regulations.

According to JSW Paints, Morgan Stanley acted as its exclusive financial advisor, while Khaitan & Co. provided legal counsel and Dloitte led the financial and tax due diligence.

Headed by Parth Jindal, JSW Paints has struggled to break into the top three since its launch six years ago. While newer rival Birla Opus (Grasim Industries) has already captured around 7% market share since its February 2024 debut, JSW Paints has largely operated below the radar in the decorative segment.Akzo Nobel India has historically focused on luxury and ultra-premium products under the Dulux brand, with a strong presence in urban markets. The acquisition will give JSW immediate brand equity, market reach, and capacity to challenge incumbents like Berger Paints and Kansai Nerolac. Post-deal, JSW will also become the second-largest player in the industrial paints segment, trailing only Kansai Nerolac.

Why Jio Financial Services shares are rising

New Delhi. The Jio Financial's shares are on the rise after Securities and Exchange Board of India (SEBI) gave its nod to Jio BlackRock Broking to work as a stock broker and clearing member.

The Jio Financial stock gained around 5 percent on the BSE on June 267, 2025. The counter opened at Rs 313.85 against its previous close of Rs 312.40 and surged 4.5 per cent to reach an intraday high of Rs 326.55. At around 12:30 pm, the scrip was trading at Rs 325.80, a gain of 4.25 per cent.Jio Financial has informed the exchanges that the Securities and Exchange Board of India has issued a certificate of registration to Jio BlackRock Broking Private Limited as a stock broker and clearing member on June 25, 2025.The latest development comes after Jio Financial Services on June 11 in its exchange filing stated that Jio BlackRock Investment Advisory has received approval from SEBI to act as an investment advisor.

"Securities and Exchange Board of India, vide letter dated June 10, 2025,has granted certificate of registration to Jio BlackRock Investment Advisers Private Limited ("JBIAPL") to act as an Investment Adviser," Jio Financial has mentioned in its regulatory filing.On June 26, 2025, Jio Financial Services Ltd (JFSL) announced to pump in Rs 190 crore in its payments bank subsidiary. The company informed the exchanges that it has been allotted 19,00,00,000 equity shares of Rs 10 each of Jio Payments Bank Ltd.

The Company has today, subscribed to and has been allotted 19,00,00,000 equity shares of Rs 10/- each of Jio Payments Bank Limited, wholly owned subsidiary, for cash at par, aggregating Rs 190 crore. The transaction is between the company and its wholly owned subsidiary and hence a related

party transaction. It is on an arm's length basis. None of the Company's promoter / promoter group / other group companies have any interest in the above transaction. No governmental or regulatory approval is required for the above transaction.

Rs 45 lakh for raising a child Why parenting feels like a luxury now

Rising everyday expenses, pricey education and costly healthcare are forcing many young couples to think twice about kids. According to a startup founder, starting a family is personal, but money has become a key factor.

New Delhi. Starting a family is a dream for many young couples in India. But these days, money worries are making that dream feel out of reach for some. Raising a child in urban India now costs almost Rs 45 lakh, making it an expense many young couples simply can't justify. Bengaluru-based startup founder Meenal Goel, broke down the numbers in a LinkedIn post, showing how middle-class parenting is turning into an unaffordable luxury.She wrote, "Cost of raising a child in India is ~ Rs 45 lakhs! We are scared to have a kid, because we cannot afford it. I recently met a couple who said this, and honestly, they're not wrong." The financial demands during this phase are substantial, requiring careful budgeting and planning. Moreover, these early years set the foundation for future expenses, making it essential to plan ahead.

Goel further wrote, "So I sat down and did the math. What does it actually cost to raise a child in India in 2025?"She broke it down stage by stage. From birth to preschool, expenses quickly accumulate. Hospital delivery costs range between Rs 1.5 and Rs 2.5 lakhs, while vaccinations can add another Rs 30,000 to Rs 50,000.Essential items such as baby gear, food, and diapers account for approximately Rs 3 lakhs. Additionally, the cost of playschool and daycare can be around Rs 2.5 lakhs, bringing the total to Rs 7–8 lakhs by the time the child reaches school age.She further wrote that the school years, from

ages 6 to 17, represent a significant portion of the financial commitment. School fees alone can amount to Rs 12 lakhs. Extra tuition and coaching could add Rs 3 lakh. Gadgets, uniforms, books, and activities take up another Rs 2 lakh, bringing this phase to about Rs 17 lakh.It doesn't end there. Higher education costs are rising too. College can take another Rs 13 lakh if you add up private college fees, hostel stay, food and other living costs.

Add all this up and the price of raising just one child lands between Rs 38–45 lakh, writes Goel. "Finance is a real fear when it comes to family planning. Are you also planning to have a kid in 2025 and feeling the money pressure?" Goel pointed out.

Put simply, the rising cost of living, expensive schooling and high healthcare expenses are making young couples think twice. Some are postponing or rethinking parenthood altogether.Though starting a family is a personal choice, money has become a big deciding factor. With expenses only set to rise, smart saving and planning ahead could ease the strain for future parents.

Where are India's ultra-rich families investing in 2025

A new EY–Julius Baer report, The Indian Family Office Playbook, reveals that many family offices are moving away from traditional wealth preservation and diving into global markets, private credit, and real assets.

New Delhi India's ultra-wealthy aren't just sitting on their fortunes anymore. In 2025, they're stepping out, investing boldly, and thinking globally. A new EY–Julius Baer report, The Indian Family Office Playbook, reveals that many family offices are moving away from traditional wealth preservation and diving into global markets, private credit, and real assets.Family offices, typically set up by high-net-worth individuals (HNIs) or ultra-high-net-worth individuals (UHNWIs), help manage everything from global investing and succession to philanthropy and compliance.India is now home to over 300 family offices—up from just 45 in 2018. And while 25% of them still put capital preservation front and centre, the big picture is clear: diversification is in, and legacy-building is taking centre stage."Families now seek efficiency, transparency, and global access—all of which require a more structured approach," said Surabhi Marwah, Co-leader of Private Tax and Partner at EY India. "The Indian family office ecosystem is at an inflection point where wealth preservation alone is no longer enough."So what does this new playbook look like? For starters, family offices are investing across borders,

with interest rising in global equities, private equity, venture capital, and real estate. Private credit—once a niche space—is quickly gaining popularity for its steady returns and built-in downside protection. And this global hunger is backed by numbers: under the Liberalised Remittance Scheme, outbound flows jumped from $18.8 billion in 2019–20 to $31.7 billion in 2023–24.

But it's not just about chasing returns. Global investing brings its own headaches. The report shows 48% of family offices are worried about shifting tax laws, and 37% are grappling with cross-border rules. These concerns are shaping strategy just as much as the returns themselves."Family offices are increasingly catering to first-generation entrepreneurs who are more risk-tolerant and open to emerging sectors," said Umang Papneja, CEO of Julius Baer India. "As the scale and complexity of wealth grow, there's a stronger focus on strengthening governance, growing asset value and planning for legacy succession."Interestingly, despite the enthusiasm for alternatives, private markets are still approached with caution. About 57% of family offices allocate less than 10% of their portfolios to private equity or venture capital, often due to limited access or a conservative approach.

Madras High Court backs bank appointment cancellation over adverse CIBIL report

NEW DELHI. The Madras High Court has upheld a decision by a public sector bank to cancel the appointment of a candidate due to a poor credit history. The court ruled that financial discipline is crucial in banking jobs and found no fault in the bank's action.The petitioner, who had cleared all stages of recruitment for the post of Circle Based Officer (CBO) at State Bank of India (SBI), including exams, interviews, and medical checks, had his appointment cancelled after the bank found an adverse credit report in his CIBIL history.According to a report on Live Law, the candidate argued that he had no pending dues at the time of the job notification and claimed that his appointment was unfairly revoked. He also alleged discrimination, saying others in similar situations were allowed to join.SBI maintained that Clause 1(E) of the eligibility criteria of its recruitment policy, disqualifies

candidates with poor credit histories or defaults in repaying loans or credit card dues. The bank noted that the candidate's CIBIL report showed multiple credit irregularities and more than ten credit enquiries, indicating serious financial mismanagement.The bank also alleged that the candidate had failed to fully disclose this history during the application process.

Justice N Mala said the bank had acted prudently. She observed that banking employees handle public money and therefore must maintain strong financial discipline. "A person with poor or no financial discipline cannot be trusted with public money," the judge noted.The court also dismissed the claim of discrimination, stating that only those who met all eligibility requirements were appointed.

Finding no merit in the petition, the court upheld the bank's decision and dismissed the plea.

Switched jobs this year Here's how to file your ITR right

New Delhi Switched jobs or worked for more than one company this year? If yes, your income tax return (ITR) needs extra care. Many people forget that salaries from all employers must be declared. Missing this can lead to unwanted tax notices or extra dues later.For the financial year 2024–25, if you got paid by two employers, maybe you changed jobs mid-year or did multiple roles, you must add up all income, check your deductions properly, and make sure you don't claim the same exemption twice.CHECK YOUR FORM-16 DETAILS CLOSELY

Form-16 is your main salary proof from each employer. While filing your tax return, pay close attention to what's in your Form-16.

Check your total (gross) salary, the allowances and deductions claimed from your salary, any deductions under Chapter VI-A like 80C or 80D, and your TDS (tax deducted at source).

If you worked for more than one employer in the same year, make sure to report each salary and related deductions separately in the ITR form. Don't mix them up; each employer's income should be shown in its own section. This helps avoid overlaps and mistakes.

BE CAREFUL WITH DEDUCTIONS

One big mistake is claiming the same deduction twice. For example, Section 80C lets you claim up

to Rs 1,50,000 a year, and not Rs 1,50,000 for each job. So, add up all your actual investments and claim the total, not the sum reported by both employers.

SHOW TDS CORRECTLY

Your ITR has a separate 'Schedule TDS' section. Here, mention each employer's TDS with their name and TAN number. If you switched jobs, the new company may not have counted your old salary and TDS. If that's the case, you might have to pay extra tax yourself as Self-Assessment Tax, before filing the return.So, if you've changed jobs this year, spend a few extra minutes checking your numbers. Reporting all income and claiming only what you're eligible for will keep your taxes in order and help you avoid penalties.

Will Sensex and Nifty hit record highs in July Here's all you need to know

With domestic flows steady and global risks fading, July could be the moment markets break through resistance. But with key events ahead, will momentum hold or falter?

New Delhi. Benchmark indices are moving closer to record highs, and the momentum looks set to continue into July, powered by resilient domestic flows, macroeconomic tailwinds, and solid performances from frontline stocks like Reliance Industries and top banks.The Nifty 50 has risen 2.9% in the June derivatives series, while small- and mid-cap indices posted gains of 5.1% and 3.1%, respectively, reported Reuters. And this rally has taken both the Nifty and Sensex within 3% of their all-time highs touched in late September last year.NEW RECORD HIGHS IN SIGHT

What's interesting to note here is that foreign istitutional investors are not fuelling this rally. Domestic institutional investors and steady SIP inflows have provided a strong liquidity base, even as foreign institutional investors (FIIs) have remained cautious. Analysts now say the market's resilience is hard to ignore.

"Markets have grown increasingly resilient to external noise, from geopolitical tensions to US presidential tweets. There is little doubt that the bullish momentum is here to stay," Abhilash Pagaria, Head of Alternative and Quantitative Research at Nuvama, told Reuters.

The July derivatives series, which runs from June 27 to July 31, has begun with lighter FII short positions compared to the previous month, signalling a slight shift in sentiment. Retail and high net-worth investors are taking a more selective approach, scaling back on index-wide bets while leaning into specific stocks.According to Sriram Velayudhan,

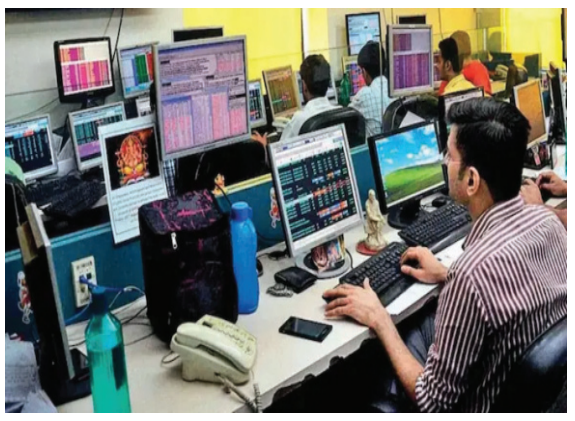

Senior Vice President at IIFL Capital Services, the sustained strength in blue-chip names such as Reliance and major banks could create a path for the Nifty to reclaim all-time high levels.

While the broader sentiment remains positive, some caution remains around key upcoming events. These include the July 9 deadline for US reciprocal tariffs, the Federal Reserve's next interest rate decision, and the upcoming corporate earnings season—all of which could introduce short-term volatility.

TRADERS CONFIDENT

Still, early signals suggest traders remain confident. Open interest at the start of the July series stood at 80% on the Nifty and 89% market-wide, indicating heightened participation and conviction in continued upside.The news agency also reported that long positions are building up in sectors like telecom, cement, IT, banking, metals, and chemicals. Meanwhile, autos are seeing some short-covering, and FMCG remains the only segment showing a marginal rise in short bets.The combination of macro stability, strong domestic liquidity, and stock-specific conviction appears to be setting the stage for a bullish July. Whether the Nifty breaks its previous record remains to be seen, but the wind, for now, is definitely at the market's back.

How a Kathak dancer is rewriting tradition, in ghungroos and turban

Ludhiana-based Taranjot Singh, one of India's first practising Sikh Kathak dancers, with all the markers of his faith intact, is challenging norms to follow his passion

Agency New Delhi.

At a modest dance studio in Delhi's Vikaspuri, 20-year-old Taranjot Singh — his turban tied neatly and beard flowing — turns his wrists to gently flick his little finger, mimicking the movement of kohl being applied to the eyes.

A gesture from Kathak's shringar ras, a staple in its presentation for centuries, it is meant to convey the intimacy of beautifying oneself. In the dance studio, a group of girls attending Singh's masterclass mimic the gesture, trying to find the grace that he brings to the fore.

Most students, along with their mothers, who sit outside waiting, have been following Singh's work on social media, where clips of him performing Kathak routines on Hindi film songs have struck a chord. For many, it is also the first time they have seen someone who looks like him — bearded and wearing a turban — taking on the role of a Kathak performer.

"I never wanted to cut my beard and shear my hair. I believe in my faith, which has taught me to stay grounded… But I also wanted to dance, specifically Kathak," says Singh, perhaps the first Sikh Kathak dancer in India with a turban and a flowing beard.

Like many boys in Punjab, he grew up with bhangra and Punjabi music, but also wanted to explore contemporary music. One day, 13 years old and a student at Kala Nikhar, a dance academy in Ludhiana, he saw one of his teachers, Pulkit Jain, performing Kathak while donning heavy ghungroos.

"The speed, the spins, the variation in spins, the difficult footwork — I thought it was all beautiful. And that I could do it all too," says Singh. Jain, a student of legendary Kathak dancer Pandit Rajendra Gangani, is a noted name from the Jaipur gharana, which is associated with powerful footwork and rhythmic virtuosity. One of the other prominent Kathak gharanas, Lucknow, emphasises bhav (expression), baithak thumri presentations (the art of sitting and expressing through one's face and subtle body movements) and storytelling.

"After Pulkit Sir encouraged me, I decided to give Kathak a shot. I never knew it would become such a significant part of my identity… Whatever I am today, it's because of Kathak," says Singh, who went on to win many local youth festivals and competitions before his television stint in 2024.

Gangster Manjit Mahal's nephew shot dead in Delhi's Bawana; police say fallout of a gang war

Agency New Delhi.

A 30-year-old man was killed and his seven-year-old daughter was injured when unidentified men shot at them in Delhi's Bawana area while they were out on a morning walk Friday.

The man has been identified as Deepak, and sources in the Delhi Police said they suspect the shooters could be linked to the gang of Kapil Sangwan, who is also known as Nandu, as the deceased is the nephew of jailed mafia don Manjeet Mahal, the Nandu gang's longtime rival.

According to senior police officers, the shooting took place at around 7.30 am when Deepak was walking with his daughter. Deepak died on the spot, and his daughter sustained injuries to her hand. She has been treated and is out of danger.

Deepak's body has been sent for post-mortem examination, the police said.

Meanwhile, the crime and forensics teams have reached the spot where the shooting took place, and are analysing the bullet shells.

Mahal and London-based Sangwan have been in each other's crosshairs even before he fled to the United Kingdom. The Delhi Police say the rivalry between the gangs originated out of a money lending dispute in 2015, when Mahal's associate allegedly gunned down Sangwan's brother-in-law over a pending loan. Sangwan then launched a full-scale gang war against Mahal, now jailed, and orchestrated the killing of his father in 2017.

Delhi Police arrest criminal after shootout in Rajouri Garden

Agency New Delhi.

The Delhi Police on Thursday night arrested a hardened criminal after a shootout in the Rajouri Garden area of West Delhi. According to the police, the encounter between the accused, Vinay, 36, and the police team took place behind the Sanjay Gandhi Animal Hospital around 10 pm, during a targeted operation to nab suspects involved in robberies and snatching cases in the area. Vinay, who sustained a gunshot injury to his right leg, was immediately overpowered and shifted to a hospital, said the police.

The accused, a resident of Sultan Garden in Najafgarh, is a habitual offender with 56 cases registered against him. According to e-prison records, he was also involved in a shootout with Delhi Police's Special Cell in 2021.

Acting on a tip-off, the police teams had been tracking the movements of the suspect, also called Mota, a hardened criminal with a long history of offences. The police mobilised multiple teams to intercept Vinay on Thursday after his movement was detected near the Rajouri Garden area, an officer said. After he was spotted on a motorcycle near the Nala Road stretch, the police cordoned off the area and attempted to stop him.

However, Vinay allegedly opened fire on the police party, and one of the bullets struck a bulletproof jacket worn by a member of the police team. In response, the police team returned fire in self-defence, during which the accused, the officer said.

Delhi government extends excise policy for 9 months, till March next year

Agency New Delhi.

The Delhi government on Friday decided to extend its existing excise policy, under which only government liquor shops are allowed in the city, for another nine months, till March 31, 2026.

According to officials, the government has formed a high-level committee to chalk out a new policy, and it will need time to finalise the modalities and guidelines. Meanwhile, as the existing policy's term ends on June 30, the excise department decided to extend the old excise regime under which four government corporations run liquor shops in Delhi.

"The Competent Authority has granted approval for continuation of Excise Duty Based Regime which is in effect from licensing year 2022-23. (which was continued in 2023-24 and 2024-25) for Excise Year 2025-26 (w.ef. 01.07.2025 to 31.03.2026), for grant of wholesale licenses on basis of same terms and conditions and accordingly new L-1, L-1F, L-2 Licenses are allowed on same terms and conditions of Excise Duty Based Regime," a notification issued by Tanvir Ahmad, Deputy Commissioner, Excise, on Friday reads. The notification said that the terms and conditions of all licences, which are renewable every year, are also continued for the excise year 2025-26 within the following timelines:

If the licensees pay the renewal fees within 30 days of the circular being issued, only the requisite licence fee (pro-rata) as per the licence category has to be paid.

If the payment is made in the 30-60 day period from the day of issuance of the circular, the licensees have to pay an additional fee of 25 per cent of the annual licence fee (pro-rata) along with the licence fee (pro-rata) as per the category.

Licensees who cross the 60-day period will have to pay an additional fee of 100 per cent of the annual licence fee (pro-rata) along with the license fee (pro-rata).

Meanwhile, the department has also asked concerned branches dealing with all the licences and permits granted or renewed to issue necessary circulars in this regard.

Delhi CNG pump owner robbed at farmhouse of Rs 30 lakh: Victim's drivers among 4 arrested

The incident took place on Monday night when the victim, Karan Chopra, was with his family at his farmhouse in Ghitorni.

Agency New Delhi.

Three days after a CNG pump chain owner was robbed of Rs 30 lakh, the Delhi Police arrested four men — including two of the victim's drivers.

The two drivers — Satendar Singh, 35, and Anil, 54 — and their accomplices, Santosh Tripathi, 40, and Shammi, 49, were arrested from different parts of Delhi where they had fled to evade capture.

The incident took place on Monday night when the victim, Karan Chopra, was with his family at his farmhouse in Ghitorni.

A man posing as a delivery boy knocked on his door. As soon as Chopra opened the gate, he was pushed aside by the accused while three more men entered his house, police had said earlier.

"They told him that they have guns. They told him to stay calm, and let them leave with the cash. They took whatever money and jewellery was at the farmhouse. Then they took Chopra to his office on MG Road in Gurgaon in his own car to take out more cash," a police officer had said.

Following the arrests, police said a total of Rs 6.6 lakh of the stolen amount has been recovered from the four accused — Rs 3.15 lakh from Satendar; Rs 95,000 from Anil; Rs 1.95 lakh from Santosh; and Rs 10,000 from Shammi.

Police said the two drivers, who were arrested late Wednesday, were the brains behind the whole operation.

"The two knew everything about the amount of cash that was kept at both the victim's house and his office. They called in the other two accused to help pull off the robbery for a fraction of the proceeds," DCP (Southwest Delhi) Amit Goel said.

After questioning Satendar and Anil, police arrested the other two accused on Thursday morning. "Attempts to recover the rest of the stolen amount are being made," a police official said.

DU undergrad admissions: New tie-breaker rule introduced, here's how it will work

The rush comes amid several changes to the admission process, including a new tie-breaking formula and the introduction of a "direct auto-accept" option for seat allocation.

Agency New Delhi.

Over a week after Delhi University opened its undergraduate admissions for the 2025–26 academic year, the varsity has recorded 83,296 registrations on its Common Seat Allocation System (CSAS) portal, The Indian Express has learnt.The rush comes amid several changes to the admission process, including a new tie-breaking formula and the introduction of a "direct auto-accept" option for seat allocation.

In response to challenges faced last year, DU has revised its tie-breaking rules — it will now take into account marks scored by students in Class X as one of the options.

Explaining why the varsity has considered the new rule this year and how it would be implemented, DU, Dean of Admissions, Haneet Gandhi, told The Indian Express, "Until last year, we were working with raw data and, in some cases, we had to allocate seats based on the alphabetical order of names."

"This year, we wanted a more rational and merit-based approach. So we decided to use Class X marks. We will take the average of all subjects taken by a student in Class X and use that to break the tie."

The move, Gandhi said, ensures that "meritorious students would be considered without fail".

Until last year, for cases where two or more applicants have the same CUET score for a given programme-college combination, the CSAS guidelines said tie-breaking rules would be applied in this order:

– Candidate with a higher percentage of aggregate marks in the best three subjects of Class XII will be given preference.

Massive fire breaks out at chemical factory in Noida; no injuries

Agency New Delhi.

A massive fire broke out early Friday at a chemical manufacturing unit in Noida's Sector 2, prompting a multi-agency response. Officials confirmed that the blaze, which started at around 5.30 am at Sham Paints Industries located in Sector 2, was brought under control with no injuries or casualties reported.

Pradeep Kumar, Chief Fire Officer (CFO), Gautam Budh Nagar, said the initial alert about the fire was received from the area's police at 5.30 am. "We were informed that a fire had broken out at Sham Paints. Two fire tenders were immediately dispatched from the nearest station, which is barely 500 metres away," he said.

However, by the time the two fire tenders arrived, the flames had intensified significantly. "There were multiple explosions, and the flames had already spread across a wide area. Given the scale and nature of the blaze, we called in reinforcements from Ghaziabad, Hapur, Bulandshahr, Meerut, and even private sector units," Kumar said. More than seven fire tenders were deployed to the site, as five more were rushed from the neighbouring units. Firefighters first made attempts to prevent the flames from spreading to the adjacent factories, which are located near the factory that had been affected by the fire.

'Think of how an old post may be problematic, then delete it': New US Visa rule fuels student anxiety over social media

Outlining each visa adjudication as a "national security decision," the United States has mandated that applicants reveal their social media usernames or handles for every platform used in the past five years.

Agency New Delhi.

A 24-year-old from Delhi, who recently secured admission to Harvard University in the United States, describes how his days now begin with combing through his Instagram account. "Every few hours, I think of how an old post may be problematic, and then delete it," he says. "Even memes feel risky now."

He is one of the several Indian students who spoke to The Indian Express about the rising anxiety over a recent US directive requiring all F, M, and J visa applicants to make their social media accounts public.

The advisory, citing "national security and public safety," instructs visa applicants to change their privacy settings to allow for vetting by consular officers — a marked shift from previous years, when only publicly visible content could be viewed and considered. The F, M, and J visas are non-immigrant visas for foreign nationals seeking to study or participate in exchange programmes. Outlining each visa adjudication as a "national security decision," the United States has mandated that applicants reveal their social media usernames or handles for every platform used in the past five years. On Thursday, the US Embassy in India issued a statement, warning that failure to disclose social media information "could lead to visa denial and ineligibility for future visas."

"I gave my interview earlier in June, and I'm still waiting for my visa," says the Delhi-based student. "The guideline is very vague. It says 'anything that violates American values.' We don't even know what that is supposed to mean."

For most students, the process of making years of personal content accessible to immigration authorities has been stressful, especially because there is little clarity on what might raise red flags. A 23-year-old from Mumbai, who also got into Harvard, says he made all his accounts public on May 22 — the day he submitted his online non-immigrant visa application (DS-160 form). "Since then, I've archived everything even remotely political. I've stopped liking posts too, just in case even that is visible," he shares.

Career counselling firms said they had to swiftly adapt in light of the change. "The recent US government directive is a significant development — but one that serious academically-oriented applicants can certainly navigate successfully," underlines Aman Singh, co-founder, GradRight, Gurgaon. "Our core guidance now focuses on helping students understand and actively manage their digital footprint. It's about being mindful and authentic."

While there has been a 20-25% drop in the number of students going to the US over the past 6-8 months, according to Singh, loan approvals through GradRight for students accepted to top-tier colleges have gone up by 60%. "The appeal of US universities remains strong. For strong, high-intent students, the process is still working," he adds. Akshay Chaturvedi, founder and CEO of Leverage Edu, based in Noida, says the shift merely formalises what many universities were already doing. "This update adds a new layer to visa assessments but also reinforces the value of a student's digital presence," he says. "No need to delete or disguise — just ensure coherence and avoid ambiguity."

"With the right awareness, students can use this as an opportunity to project clarity and intent, traits that matter across every global education system," Chaturvedi adds. About 15-20% of the monthly student applications at Leverage Edu represent students aiming to pursue higher education in the United States.

NEWS BOX

Thailand to hold trade talks with US next week amid Trump's tariffs threat

BANGKOK. Thailand's finance minister will travel to the United States next week for trade talks, local media reported Friday, as the kingdom seeks to secure a deal with Washington over US President Donald Trump's threatened tariffs.Thai exports face a 36 percent levy on key exports to America under the US president's raft of "Liberation Day" measures if no agreement is reached to head them off before next month's deadline.Finance Minister Pichai Chunhavajira told reporters he has scheduled talks with a US representative and plans to depart next week, according to local media outlet Thai News Agency MCOT.His remarks followed online speculation that the tariffs would be cut to 18 percent after the talks, which he dismissed in a post on X."It's just a projection made by economists," he told reporters at Government House, as quoted by local media.In May, Pichai said the proposal aimed to reduce the trade imbalance and expand US export access to Thailand's market.

America's goods trade deficit with Thailand hit $45.6 billion in 2024, up 11.7 percent from the year before, according to US Trade Representative data.

The Thai government last month cut its 2025 economic growth forecast to 2.3-3.3 percent, from 3.2-4.2 percent, citing uncertainty over "reciprocal tariffs."

AFP has reached out to Pichai's party representative who was unable to confirm details of the trip.

Many Southeast Asian nations were threatened with the highest "reciprocal" tariff rates: 49 percent on Cambodia's exports, 46 percent on Vietnam's and 44 percent on Myanmar's.

South Korea detains six Americans for trying to send rice, Bibles to North Korea by sea

SEOUL. Six Americans were detained Friday in South Korea for trying to send 1,600 plastic bottles filled with rice, US dollars bills and Bibles toward North Korea by sea, police said.The Americans tried to throw the bottles into the sea from front-line Gwanghwa Island so they could float toward North Korean shores by the tides, said a police officer who spoke on condition of anonymity because he wasn't authorized to speak to media on the issue.He said they are being investigated on allegations they violated the law on the management of safety and disasters.A second South Korean police officer confirmed the detentions of the Americans.The police officers gave no further details, including whether any of the six had made previous attempts to send bottles toward North Korea.Activists floating plastic bottles or flying balloons carrying anti-North Korea propaganda leaflets across the border has long caused tensions on the Korean Peninsula.North Korea expressed its anger at the balloon campaigns by launching its own balloons carrying trash into South Korea, including at least two that landed in the presidential compound in Seoul last year.In 2023, South Korea's Constitutional Court struck down a 2020 law that criminalized the sending of leaflets and other items to North Korea, calling it an excessive restriction on free speech.But since taking office in early June, the new liberal government of President Lee Jae Myung is pushing to crack down on such civilian campaigns with other safety-related laws to avoid a flare-up in tensions with North Korea and promote the safety of frontline South Korean residents.On June 14, police detained an activist for allegedly flying balloons toward North Korea from Gwanghwa Island.Lee took office with a promise to restart long-dormant talks with North Korea and establish peace on the Korean Peninsula. Lee's government halted frontline anti-Pyongyang propaganda loudspeaker broadcasts to try to ease military tensions.

Israel-Iran war highlights Asia's dependence on Middle East oil, 'slow' progress on clean energy

HANOI. Asia's dependence on Middle East oil and gas — and its relatively slow shift to clean energy — make it vulnerable to disruptions in shipments through the Strait of Hormuz, a strategic weakness highlighted by the war between Israel and Iran.

Iran sits on the strait, which handles about 20% of shipments of the world's oil and liquefied natural gas, or LNG. Four countries — China, India, Japan and South Korea — account for 75% of those imports.

Japan and South Korea face the highest risk, according to analysis by the research group Zero Carbon Analytics, followed by India and China. All have been slow to scale up use of renewable energy.

In 2023, renewables made up just 9% of South Korea's power mix — well below the 33% average among other members of the Organization for Economic Cooperation and Development, or OECD. In the same year, Japan relied more heavily on fossil fuels than any other country in the Group of Seven, or G7.

A truce in the 12-day Israel-Iran war appeared to be holding, reducing the potential for trouble for now. But experts say the only way to counter lingering uncertainty is to scale back reliance on imported fossil fuels and accelerate Asia's shift to clean, domestic energy sources."These are very real risks that countries should be alive to — and should be thinking about in terms of their energy and economic security," said Murray Worthy, a research analyst at Zero Carbon Analytics.Japan and South Korea are vulnerableChina and India are the biggest buyers of oil and LNG passing through the potential chokepoint at the Strait of Hormuz, but Japan and South Korea are more vulnerable.

Japan depends on imported fossil fuels for 87% of its total energy use and South Korea imports 81%. China relies on only 20% and India 35%, according to Ember, an independent global energy think tank that promotes clean energy.

US Supreme Court to rule on birthright citizenship, voting rights before current term concludes

The justices are weighing a three-year battle over congressional districts in Louisiana that is making its second trip to the Supreme Court.

WASHINGTON. The Supreme Court is meeting Friday to decide the final six cases of its term, including President Donald Trump's bid to enforce his executive order denying birthright citizenship to U.S.-born children of parents who are in the country illegally.The justices take the bench at 10 a.m. for their last public session until the start of their new term on Oct. 6.

The birthright citizenship order has been blocked nationwide by three lower courts. The Trump administration made an emergency appeal to the Supreme Court to narrow the court orders that have prevented the citizenship changes from taking effect anywhere in the US.The issue before the justices is whether to limit the authority of judges to issue nationwide injunctions, which have plagued both Republican and Democratic administrations in the past 10 years.These nationwide court orders have emerged as an important check on Trump's efforts and a source of mounting frustration to the Republican president and his allies.

Decisions also are expected in several other important cases.The court seemed likely during arguments in April to side with Maryland parents in a religious rights case over LGBTQ storybooks in public schools.

Parents in the Montgomery County school system, in suburban Washington, want to be able to pull their children out of lessons that use the storybooks, which the county added to the curriculum to better reflect the district's diversity.The school system at one point allowed parents to remove their children from those lessons, but then reversed course because it found the opt-out policy to be disruptive. Sex education is the only area of instruction with an opt-out provision in the county's schools.The justices also are weighing a three-year battle over congressional districts in Louisiana that is making its second trip to the Supreme Court.Before the court now is a map that created a second Black majority congressional district among Louisiana's

six seats in the House of Representatives. The district elected a Black Democrat in 2024.Lower courts have struck down two Louisiana congressional maps since 2022 and the justices are considering whether to send state lawmakers back to the map-drawing board for a third time.The case involves the interplay between race and politics in drawing political boundaries in front of a conservative-led court that has been skeptical of considerations of race in public life.At arguments in March, several of the court's conservative justices suggested they could vote to throw out the map and make it harder, if not impossible, to bring redistricting lawsuits under the Voting Rights Act.Free speech rights are at the center of a case over a Texas law aimed at blocking kids from seeing online pornography.Texas is among more than a dozen states with age verification laws. The states argue the laws are necessary as smartphones have made access to online porn, including hardcore obscene material, almost instantaneous.The question for the court is whether the measure infringes on the constitutional rights of adults as well. The Free Speech Coalition, an adult-entertainment industry trade group, agrees that children shouldn't be seeing pornography. But it says the Texas law is written too broadly and wrongly affects adults by requiring them to submit personal identifying information online that is vulnerable to hacking or tracking.

'Shocking' COP30 lodging costs heap pressure on Brazil's host city Belem

RIO DE JANEIRO. "Belem is ready," Brazilian officials have insisted ahead of the COP30 gathering in November -- but eye-watering lodging costs in the northern city have panicked many would-be attendees.President President Luiz Inacio Lula da Silva has personally championed the symbolic choice of holding the major UN climate conference in the Amazon. And with months to go before the November 10-21 meeting, work is in full swing, AFP journalists witnessed recently.But members of national delegations, civil society, and the media have been faced with a major dilemma: how to find a room at a decent price?"I've never seen anything quite like the situation unfolding in Belem. The soaring accommodation prices, which mean it will now cost thousands of dollars a night for even basic rooms," Mariana Paoli, with the NGO Christian Aid, told AFP.The steep rates are "not just shocking, it is exclusionary," said Paoli, a Brazilian who has attended several UN climate summits before."Delegates from across the Global South, particularly

grassroots activists, Indigenous leaders, and civil society groups, already face immense barriers to participation... Now, they're being priced out entirely."In recent months, AFP has seen hotels offering rooms at $1,200 a night. On short-term rental platform Airbnb, some rates were even higher.With a total of 50,000 people expected to attend, Claudio Angelo of the Brazilian Climate Observatory collective warned that delegations are mulling cutting back on the number of attendees."Everybody's concerned because at this point, five months to the date, everybody should have hotels and no one has," he told AFP in Bonn, Germany, where technical negotiations have been held over the past two weeks.CEO rules out relocationBrazil is no stranger to hosting major events, particularly in Rio de Janeiro. After the 2016 Olympic Games and last year's G20 summit, Rio will host a summit of the BRICS group of emerging economies next month.Some have speculated about a possible last-minute move to a large city, maybe Rio.COP30 chief Ana Toni, while sharing concerns over the lodging, ruled out any last-minute relocation to a larger city. "Let's be very very clear, it's all happening in Belem," she told AFP in Bonn.

Tibetans face up to uncertain future as Dalai Lama turns 90

DEHRADUN. Tibetans in exile celebrate the 90th birthday of spiritual leader the Dalai Lama next week, an occasion overshadowed by uncertainty about the future of the role and what it means for their movement.

The charismatic Nobel Peace Prize-winning Buddhist -- who Tibetans say is the 14th reincarnation of the 600-year-old post -- will reveal if there will be another Dalai Lama after him.The inevitable change ahead brings wider concerns for Tibetans over the struggle to keep their identity alive after generations in exile, following a failed 1959 uprising against Chinese rule.

There is widespread support among Tibetans in exile for the Dalai Lama role to remain, said Dawa Tashi, once jailed in Tibet for his criticism of Beijing.The Dalai Lama has said the institution will continue only if there is popular demand. "I strongly believe the reincarnation of the 14th Dalai Lama will continue," said Tashi, of the India-based Tibetan Centre for

Human Rights and Democracy."This hope is not only shared by Tibetans inside and outside Tibet, but by thousands who are connected to the Dalai Lama across the world," he told AFP.The leader, who turns 90 on July 6, and thousands of other Tibetans have lived in exile in India since Chinese troops crushed the uprising in the Tibetan capital Lhasa.The Dalai Lama has been lauded by his followers for his tireless campaign for greater autonomy for Tibet, a vast high-altitude plateau in China about the size of South Africa.

'Vested political interests'

The Dalai Lama handed over political authority in 2011 to an exiled government chosen democratically by 130,000 Tibetans globally. At the same time, he warned that the future of his spiritual post faced an "obvious risk of vested political interests misusing the reincarnation system."Many Tibetans in exile fear China will name a successor to bolster its control over Tibet.The Dalai Lama has said that if there is a successor it will come from the "free world" outside China's control.The Dalai Lama has long said he does not seek full independence for Tibet.Beijing says the territory is an integral part of China and that the Dalai Lama "has no right to represent the Tibetan people".

Justice Department says Kilmar Abrego Garcia will face US trial before any move to deport him again

WASHINGTON. The Justice Department said Thursday that it intends to try Kilmar Abrego Garcia on federal smuggling charges in Tennessee before it moves to deport him, addressing fears that he could be expelled again from the U.S. within days.U.S. Magistrate Judge Barbara Holmes in Nashville, Tennessee, recently ruled that Abrego Garcia has a right to be released from jail while awaiting trial on the smuggling charges. But she decided Wednesday to keep him in custody for at least a few more days over concerns that U.S. immigration officials would swiftly detain him and try to deport him again.

But DOJ spokesperson Chad Gilmartin told The Associated Press that Abrego Garcia will first be tried in court on the charges."This defendant has been charged with horrific crimes, including trafficking children, and will not walk free in our country again," Gilmartin said.Abrego Garcia became a flashpoint over President Donald Trump's hardline immigration policies when he was mistakenly deported to El Salvador in March. Facing mounting pressure and a Supreme Court order, the Trump administration returned him this month to face the smuggling charges, which Abrego Garcia's attorneys characterized as an

attempt to justify his erroneous deportation.As Abrego Garcia's criminal case has moved forward, concerns grew that he would be swiftly deported upon his release from jail in Tennessee.Abrego Garcia's lawyers filed an emergency request Thursday to a federal judge in Maryland to order the government to take Abrego Garcia to that state upon release, an arrangement that would prevent his deportation before trial.If this Court does not act swiftly, then the Government is likely to whisk Abrego Garcia away to some place far from Maryland," Abrego Garcia's attorneys wrote.Abrego Garcia had lived and worked as a construction worker in Maryland with his American wife and children for more than a decade before his deportation in March. His wife, Jennifer Vasquez Sura, is suing the Trump administration over his deportation in the Maryland federal court where Abrego Garcia's attorneys filed their emergency request."We have concerns that the government may try to remove Mr. Abrego Garcia quickly over the weekend," one of his attorneys, Jonathan Cooper, told U.S. District Judge Paula Xinis in Greenbelt, Maryland, during a conference call Thursday afternoon.Justice Department attorney Jonathan Guynn acknowledged on the call that the U.S. government plans to deport Abrego Garcia to a "third country.

Syria's wheat war: Drought fuels food crisis for 16 million

DAMASCUS. Rival Syrian and Kurdish producers are scrambling for shrinking wheat harvests as the worst drought in decades follows a devastating war, pushing more than 16 million people toward food insecurity."The country has not seen such bad climate conditions in 60 years," said Haya Abu Assaf, assistant to the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) representative in Syria.Syria's water levels have seen "a very significant drop compared to previous years, which is very worrying", Abu Assaf told AFP, as a relatively short winter rainy season and decreased rainfall take their toll."A gap of between 2.5 to 2.7 million tonnes in the wheat crop is expected, meaning that the wheat quantity will not be sufficient to meet local needs," Abu Assaf said, putting "around 16.3 million people at risk of food insecurity in Syria this year."Before the civil war erupted in 2011, Syria was self-sufficient in wheat, producing an average of 4.1 million tonnes annually.

Nearly 14 years of conflict have since crippled production and devastated the economy. The FAO estimates that harsh weather has impacted nearly 2.5 million hectares of wheat-growing land.

"Around 75 percent of the cultivated areas" have been affected, as well as "natural pastures for livestock production", said Abu Assaf.

Imports, competition

To bridge the wheat gap, imports would be essential in a country where around 90 percent of the population lives in poverty.

Before his ouster in an Islamist-led offensive in December, Syria's longtime ruler Bashar al-Assad used to rely on ally Russia for wheat.In April, new authorities reported the first wheat shipment since his removal arrived in Latakia port, with more Russian shipments following.Iraq also donated more than 220,000 tonnes of wheat to Syria.During the war, Damascus competed with the semi-autonomous Kurdish administration in the northeast to buy

wheat from farmers across fertile lands.Last year, Assad's government priced wheat at $350 per tonne, and the Kurds at $310.After Assad's ouster, Damascus and the Kurds agreed in March to integrate Kurdish-led institutions into the new Syrian state, with negotiations ongoing on implementation.Damascus set wheatprices this month at between $290 and $320 per tonne, depending on the quality, plus a $130 bonus.The Kurdish-led administration offered $420 per tonne including a $70 bonus.

'Poverty and hunger'

Damascus' agriculture ministry expects a harvest of 300,000 to 350,000 tonnes in government-controlled areas this year.

Hassan Othman, director of the Syrian Grain Establishment, acknowledged Syria was not self-sufficient, in comments on state television.But he said authorities were working "to ensure food security by importing wheat from abroad and milling it in our mills".In northeast Syria's Amuda, farmer Jamshid Hassu, 65, inspected the tiny wheat grains from his fields, which cover around 200 hectares (around 500 acres).Despite heavy irrigation efforts to offset scarce rainfall, he said, production has halved.The FAO's Abu Assaf said indicators showed that "about 95 percent of rain-fed wheat has been damaged and affected", while irrigated wheat yields were down 30 to 40 percent.

NEWS BOX

Freestyle Chess Tour's India-leg cancelled amidst lack of sponsors, CEO confirms

NEW DELHI. The Freestyle Chess Grand Slam Tour, which was supposed to have its fifth event in Delhi in September, later this year has been cancelled due to the lack of sponsors. The co-founder, Jan Henric Buettner, confirmed the news to Chess.com after speculation over the event's status following the removal of the Delhi leg from the official website.

This event was supposed to be their fifth event of the inaugural Grand Slam, after posting successful shows in Weissenhaus, Paris, and Karlsruhe. Presently, GM Magnus Carlsen holds the lead at the top with 65 points after winning two events.Carlsen will be headlining the next event, which is set to be held in Las Vegas on July 16-20, later next month. He was recently seen in action against the nine-year-old Aarit Kapil from Delhi, who had come close to beating the current top-ranked player.When asked if there may be a possible replacement, Buettner provided a cryptic response and suggested that there could be something done, but the announcement has yet to be made.

"Yes and no," he was quoted as saying by Chess.com.

"We will do something special for the September leg of the tour instead. This will be announced after Las Vegas," he added.

Buettner also revealed that he is planning on stepping down from his role as CEO. In a previous interview, he had revealed how he wants to take up a more executive role instead. Now he is set to end his tenure as CEO on July 1.I hope I get out of it! I want it to be implemented in a perfect way. I am giving everything, so when all my visions in my head are implemented, then I can have a more executive role," he said.

WHAT'S NEXT FOR INDIA'S CHESS STARS?

With the Freestyle Chess Grand Slam Tour now cancelled, the next home event for India's top chess stars will be the Chennai Grand Masters, starting August 6, where the tournament comprises a 10-man round-robin format with GMs like Arjun Erigaisi, Nihal Sarin, Anish Giri, Vincent Keymer, amongst many others set to compete.

European teams vs USA weather: FIFA Club World Cup is facing the heat

New Delhi. When elite footballers start worrying more about the sun than their opponents, it's a sign something's not right.The FIFA Club World Cup was supposed to be a smooth preview for next year's expanded World Cup in the United States, Mexico, and Canada. Instead, it has turned into a heatwave reality check. As temperatures soar across host cities, players and coaches are struggling - not just to win, but to keep up with the conditions.In cities like Cincinnati, Philadelphia, and Charlotte, mid-afternoon games have been played in scorching heat, often above 90F (32C). At Borussia Dortmund's group match against Ulsan Hyundai, the game kicked off at 3 p.m. under a blazing sun. Cooling breaks were allowed, but the weather made a bigger impact than any tactical change.Chelsea boss Enzo Maresca didn't hold back after experiencing the Philadelphia heat.

"It's impossible to organise regular training sessions in the afternoons," he told reporters.

Atletico Madrid midfielder Marcos Llorente agreed, saying the heat had affected how the team trains and prepares. Players have found it hard to recover quickly or maintain normal match sharpness.While European sides have struggled, South American clubs - more used to hot and humid climates - have had less trouble. All four Brazilian sides in the tournament - Flamengo, Palmeiras, Botafogo, and Fluminense - made it through to the second round without much fuss. Their advantage in such conditions has become clear.

Pitch problems add to the pressure

If the weather wasn't enough of a challenge, the playing surfaces have added another layer of difficulty. Several players and coaches have raised concerns about dry, uneven, and hard pitches at different venues - conditions that have only been made worse by the extreme heat.

Avinash Sable eyes World Championship redemption: Preparations are going well

- Avinash Sable overcame a year-long calf injury to return to form
- He trained at high altitude in Ooty and Bengaluru for peak fitness
- Sable aims to improve his personal best by closer to eight minutes

NEW DELHI. India's top 3000m steeplechase athlete, Avinash Sable, is fit again and firmly focused on redemption at the upcoming World Athletics Championships in September. Having finally shaken off a nagging calf injury that plagued him for over a year, Sable is now focused on improving his personal best and making a strong statement on the global stage.The reigning Asian Games gold medalist has been steadily rebuilding his fitness, splitting his time between high-altitude training in Ooty and intense workouts at the Sports Authority of India's Southern Centre in Bengaluru. With preparations going smoothly, Sable is quietly confident.Last year was not good, it didn't even look like I'll be able to perform well. But this year I am competing in the Diamond League, so preparation (for the World Championship) is good," Sable told a select group of reporters."My target is to notch my personal best, closer to eight minutes. 15 days are left of training, I think I will be able to go near eight."Since winning the 3000m steeplechase title at the Hangzhou Asian Games in 2023, Sable had been hampered by a persistent injury in his right calf and hamstring that lingered until early 2025."I had a calf injury, there was a lot of pain in my right calf and hamstring. It started after the Asian Games and continued the entire year. The pain was there till January-February this year," he said.Sable kicked off his 2025 season at the Xiamen Diamond League with a time of 8:22.59, followed by an 8:23.85 run in Shaoxing. Though below his usual standards, he bounced back by winning gold at the Asian Championships in Gumi, South Korea, in May, clocking 8:20.92."Preparations are going well. I was injred in the opening of the season. But despite that I participated in two Diamond League events in China."The results weren't good because of the injury. Then I competed in the Asian Championship to boost my confidence. I started training in November, the off season also went well. I faced a lot of trouble due to injuries last season."At the previous World Championships, Sable failed to progress beyond the heats, finishing seventh in his race. This year, however, he's determined to turn things around."At the World Championships, I want to improve my position from last time. This year I have worked on finishing the race, mileage etc."It's been nearly a year since Sable set the national record of 8:09.91, and breaching the eight-minute mark remains a key goal."

Yes I want to do it. It won't happen soon but I think I'll be able to improve my personal best.

WI vs AUS: Coach Sammy meets referee Srinath over contentious TV umpiring decisions

- The dismissals of Roston Chase and Shai Hope were contentious umpiring decisions
- WI coach Darren Sammy seeks greater clarity and consistency in umpiring decisions
- Australia hold an 84-run lead at the end of Day 2

NEW DELHI. West Indies head coach and former captain Darren Sammy met with match referee Javagal Srinath to express his concerns over the decisions made by on-field umpire Adrian Holdstock during the second day of the opening Test against Australia at Bridgetown on Friday, June 27.Two major decisions, both going against the hosts, sparked controversy as Australia ended the day with an 82-run lead and six wickets in hand. The first contentious moment was the dismissal of West Indies captain Roston Chase. Australian skipper Pat Cummins delivered a ball that nipped back into the right-hander and struck him on the pads, prompting a successful leg-before-wicket appeal. Chase reviewed the decision, and the point of concern was the ultra-edge replay, which showed small, closely spaced spikes—raising questions about a possible inside edge.The second contentious decision involved the dismissal of Shai Hope, who was just two runs short of his half-century. Hope appeared to get an inside edge off Beau Webster's delivery, and wicketkeeper Alex Carey, diving forward for the catch, seemed to have the ball in contact with the ground during the attempt, as shown in the replay. Despite being referred to the third umpire, the on-field decision was upheld.The Men in Maroon will be hoping for a stronger performance as they aim to topple the formidable Australian side, who are seeking their first Test win in the West Indies since 2003. The hosts' last home victory against Australia came in St. John's, Antigua, on May 9, 2003.Speaking after the day's play, Sammy expressed his reservations about umpire Adrian Holdstock and called for greater consistency from the match officials."We are just trying to find some sort of understanding as to what the process is. We only hope for consistency. That's all we could ask for. When there is doubt in something, just be consistent across the board," Sammy told ESPNcricinfo.

"I have noticed, especially with this particular umpire, it's something that, for me, started in England. It's frustrating.

Kylian Mbappe accuses PSG of 'moral harassment, files legal complaint vs ex-club

Kylian Mbapp has accused Paris Saint-Germain of moral harassment in a legal filing, the Paris prosecutor's office confirmed on Thursday.

The Real Madrid star is at odds with his former club, arguing PSG owes him 55 million euros ($61 million) in unpaid wages.Mbapp is also unhappy with the way he was treated by the Ligue 1 club when the France captain was sidelined before the 2023-24 season, following his decision not to extend his club contract.

The prosecutor's office said Mbapp is "denouncing the 'lofting' he claimed to have been subjected to at Paris Saint-Germain." The word lofting is used in France to describe a practice that involves isolating a player from the main squad for sporting, administrative, or disciplinary reasons.Mbapp joined Real Madrid last summer on a free transfer after scoring a club-record 256 goals in seven years at PSG, which won the Champions League without him this year.Mbapp's relationship with PSG ended amid deep tensions, and some fans booed him in his last home game at Parc des Princes. PSG felt let down by Mbapp after offering him the most lucrative contract in club history when he signed a new contract in 2022.

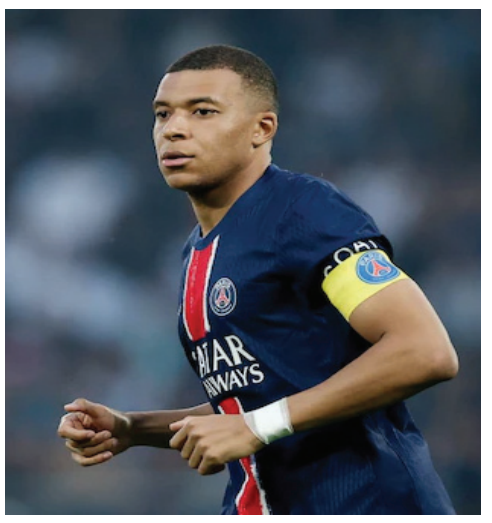

But Mbapp was frustrated because he felt promises to sign key players were not kept. When he signed that deal, he was paraded in front of fans holding up a jersey with 2025 on it. Mbapp was reportedly annoyed because the contract was until 2024 — with a player's option for an extra season.Mbapp stunned PSG in June 2023 by informing the club he would not take the option for an extra year.

No Kane Williamson; Milne, Henry return as New Zealand announce tri-series squad

New Delhi. New Zealand have named fast bowler Adam Milne and uncapped batter Bevon Jacobs in their T20I squad for next month's tri-series in Zimbabwe, which also features South Africa. The 15-man group will be led by Mitchell Santner, with new head coach Rob Walter beginning preparations for the 2026 T20 World Cup.Kane Williamson is among several senior players unavailable. The veteran batter, currently turning out for Middlesex and set to represent London Spirit in The Hundred, has opted out of the tour. Lockie Ferguson has been rested to manage his workload, while Kyle Jamieson is awaiting the birth of his first child. Ben Sears is sidelined with a side strain, and there is no room for Devon Conway or Mitch Hay, with Tim Seifert preferred behind the stumps.Jacobs, yet to make his international debut, retains his place after being part of the squad for the December T20I series against Sri Lanka. The 22-year-old, who impressed during domestic competitions and earned an IPL contract with Mumbai Indians, offers an explosive option with the bat.Milne returns for the first time since November, having missed the previous World Cup due to ankle surgery. He has recently shown strong form in Major League Cricket, taking nine wickets in four matches for Texas Super Kings. Fellow pacer Matt Henry is also back after recovering from the shoulder injury that ruled him out of the ICC Champions Trophy earlier this year.Several players who missed the March T20Is against Pakistan owing to IPL commitments - including Glenn Phillips, Rachin Ravindra and Santner - are back in the fold."I think we've got a really strong squad for this tour, and I'm looking forward to getting the team together and getting into the work," Walter said. "It's great to have some of the experienced players back, and this series offers a valuable opportunity to look at some new faces too."He added: "Bevon has been outstanding in domestic cricket and gained good exposure in franchise leagues. It's a great chance for him to integrate with the group and push for selection. Adam brings pace and experience, and with a few regulars unavailable, it's ideal to have someone of his quality back in the squad."

Walter, appointed across all formats earlier this month, will be supported by assistant coaches Luke Ronchi, Jake Oram and James Foster. He sees the tri-series as a vital step in building towards the next World Cup.With the tournament just a year away, every series counts. This tour allows us to test our depth, assess different combinations, and compete against strong opposition in challenging conditions," he said.

India beat England in historic Mixed Disability match at Lord's to leave series poised

- India won the iconic match at Lord's to leave the 7-match series poised
- India lost the first two matches of the series in Taunton and Wormsley
- India and England will meet in the fourth T20I on Friday in Worcester

New Delhi. India's Mixed Disability Team held its nerve and sealed a thrilling two-wicket win over England in the last over at Lord's in the third T20I of their ground-breaking Mixed Disability seven-match IT20 series at the Lord's Cricket Ground on Wednesday. The occasion was historic as it was the first-ever international Disability match at the 'Home of Cricket.'The date, venue and the result of the match all made for a tremendous coincidence- 42 years ago, India, led by the legendary Kapil Dev, had clinched the 1983 World Cup on June 25 at Lord's in 1983."We dedicate our team's historic win to Kapil Dev sir's team's 1983 World-Cup winning team," said Ravi Chauhan, the Gen Secretary of the Differently-Abled Cricket Council of India (DCCI).Both teams wore black armbands during the match to mourn the passing away of former India left-arm spinner Dilip Doshi on Monday in London.

June 25 is incidentally celebrated as the 'World Mixed Disability Day.' The fixture at Lord's formed part of the Cricket Disability Day, and was the biggest ever one-off showcase of disability cricket, as it was the first time that India and England's mixed Disability teams played at Lord's. Hosted by the MCC, ECB and Lord's Taverners, the game was the showpiece event of this series.

India's Mixed Disability team is now trailing 2-1 in the series after losing the first two matches at Taunton and Wormsley Cricket Club.Led by a magnificent show with the ball by seamer Vivek Kumar (three for 16 in three overs) and left-arm spinner and captain Ravindra Sante (three for eight in four overs), India's Mixed Disability team restricted England to just 123 for nine in 20 overs after the hosts elected to bat first. A.

Brown was the lone warrior for England with a brilliant half-century (77, 47b, 5x4, 5x6). Brown added 35 for the ninth wicket with A Pyle (4 not out) off just 17 balls to help England cross the 100-run mark. He took 18 off the last over bowled by spinner Tarun, smashing him for two sixes, to give the hosts' total some respectability after they had collapsed to 49 for seven in 12 overs.Staving off a superb fightback by England with the ball, India scampered to the target in the final over, losing eight wickets. The hero of the chase was middle-order batter Sai Akash, who made 44There are four more matches left in the series, with the next game to be played on Friday (June 27) at Worcester.

Katrina Kaif

Has A Hilarious Nickname For Vicky Kaushal Amid His Night Shoots With Ranbir Kapoor, Alia Bhatt

Vicky Kaushal and Kareena Kapoor Khan recently sat down for a candid chat with The Hollywood Reporter India, where they interviewed each other and opened up about films, relationships, and everything in between.During the conversation, Kareena brought up a question many couples in the industry can relate to — how do you find time for your partner when both of you are constantly working? She asked Vicky how he and wife Katrina Kaif manage to spend time together despite their packed shooting schedules.

To this, Vicky smiled and said, "Being an actor, both ways, you're not doing a 9-to-5 job where there's a proper structure, right? So everything comes down to about how we can figure out the time that we'll get for each other. And that sometimes in phases becomes difficult, in phases it's easy."

He went on to talk about shooting with Ranbir Kapoor and Alia Bhatt for Sanjay Leela Bhansali's Love & War and added, "Right now I'm in that phase where I'm shooting nights, so you are getting very limited time. Because you just get up and go. Now she has jokingly started pinching it in. She says, 'I'm just going to call you Mr. Go. Because every time I see you, you're like, I need to go.'

So that, but then there are phases also where you have to consciously plan out. Like, this is our time. But then, you kind of figure it out."

Katrina Kaif and Vicky Kaushal Marriage

Katrina Kaif and Vicky Kaushal tied the knot in a private yet grand ceremony on December 9, 2021, at Six Senses Fort Barwara in Rajasthan. The wedding was an intimate affair attended by close family and friends, with strict security and limited media access. Despite keeping their relationship low-key before the wedding, the couple's marriage quickly became one of the most talked-about events in Bollywood. Since then, Katrina and Vicky have often shared glimpses of their life together on social media.On the work front, Vicky was last seen in Chhaava, where he portrayed Chhatrapati Sambhaji. Katrina Kaif was last seen in the movie Merry Christmas which was released in 2024.

Seerat Kapoor

To Make Her Bollywood Debut With Fahadh Faasil? What We Know

Seerat Kapoor is set for a big Bollywood debut opposite Pushpa star Fahadh Faasil, promising a fresh and powerful on-screen pairing.

With grace, grit and an undeniable screen presence, Seerat Kapoor has steadily emerged as one of the most promising talents in Indian cinema. What began as a dream debut in the Telugu blockbuster Run Raja Run in 2014 has blossomed into a career marked by versatility, charm and national recognition. Her performance in the film not only won her widespread appreciation but also earned her the prestigious National Award presented by the Telangana Government—an early indication of the powerful career trajectory that was to follow.Now, after years of delivering solid performances in Tollywood, Seerat Kapoor is setting her sights on Bollywood—and this time, with a project that could mark a major turning point. Sources from the film industry have confirmed that Seerat is in talks for a new film opposite the widely acclaimed Pushpa star, Fahadh Faasil. Known for his intense performances and captivating screen aura, Fahadh Faasil's presence in any project automatically raises expectations and pairing him with Seerat promises to be a fresh cinematic experience that blends mass appeal with artistic depth.

According to a report by FilmiBeat, "The production is planning to bring fresh pairs onscreen and actress Seerat has been approached for the film alongside Fahadh. Seerat is winning hearts with her back-to-back performances. The script is very unique with lots of twists and turns and the film promises a gripping narrative with these south sensations sharing screen space for a Bollywood film for the first time. An official announcement is expected soon."

This project is reportedly built around a layered and suspenseful plot, one that will allow both actors to flex their acting skills in equal measure. While exact details about the storyline remain under wraps, insiders suggest that it will feature a thrilling narrative filled with emotional depth, unexpected twists and character arcs designed to showcase the full range of the actors' talents.Seerat, who has always remained selective with her roles, recently added fuel to the speculation through a cryptic Instagram post. Dressed in a radiant orange outfit, the actress looked stunning—but it was her caption that truly caught attention: "That quiet confidence of knowing what's about to change the game! #BollywoodCalling". The post, drenched in excitement and subtlety, sent fans into a frenzy, many of whom believed she was hinting at her Bollywood debut.

Though no formal announcements have been made by the production team or the actors involved, the film is already being viewed as one of the most anticipated collaborations in the coming months. The idea of seeing Seerat's elegance paired with Fahadh Faasil's intensity on the big screen has piqued the interest of both fans and critics alike.

Aamir Khan Makes RARE Appearance With Sisters Nikhat And Farhat Khan At Umrao Jaan Premiere

Aamir Khan attended the grand premiere of Rekha's Umrao Jaan in Mumbai with his sisters Nikhat Khan and Farhat Khan, and his daughter Ira Khan's mother-in-law.

Aamir Khan made a rare public appearance at the grand premiere of Rekha's Umrao Jaan in Mumbai on Thursday night, and this time he wasn't alone. The superstar was joined by his sisters Nikhat Khan and Farhat Khan, as well as his daughter Ira Khan's mother-in-law — Nupur Shikhare's mother — making it a warm, familial showing on the star-studded red carpet.Aamir's sister Nikhat Khan, standing to his left, looked elegant in a turquoise silk saree with black detailing and a silver border, styled with minimal jewellery. On his right, Farhat Khan wore a regal violet saree with a gold border, paired with a traditional bun and gold earrings that added to the charm. Beside her, Nupur's mother opted for a classic black saree with a red printed pallu.

Aamir Khan's sisters

Aamir Khan is the second of four siblings in a close-knit family. He has a younger brother, Faisal Khan, and two sisters—Nikhat Khan Hegde and Farhat Khan Datta.Nikhat Khan Hegde, the elder sister, began her career behind the scenes in the film industry, contributing as a producer and costume designer to projects like Qayamat Se Qayamat Tak and Tum Mere Ho. In her later years, she transitioned to acting, starring in films such as Saand Ki Aankh, Mission Mangal, and Tanhaji, as well as in the web series Special Ops 1.5. She made her TV debut in Banni Chow Home Delivery in 2022. Nikhat is married to Santosh Hegde, a businessman, and is both a mother and stepmother.

Farhat Khan Datta, the younger sister, leads a more private life. She resides in the United States with her husband, Rajeev Datta, who is the brother of Aamir's first wife, Reena Dutta. Farhat maintains a low public profile and is focused on her family life.

The grand screening of Umrao Jaan ahead of its re-release is a star-studded affair with several celebs in attendace and walking the red carpet in Mumbai tonight.On the work front, Aamir Khan's Sitaare Zameen Par is running in the theatres.

Rekha Admires Tabu's Beauty, Embraces Her With A Long Hug At Umrao Jaan Screening

Rekha, Hema Malini, and several Bollywood celebs have gathered under one roof to celebrate the cult Bollywood classic, Umrao Jaan (1981). The event was attended by Tabu, who received a warm welcome from Rekha. They hugged each other on the red carpet and admired each other's beauty before clicking photos.

Rekha, 70, was a vision on the red carpet as she paid a fitting tribute to her iconic character. Dressed in all-white with mogras on her hair and ethereal jewellery, the veteran actor stood in front of paps and her audience, greeting them with folded hands. Soon after, Tabu appeared, ringing on the film's theme. Usually a light dresser, the Haider actor looked mesmerising in a red lehenga choli set with intricate golden borders. Without a care in the world, they met like long lost friends and embraced each other in their arms.

Rekha, who is always more elusive in her greetings and approach, expressed her excitement by not letting Tabu go. They then, looked at each other and appreciated each other's beauty. Later, they posed for photos. Watch the video here:

Rekha's Umrao Jaan will re-release on the big screen on June 27. The film has been meticulously restored for contemporary audiences, retaining the essence of the original while enhancing its visual and auditory splendor. The film returns as part of PVR INOX's Timeless Classics initiative, which curates landmark films that have shaped Indian cinema's artistic heritage.

Rekha's depiction of the courtesan-poetess is hailed as one of the greatest performances in film history, earning her the National Film Award for Best Actress.

The film's music, composed by Khayyam with lyrics by Shahryar, features ghazals such as Dil Cheez Kya Hai, In Aankhon Ki Masti, and Justuju Jiski Thi, which continue to be cherished across generations. In 2006, the film was remade with Aishwarya Rai in the lead role.Rekha recently spoke about Umrao Jaan's re-release. She said, "Umrao Jaan is not just a film I acted in — she lives within me, breathes through me, even now.